# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 09 नवंबर–15 नवंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


# गाय, शैतानी साज़िश

**“कहते हैं, कुछ लोगों को भोजन तब तक हजम नहीं होता, जब तक वे उठा-पटक वाली, समाज को तोड़ने वाली, नकारात्मक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे लेते. ऐसे ही कुछ निठल्ले तत्व इन दिनों गो-रक्षकों का रूप धारण करके देश के विभिन्न हिस्सों में अमन-चैन, भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के काम में जी-जान से जुटे हुए हैं. वे अपने कृत्यों के ज़रिये न सिर्फ़ माहौल को दूषित कर रहे हैं, बल्कि देश को विकास की धारा से दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं.”**

मनीष कुमार

21 वीं सदी के भारत में यह क्या हो रहा है? दुनिया आगे जा रही है और हम 19वीं सदी की ओर लौट रहे हैं. ये कौन लोग हैं, जो गोमांस के नाम पर इंसानों की जान ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं, जो यह तय करने पर तुले हैं कि कौन क्या खा सकता है और क्या नहीं? ये कौन लोग हैं, जो गोरक्षा के नाम पर देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं, जो गाय को हिंदू-मुस्लिम में बांटकर देश में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं? दरअसल, गाय को धार्मिक मुद्दा बनाकर हिंदू-मुस्लिम में बांटना एक साज़िश है. यह हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साज़िश है. इसे शैतानी साज़िश कहना चाहिए. शैतानी साज़िश इसलिए, क्योंकि यह इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क़ानून के ख़िलाफ़ है, धर्म के ख़िलाफ़ है. इस मुद्दे पर

**गाय कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उसे धार्मिक मुद्दा बना दिया गया है. गाय का रिश्ता देश की आर्थिक व्यवस्था से है. गाय को भारत में हम माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि वह जीवनदायिनी है. कारण धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक है. भारत आज भी गांव प्रधान देश है. ग्रामीण इलाकों के आर्थिक क्रियाकलाप आज भी गोवंश पर केंद्रित हैं. ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, जो गोवंश से अछूता हो.**

देश की सरकार, राजनीतिक दलों और सिविल सोसायटी को आगे आना होगा तथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी. पहले दादरी, फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों और उसके बाद दिल्ली स्थित केरल भवन से शर्मनाक ख़बरें आईं. गाय के नाम पर सांप्रदायिकता को हवा दी जा रही है. इसे अविलंब रोकना होगा, वरना देश में घृणा और हिंसा का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना नामुमकिन होगा. केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधकर या गोलमटोल जवाब देकर अपने दायित्व से पीछे हट रही है. उसे देश में घृणा और हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटना होगा.

समझने वाली बात यह है कि गाय कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उसे धार्मिक मुद्दा बना दिया गया है. गाय का रिश्ता देश की आर्थिक व्यवस्था से है. गाय को भारत में हम माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि वह जीवनदायिनी है. कारण धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक है. भारत आज भी गांव प्रधान देश है. ग्रामीण इलाकों के आर्थिक क्रियाकलाप आज भी गोवंश पर केंद्रित हैं. ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, जो गोवंश से अछूता हो. हज़ारों सालों से गाय लोगों को अपने दूध से पालती रही है. यही वजह है कि उसे मां का दर्जा दिया जाता है. गाय का जितना महत्व हिंदुओं के जीवन में है, उतना ही महत्व मुस्लिम एवं दूसरे धर्म के लोगों के जीवन में है. लेकिन, आज भारत में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली राजनीति उफान पर है. गाय को हिंदू-मुस्लिम के बीच बांट दिया गया. यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान गाय के भक्षक हैं और हिंदू गाय के रक्षक. जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. देश में गायों की तस्करी करने वाले, गायों को मारने वाले, गायों पर अत्याचार करने वाले और गायों के नाम पर घोटाला करने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर हिंदू हैं. गोमांस निर्यात करने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक भी ग़ैर-मुस्लिम हैं. यह मुद्दा देश के लोगों के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन इसे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## गोवंश का मतलब क्या है

गोवंश में गाय, भैंस, बैल, सांड और बछड़ा आदि पशु आते हैं. भारत में वैदिक काल से ही गाय का महत्व है. आरंभ में आदान-प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय का उपयोग होता था और मनुष्य की समृद्धि उसकी गो-संख्या से आंकी जाती थी. हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी गाय पवित्र मानी जाती रही है और उसकी हत्या को पाप करार दिया जाता है. अगर भारत में गोवंश की बात करें, तो यहां 25 गौ प्रजातियां हैं. भारत में हर राज्य में गोवंश की अलग प्रजाति पाई जाती है. वैश्विक संदर्भ में देखें, तो बीफ शब्द का इस्तेमाल गाय, भैंस, बैल, सांड के मांस को परिभाषित करने के लिए किया जाता है. ■


दिल्ली
गौशाला: जहां अपनी माता को मरने के लिए भेज देते हैं | P-3

उत्तर प्रदेश
आख़िर कौन कर रहा है नफ़रत की खेती | P-4

छत्तीसगढ़
रियायत की आड़ में करोड़ों लूटने की साज़िश | P-5

# गाय, शैतानी साज़िश

पृष्ठ 1 का शेष

हिंदू–मुस्लिम का मुद्दा बना दिया गया. सरकार और राजनीतिक दलों ने कभी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं किया. यही वजह है कि जब भी गाय की बात होती है, तो मामला यहां अटक जाता है कि गोमांस की बिक्री पर पाबंदी हो या न हो. मीडिया भी इस विवाद में क़दमताल करता है. पूरा मामला यहां आकर रुक जाता है कि क्या प्रजातंत्र में इच्छा के मुताबिक खाने का अधिकार है या नहीं? यही देश का दुर्भाग्य है.

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में 150 मिलियन गायें हैं. भारत में एक गाय साल भर में औसतन 200 लीटर दूध देती है. इसकी वजह यह है कि भारत में गायों का भरण–पोषण सही तरीके से नहीं होता. इजरायल में एक गाय साल में औसतन 11 हज़ार लीटर दूध देती है. हम अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो देश में दूध की नदियां बहेंगी ही, साथ ही हम पूरी दुनिया में दूध और उसके उत्पाद निर्यात करने वाले देशों में अव्वल बन जाएंगे. सिर्फ़ दूध ही नहीं, बल्कि चर्म उद्योग का विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी समृद्ध हो जाएगा. लेकिन, क्या गोरक्षकों ने इस पहलू पर कभी ध्यान दिया? नहीं. क्या उन्होंने कभी इस बात के लिए आंदोलन किया कि देश में नकली दूध और नकली घी क्यों बेचा जाता है? गोरक्षक सेना को यह छोटी–सी बात समझ में नहीं आती कि गायों की रक्षा इंसानों को मारने से नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पालने और उनकी सेवा करने से होगी. जिस देश में छोटे–छोटे बच्चों को यूरिया से बना दूध पिलाया जाता हो, वहां गोरक्षा के नाम पर हिंसा करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है. गाय के नाम पर हिंसा भड़काने वालों को गाय की चिंता नहीं है, उनकी नज़र राजनीतिक फ़ायदे–नुक़सान पर ज़्यादा है. पूरी दुनिया में भारत की सड़कों पर यातायात बाधित करने वाली गायों की चर्चा होती है. भारत के हर शहर में गायें सड़कों पर भटकती रहती हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता. दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए. यहां क़रीब डेढ़ करोड़ की आबादी है और क़रीब 40 हज़ार गायें सड़कों पर घूमती नज़र आती हैं. यातायात बाधित करने के अलावा वे सड़कों पर पड़े कूड़े–कचरे और पॉलीथिन बैग्स को अपना आहार बनाती हैं, नतीजतन बीमार हो जाती हैं और फिर काल का ग्रास बन जाती हैं. गोरक्षा का दंभ भरने वालों की नज़र उन पर क्यों नहीं जाती?

बाबा रामदेव अक्सर कहते हैं कि गाय को बचाना भारत को बचाना है. गांधी जी भी यही बात कहते थे. यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन बचाने का मतलब क्या है? किससे बचाना है, इससे समझना बहुत ज़रूरी है. गाय भारत की जीवनशैली का अभिन्न अंग है. उसे बचाने की अपील इसलिए होती रही, क्योंकि लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया था. जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में गायों की संख्या नहीं बढ़ी. ग्रामीण भारत कुपोषण की चपेट में आ गया. नतीजा यह हुआ कि आज देश में दूध के नाम पर केमिकल बेचा जा रहा है. गो–वध करने वालों, बीफ बेचने वालों और खाने वालों की पिटाई या हत्या से यह समस्या ख़त्म नहीं होगी. इस समस्या का हल ज़्यादा से ज़्यादा गाय पालने से निकलेगा. समझने वाली बात यह भी है कि जो खुद को गोरक्षक–कार्यकर्ता मानने वाले लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर गाय नहीं पालते, गाय के गोबर से परहेज करते हैं और गोमूत्र को दूषित मानते हैं. गोरक्षा का सही मतलब देश में ज़्यादा से ज़्यादा गायों का होना है. इसलिए नहीं कि ऐसा किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, बल्कि इसलिए, क्योंकि गाय भारतीय जीवन के हर पहलू को छूती है. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में गोवंश रहा है. कृषि से लेकर उद्योग तक गाय की उपयोगिता है. चाहे पुरातन काल में वेद हों या आधुनिक भारत में गांधी जी, सभी ने गाय को धन माना है यानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा. यही वजह है कि गाय को कामधेनु कहा गया. कामधेनु का मतलब, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली. पुरातन काल से गाय के दूध, गोबर, गोमूत्र, खाल एवं हड्डियों का इस्तेमाल होता रहा है. यह वह वक्त था, जब मुद्रा (करेंसी) का प्रचलन नहीं था. आज जब सब कुछ करेंसी में होता है, तब भी गाय को कामधेनु की प्रतिष्ठा हासिल हो सकती है. ऐसा गुजरात में लोगों ने दूध की श्वेत क्रांति लाकर साबित किया है. लेकिन, ये सारी बातें गोरक्षक होने का दंभ भरने वालों को समझ में नहीं आतीं, क्योंकि उनकी आंखों पर घृणा रूपी पट्टी बंधी है.

गांधी जी हमेशा कहते थे कि ग्रामीण भारत के आर्थिक ताने–बाने के केंद्र में गाय है. उसे न सिर्फ़ बचाना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग गाय पालें, यह सुनिश्चित करना है. भारत के गांवों की सच्चाई यह है कि क़रीब 90 फ़ीसद परिवारों के पास इतनी ज़मीन नहीं है, जिससे उनका जीवनयापन हो सके. इन ग़रीब परिवारों में 43 फ़ीसद ऐसे हैं, जो भूमिहीन मज़दूर हैं और जीवनयापन के लिए दूसरे के खेतों में मज़दूरी करते हैं या फिर शहर पलायन कर जाते हैं. पलायन करने वाले ज़्यादातर ग्रामीण कुशल नहीं हैं, इसलिए शहरों में भी मज़दूरी करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है. वे घर–परिवार से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. ऐसे लोगों का जीवन गो–पालन के ज़रिये बदला जा सकता है. गाय अपने आप में उद्योग का एक केंद्र है. गाय के दूध से गुजरात के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल गई. क्या सरकार दूसरे राज्यों में यह मॉडल नहीं अपना सकती? इससे गांवों में न सिर्फ़ नकद राशि का संचार होगा, बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा. दूसरी बात यह कि गाय सिर्फ़ दूध नहीं देती, वह गोबर भी देती है, जिसका इस्तेमाल खाद और गोबर–गैस तैयार करने में होता है. गोबर–गैस घरेलू ईंधन का काम करती है. भारत में बड़ी मात्रा में गोबर बर्बाद हो जाता है. राजस्थान के नवलगढ़ में जैविक खेती करने वाले किसानों ने एक मिसाल पेश की है, जिस पर पूरे देश में अमल होना चाहिए. यहां जैविक खेती करने वाले किसानों की कमाई के केंद्र में गाय है. गाय के गोबर से वे खाद तैयार करते हैं और गोबर–गैस का इस्तेमाल घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं. उन्हें न तो कभी बाज़ार से केमिकल खरीदना पड़ता है और न भोजन तैयार करने के लिए लकड़ियां खरीदने की ज़रूरत पड़ती है. मतलब यह कि खेती में लागत कम लगती है, ईंधन का पैसा बचता है और गाय का दूध बेचने से जो पैसा मिलता है, वह सीधा मुनाफ़ा है. नवलगढ़ के किसान न सिर्फ़ कई तरह की बचत करते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान देते हैं. यह फ़ायदा तो कोई भी उठा सकता है, हर धर्म के लोग इसे अपना सकते हैं. इसके अलावा भारत का चर्म उद्योग दो बिलियन यूएस डॉलर का है. देश में 4,000 टेनरियां हैं, जो गाय की खाल पर निर्भर हैं. ज़्यादा गायों का मतलब चर्म उद्योग का विकास है. फिलहाल जो स्थितियां हैं, उनमें चर्म उद्योग की हालत बद से बदतर होती जा रही है. टेनरियों का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, इसलिए यह उद्योग वातावरण को प्रदूषित करने में अव्वल है. इस उद्योग में निवेश की कमी है, इसलिए यह भारत में थम–सा गया है. सरकार अगर गायों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाना चाहती है, तो देश के तथाकथित गोरक्षकों को भी इसे हिंदू–मुस्लिम चश्मे से बाहर निकल कर देखना चाहिए. गायों की संख्या बढ़ने से अकेले चर्म उद्योग में लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है. भारत में इस बात की संभावना प्रबल है कि हर राज्य ज़रूरत से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर सकता है. इससे हम दुग्ध उत्पाद उद्योग यानी मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री की ओर क़दम बढ़ा सकते हैं. करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन गो–रक्षकों की जमात गाय से जुड़े मामलों को सांप्रदायिक रंग देने में कामयाब हो गई है. उसकी शैतानी साज़िश के सामने सर्वशक्तिमान सरकार भी घुटने टेक चुकी है. यही वजह है कि गाय से हर जुड़ी हर बात दिशाविहीन–अर्थहीन हो गई. इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात भला क्या हो सकती है कि जो मामला अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का है, उसे हमने धार्मिक रंग दे दिया. इन तथाकथित गोरक्षकों को अगर कामधेनु के फ़ायदों का जरा भी ज्ञान होता और राजनीतिक दलों ने गाय पर राजनीति न की होती, तो अब तक देश की दिशा और दशा बदल गई होती.

**गाय किसी धर्म की बपौती नहीं है, हर धर्म के लोग उसे पालते हैं. सभी जातियों-धर्मों के लोगों को गाय से समान लगाव है, क्योंकि गाय जाति-धर्म के नाम पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करती. संख्या के लिहाज से गाय पालने वाले ज़्यादातर हिंदू हैं. गायों को खेतों एवं जंगलों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है. चारे की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनमें दूध देने की क्षमता धीरे-धीरे घट रही है. इसके अलावा वह बच्चे को जन्म देने के बाद छह-सात महीने तक ही दूध देती है. इसका असर यह हुआ कि लोगों ने गाय छोड़कर बकरी पालना शुरू कर दिया. बकरी पालने का फ़ायदा यह है कि लोग उसे आसानी से बाज़ार में बेच लेते हैं, लेकिन गाय को लेकर देश में इतना भावनात्मक माहौल बना दिया गया है, जिसकी वजह से उसे बेचना मुश्किल हो जाता है.**

गाय किसी धर्म की बपौती नहीं है, हर धर्म के लोग उसे पालते हैं. सभी जातियों–धर्मों के लोगों को गाय से समान लगाव है, क्योंकि गाय जाति–धर्म के नाम पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करती. संख्या के लिहाज से गाय पालने वाले ज़्यादातर हिंदू हैं. गायों को खेतों एवं जंगलों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है. चारे की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनमें दूध देने की क्षमता धीरे–धीरे घट रही है. इसके अलावा वह बच्चे को जन्म देने के बाद छह–सात महीने तक ही दूध देती है. इसका असर यह हुआ कि लोगों ने गाय छोड़कर बकरी पालना शुरू कर दिया. बकरी पालने का फ़ायदा यह है कि लोग उसे आसानी से बाज़ार में बेच लेते हैं, लेकिन गाय को लेकर देश में इतना भावनात्मक माहौल बना दिया गया है, जिसकी वजह से उसे बेचना मुश्किल हो जाता है. यहीं से गाय की तस्करी का खेल शुरू होता है. गाय को गांव से बूचड़खाने तक पहुंचाने का काम एक ग़ैर–क़ानूनी नेटवर्क अंजाम देता है. हैरानी की बात यह है कि ऐसा पूरा नेटवर्क हिंदू ही चलाते हैं. गाय को गांव से उठाने वालों से लेकर बूचड़खाने चलाने वालों तक ज़्यादातर हिंदू हैं.

समस्या यह है कि गाय को सरकार ने कभी आर्थिक नज़रिये से नहीं देखा. जब भी गाय का मुद्दा उठा, उसे गो–वध पर प्रतिबंध लगाकर या उठाकर ख़त्म कर दिया गया. लेकिन, अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार गाय को लेकर एक समग्र नीति बनाए. गाय को धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की ज़रूरत है. गाय के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा गाय पालने के लिए सरकारी मदद देने की ज़रूरत है, ताकि दोनों संप्रदायों के ग़रीब तबके लाभांवित हो सकें. इससे देश के गांवों में संवहनीय विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) का मॉडल विकसित होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा. अगर सरकार इन सुझावों पर अमल करती है या फिर गाय को केंद्र में रखकर कोई योजना बनाती है, तो गाय सदैव के लिए पूजी भी जाएगी और गांवों का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा. मोदी सरकार अगर ग्रामीणों एवं वनवासियों को रोज़गार मुहैय्या कराने की इच्छुक है, तो उसे गो–वध के नाम पर घृणा फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी होगी. ऐसे तत्वों का दिमाग़ दुरुस्त करना ज़रूरी है, ताकि वे समझ सकें कि गो–रक्षा का मतलब गो–वध के ख़िलाफ़ हिंसा करने के बजाय गो–पालन को बढ़ावा देना है. गांवों को गो–केंद्रित योजनाओं से जोड़ना होगा. नदियों एवं जलाशयों के किनारे बसे गांवों में गो–पालन को प्रोत्साहन देना होगा और इलाकाई स्कूलों–कॉलेजों में पढ़ रहे युवाओं को उससे जोड़ना होगा. ग्रामीणों एवं वनवासियों को गो–पालन के ज़रिये बाज़ार से जोड़ा जा सकता है. इससे देश के भूमिहीन किसानों, मज़दूरों, पिछड़ों एवं दलितों को फ़ायदा होगा. इससे न सिर्फ़ कुपोषण की समस्या ख़त्म होगी, बल्कि गोबर–गैस और गोबर–खाद के इस्तेमाल के ज़रिये पर्यावरण की रक्षा भी संभव हो सकेगी. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 36
दिल्ली, 09 नवंबर–15 नवंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यह दिल्ली की एक ऐसी सच्ची तस्वीर है, जो कानों सुनी या आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि आंखों देखी है. दक्षिणी दिल्ली के कालका जी इलाके में रहने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने एक गाय को लेकर अपने जो अनुभव बताए, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे. दिल्ली नगर निगम के कब्जे से एक गाय छुड़ाने के लिए उनकी ओर से की गई जद्दोजहद न सिर्फ़ कई अमानवीय चेहरों की कहानी कहती है, बल्कि समाज का दोहरा चरित्र भी सामने लाती है. यह दोहरा चरित्र बताता है कि कैसे हम एक तरफ़ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ़ उसी गाय को शहर साफ़ करने के नाम पर जीते–जी मौत के मुंह में धकेल देते हैं.

दिल्ली

# गौशाला : जहां अपनी माता को मरने के लिए भेज देते हैं

**आज हम इंसानों के लिए बने वृद्धाश्रमों की नहीं, बल्कि गौ माता के वृद्धाश्रम यानी गौशालाओं की बात करेंगे. वह भी दिल्ली यानी देश की राजधानी में स्थित गौशालाओं की, जहां एक फोन कॉल पर पुलिस केरल भवन में बीफ होने की शिकायत पर जांच करने पहुंच जाती है. उस दिल्ली की, जहां से चंद किलोमीटर दूर दादरी में बीफ रखने के शक में असामाजिक तत्व घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर देते हैं. आइए, जानते हैं दिल्ली में हमारी गौ माता की हालत क्या है?**

शशि शेखर

इंसान के जीवन का पहला निवाला दूध है, मां का दूध, फिर गाय का दूध. शायद इसलिए भी हम गाय को मां का दर्जा देते हैं. एक अकेली गाय अपने दूध से कईयों को जीवन देती है, अपने गोबर से खेतों में हरियाली लाती है, ऊर्जा का स्रोत बनती है. लेकिन, वही गाय जब हमारे काम की नहीं रहती यानी दूध देना बंद कर देती है, तो हम क्या करते हैं? शायद वही, जो आज का तथाकथित सभ्य समाज अपनी जन्मदात्री के साथ करता है. इस देश में हज़ारों वृद्धाश्रम हैं, जहां लोग अपने वृद्ध माता–पिता को छोड़ आते हैं. उसी तरह यही तथाकथित सभ्य समाज दूध न देने पर अपनी मां यानी गाय को सड़क पर खुला छोड़ देता है या फिर गौशाला भेज देता है. खैर, आज हम वृद्धाश्रमों की नहीं, बल्कि बात करेंगे गौ माता के वृद्धाश्रम यानी गौशालाओं की. वह भी दिल्ली यानी देश की राजधानी में स्थित गौशालाओं की, जहां एक फोन कॉल पर पुलिस केरल भवन में बीफ होने की शिकायत पर जांच करने पहुंच जाती है. उस दिल्ली की, जहां से चंद किलोमीटर दूर दादरी में बीफ रखने के शक में असामाजिक तत्व घर में घुसकर एक शख्स की हत्या कर देते हैं और उसके बेटे को जख्मी.

यह दिल्ली की एक ऐसी सच्ची तस्वीर है, जो कानों सुनी या आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि आंखों देखी है. दक्षिणी दिल्ली के कालका जी इलाके में रहने वाली एक वरिष्ठ महिला पत्रकार ने एक गाय को लेकर अपने जो अनुभव बताए, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे. दिल्ली नगर निगम के कब्जे से एक गाय छुड़ाने के लिए उनकी ओर से की गई जद्दोजहद न सिर्फ़ कई अमानवीय चेहरों की कहानी कहती है, बल्कि समाज का दोहरा चरित्र भी सामने लाती है. यह दोहरा चरित्र बताता है कि कैसे हम एक तरफ़ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ़ उसी गाय को शहर साफ़ करने के नाम पर जीते–जी मौत के मुंह में धकेल देते हैं.

उक्त वरिष्ठ महिला पत्रकार बताती हैं कि उनके मोहल्ले में रोज़ एक तंदुरुस्त गाय आती थी. वह उसे रोज़ाना रोटी खिलाती थीं. एक दिन गाय नहीं आई, तो उन्होंने यूं ही पता किया कि आख़िर वजह क्या है? मोहल्ले के लोगों ने बताया कि एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) वाले आज ही उसे ट्रक में भरकर ले गए हैं. ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले निर्देश दिया था कि शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं को हटाया जाए. उसी निर्देश के आलोक में एमसीडी वाले शिकायत मिलने पर या खुद ऐसे पशु देखने पर उठा ले जाते हैं. खैर, जब वरिष्ठ महिला पत्रकार को पता चला कि एमसीडी वाले उस गाय को उठा ले गए हैं, तो उन्होंने उसे एमसीडी के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी. अगले दिन सबसे पहले वह अपने एक साथी के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उस दफ्तर पहुंचीं, जहां शहर की गलियों से पकड़ कर लाई गई गायों की गणना होती है और फिर उन्हें वहां से बाहरी दिल्ली स्थित विभिन्न गौशालाओं में भेज दिया जाता है.

## हिंदू गाय-मुस्लिम गाय

दिल्ली का किशनगढ़ गांव. यहां एक गौशाला है, क़रीब 125 साल पुरानी, जिसमें मौजूद गायों की संख्या तक़रीबन 1,200 है, जिनकी देखभाल करती हैं आसिया खान और उनका परिवार. आसिया बताती हैं कि वह रोज़ाना सबसे पहले गायों को नहला कर उनका गोबर साफ़ करती हैं. उसके बाद वह पशुओं में होने वाली बीमारियों और चारे की जांच करती हैं. वह कहती हैं कि गायों की सेवा से उन्हें खुशी मिलती है. यह गौशाला दक्षिणी दिल्ली के क़रीब 30 गांवों द्वारा दिए जाने वाले पैसों से चलती है. आसिया और उसके पति किशनगढ़ की इस गौशाला में 13 वर्ष पहले आए थे और तबसे गायों की सेवा कर रहे हैं. यहां सवाल यह उठता है कि आसिया तो मुस्लिम हैं, लेकिन क्या वे 1,200 गायें भी किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई हैं? ■

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर पहुंचने के बाद जब उन्होंने वहां के कर्मचारियों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि उस गाय को कल ही बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित एक गौशाला में भेज दिया गया है. वह किसी भी क़ीमत पर उस गाय को छुड़ाना चाहती थीं. उन्होंने वहां एमसीडी का एक ट्रक देखा, जिसमें क्षमता से कहीं अधिक गायों को ठूंस–ठूंस कर भरा गया था और उन्हें भी नजफगढ़ स्थित उसी गौशाला में ले जाने की तैयारी हो रही थी, जहां उनके मोहल्ले की गाय को पहुंचाया गया था. वह बताती हैं कि उन्होंने उस ट्रक का पीछा करने का फ़ैसला किया. ट्रक के पीछे–पीछे चलते हुए वह नजफगढ़ पहुंच गईं. वह बताती हैं कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर से नजफगढ़ पहुंचने का रास्ता बेहद खराब है और उसके बावजूद ट्रक में इतनी अधिक संख्या में गायों को भरा गया था कि वहां तक पहुंचते–पहुंचते आधी से अधिक गायें बेहाल हो चुकी थीं. खैर, ट्रक ने जैसे ही गौशाला में प्रवेश किया, उन्होंने भी अपनी कार उसके पीछे ले जाकर खड़ी कर दी. वहां उन्होंने जो दृश्य देखा, वह किसी भी इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी था.

वह बताती हैं, हमने वहां गायों के ज़िंदा कंकाल देखे. वे कातर निगाहों से हमें देख रही थीं, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि हम उन्हें बचाकर वहां से ले जाएंगे. गौशाला के एक कर्मचारी ने तुरंत आकर उनसे सबसे पहले यह पूछा कि वह बिना अनुमति के अंदर कैसे आ गईं? उन्होंने पूरी कहानी बताई कि वह अपनी गाय छुड़ाने के लिए आई हैं. वह बताती हैं कि उस गौशाला में जितनी जगह थी, उस लिहाज से कहीं ज़्यादा गायें वहां मौजूद थी. उन्होंने वहां देखा कि एक मरी गाय किनारे पड़ी हुई थी, जिसका शरीर फूलकर काफी बड़ा हो गया था. इस बारे में पूछने पर गौशाला के कर्मचारी ने उनसे सिर्फ़ इतना कहा कि हां, इसे हटाने के लिए बोला गया है.

गौशाला में गायों की बदहाली के बारे में उक्त कर्मचारी का कहना था कि प्रति गाय प्रतिदिन सिर्फ़ 40 रुपये मिलते हैं, चारा वगैरह खिलाने के लिए. इतने पैसों में क्या किया जा सकता है? महिला पत्रकार ने बताया कि वहां गायों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह अपनी गाय ढूंढ नहीं पाईं. हो सकता है कि जिस तरह गायों को वहां लाया और रखा जाता है, उससे उनकी गाय मर गई हो. उन्होंने वहां गायों की जो हालत देखी, वह जीते–जी किसी की हत्या करने जैसी थी. सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी हवाला देते हुए, जिसमें सड़कों पर घूमते पशुओं को उठाने के लिए कहा गया है, वह कहती हैं कि अदालत को इन गौशालाओं की हालत भी देखनी चाहिए कि कैसे इन गायों को असमय मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है.

वह जब मुझे यह कहानी बता रही थीं, तो उनके चेहरे पर संवेदना, गुस्सा, लाचारी यानी सारी भावनाएं एक साथ तैर रही थीं. उनकी आंखों में इस बात की लाचारी दिख रही थी कि वह अपने मोहल्ले की उस गाय को बचा नहीं सकीं और गुस्सा पूरे सिस्टम पर. खासकर उस समाज पर, जो गाय को माता तो मानता है, लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, वह उसे न सिर्फ़ अपने दिल से, बल्कि अपने घर से, अपने शहर से बाहर एक ऐसी जगह भेज देता है, जहां मौत उसका इंतजार कर रही होती है. और, सबसे अहम तथ्य यह कि ज़्यादातर गौशाला संचालक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, खुद को हिंदू संत बताते हैं.

एक तरफ़ गाय के नाम पर इस देश में राजनीति और गंदी बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ़ शर्मनाक तथ्य यह सामने आया है कि दिल्ली नगर निगम, जहां पिछले एक दशक से भी अधिक समय से सत्ता में भाजपा है, ने अब तक जितनी गायें सड़कों से उठाकर गौशाला भिजवाईं, उनमें से क़रीब 90 फ़ीसद गायें असमय काल का ग्रास बन गईं. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2008 में मई से अक्टूबर तक यानी छह महीने के दौरान 11 हज़ार 26 गायें पकड़ कर दिल्ली की विभिन्न गौशालाओं में भेजी गईं, जिनमें से 10 हज़ार 716 गायों की मौत हो गई. 2007 में कुल 10 हज़ार 574 गायें सड़कों से उठाई गईं और इसी साल 10 हज़ार 793 गायें मर गईं. यानी 2007 में पकड़ी गईं गायों में से एक भी गाय जीवित नहीं बची और 2006 में पकड़ी गई कुल गायों में से भी 119 गायें मर गईं.

ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में कुछ सवाल मन में उठते हैं. असमय गायों को मरने पर मजबूर कर देने के पीछे क्या कोई साज़िश है? क्या इसके पीछे मांस या चमड़ा व्यापार से जुड़े लोग हैं? आख़िर मरी हुई गायों का होता क्या है? कहां जाती हैं ये गायें? जिस ढंग से अधमरी हालत में गायों को गौशालाओं तक पहुंचाया जाता है, क्या यह जानबूझ कर, किसी के कहने पर, किसी लालच में किया जाता है? इन सवालों के जवाब गाय की राजनीति करने से पहले गाय की राजनीति करने वालों को ढूंढना चाहिए. लेकिन, क्या ऐसा हो पाना संभव है? ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

## कौन बेचता है बीफ

बीफ का निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत नंबर वन है. देश में बीफ का सालाना कारोबार 300 अरब रुपये का है. 2014 में भारत ने 24 लाख टन बीफ निर्यात किया था, जो पूरी दुनिया में बीफ के कारोबार का क़रीब साठ फ़ीसद हिस्सा है. सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत से भैंसों का मांस सबसे अधिक एशियाई देशों में जाता है यानी 80 फ़ीसद. शेष में से 15 फ़ीसद अफ्रीकी देशों को निर्यात किया जाता है. एशियाई देशों में भी खासकर वियतनाम भारत के 45 फ़ीसद बीफ का खरीदार है. 2014 में भारत को बीफ निर्यात से 48 लाख डॉलर की कमाई हुई. सरकार बीफ के कारोबार पर 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है. सबसे अहम बात यह है कि भले ही हिंदूवादी संगठन धार्मिक आधार पर इसका विरोध कर रहे हों, पर सच्चाई यह है कि देश के सबसे बड़े चार मांस निर्यातक हिंदू हैं, न कि मुसलमान. यानी अरेबियन एक्सपोर्ट (सुनील करन), एमकेआर फ्रोजन फूड्स (मदन एबट) अल कबीर एक्सपोर्ट (सतीश एवं अतुल सभरवाल) और पीएमएल इंडस्ट्रीज (एएस बिंद्रा). ■

## दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के तहत चलने वाली गौशालाएं

1. गोपाल गौसदन, हारेवेली.
2. श्रीकृष्णा गौशाला, सुल्तानपुर डबास.
3. डॉबर हरिकृष्ण गौसदन, सुरहेरा.
4. मानव गौसदन, रेवला खानपुर.
5. आचार्य सुशील गौसदन, घूमनहेरा.

दंगे फैलाने के पीछे के कुचक्र का एहसास करते चलें. कानपुर शहर में धार्मिक बैनर फाड़ने की घटना से तनाव की शुरुआत हुई. उसके बाद अफ़वाह फैली कि इसके विरोध में मुहर्रम का जुलूस रोका जाएगा. फिर क्या था, कानपुर में हिंसा शुरू हो गई. मारपीट, पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटनाएं होती रहीं, लेकिन ज़िला पुलिस गलियों में घुसने का साहस नहीं बटोर पाई. शहर में धारा–144 लागू होने के बावजूद हालात बेकाबू थे. चंद्रिका देवी इलाके में इंस्पेक्टर डीके सिंह एवं आरआई एमपी शर्मा दंगाइयों की गोली से जख्मी हुए, लेकिन पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई. कानपुर के डीएम कौशलराज शर्मा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने में ही पूरा ध्यान लगाए रह गए.

# यूपी में तेज़ी से बढ़ रहा है सांप्रदायिक तनाव और सियासी टकराव

सभी फोटो–जीपी अवस्थी

# आख़िर कौन कर रहा है नफ़रत की खेती

**राजनीतिक नफा–नुकसान का आकलन करने के बाद ही कोई क़दम उठाने की मानसिकता ने राजनेताओं एवं पार्टियों को इस कदर स्वार्थी बना दिया है कि वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और अमन–चैन बिगाड़ने के पीछे भी यही मानसिकता देखने को मिली. किसने और कैसे अंजाम दी यह घिनौनी साज़िश, पढ़िए इस स्टोरी में...**

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, उसी तेजी से राजनीतिक टकराव भी बढ़ रहा है. इस तनाव और टकराव के अंतर्संबंध हैं. दादरी के बाद मैनपुरी, फिर कन्नौज, फिर कानपुर और उसके बाद तक़रीबन पूरे प्रदेश में जिस तरह सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसा की घटनाएं हुईं, उस पर ग़ौर करें, तो उसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ साफ़–साफ़ दिखाई पड़ेंगे. केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी उसका साथ देती रही, लेकिन आज कांग्रेस ही आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही हैं. दोनों ही पार्टियों को अलग–अलग नज़रिये से इसका फ़ायदा नज़र आता है. वाराणसी के सांप्रदायिक तनाव के हवाले से कांग्रेस का कहना है कि हिंसा भड़काने में भाजपाइयों का हाथ था, लेकिन सपा सरकार ने कांग्रेस नेता अजय राय एवं पार्टी समर्थकों पर मुक़दमा ठोक दिया. यह सपा–भाजपा की मिलीभगत का उदाहरण है. दूसरी तरफ़ मायावती भी लगातार यह आरोप लगाती आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और फसाद की वारदातें सपा–भाजपा की मिलीभगत से हो रही हैं. दादरी कांड के बाद जिस तरह क्रमिक रूप से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ीं और दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम तक आकर व्यापक शक्ल लेने लगीं, उससे साफ़ हुआ कि इसके पीछे राजनीतिक भागीदारी भले न हो, लेकिन राजनीतिक समझदारी ज़रूर है.

दादरी के बाद मुलायम सिंह के पुराने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी और अखिलेश के पुराने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में हिंसा भड़क उठी. मुलायम सिंह अभी हाल में यह कह चुके हैं कि मैनपुरी ही उनकी असली कर्मभूमि रही है. और, कन्नौज तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव के कब्जे में है. मैनपुरी संसदीय सीट भी मुलायम सिंह के पौत्र तेज प्रताप यादव को उत्तराधिकार–उपहार में मिली है. लिहाजा, इन क्षेत्रों में सांप्रदायिक उन्माद फैलना राजनीतिक दृष्टिकोण से गंभीर है. यादव विरासत के इन इलाकों में फैली यह सांप्रदायिक आग सुलगती हुई धीरे–धीरे प्रदेश के कई ज़िलों में फैल गई. प्रदेश में फैल रहा सांप्रदायिक तनाव कम करने और अपनी–अपनी कर्मभूमि में सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करने के बजाय सपा के अलमबरदार लखनऊ में चिंतन बैठक में लगे रहे. चिंतन का विषय था, राज्यपाल राम नाईक से कैसे पार पाया जाए. राम नाईक सपा सरकार के अलोकतांत्रिक कृत्यों को बार–बार संविधान का लाल सिग्नल दिखा रहे हैं, इसलिए सपा ने उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. सरकार की प्राथमिकता चुनाव के पहले प्रदेश में पूर्ण अराजकता का सृजन करना है, चाहे वह सांप्रदायिक मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर. विधान परिषद में संदेहास्पद किस्म के लोगों को भेजने या अपनी जाति के विवादास्पद शख्स को लोकायुक्त बनाने की जिद अराजकता की ओर बढ़ रहे क़दमों का ही एक आयाम है, जिस पर राज्यपाल ने अड़ंगा लगा रखा है.

बहरहाल, दादरी की घटना पर देश भर में राजनीति तो खूब हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन की हनक के धराशायी होने पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दादरी कांड के बाद प्रदेश की क़ानून व्यवस्था की समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं समझी. जब सांप्रदायिक उन्माद विस्तार लेने लगा, तब पिछले दिनों (26 अक्टूबर को) मुख्यमंत्री ने क़ानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश देकर छुट्टी कर ली. अंदर ही अंदर सुलग रहा तनाव दुर्गा पूजा और मुहर्रम के दौरान सतह पर आ गया. यह कानपुर, बांदा, कन्नौज, सिद्धार्थ नगर, कुशी नगर, फतेहपुर, संत कबीर नगर होता हुआ कई अन्य ज़िलों में फैल गया. प्रदेश के क़रीब दर्जन भर ज़िले सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में हैं. सिद्धार्थ नगर और कन्नौज में दो–दो लोग मारे गए. कानपुर में तो पुलिस वालों पर ही खुलेआम गोलियां दागी गईं. दो पुलिस वालों को गोली लगी और दर्जनों लोग घायल हुए. कानपुर के फजलगंज, सीसामऊ, नौबस्ता एवं चमनगंज थाना क्षेत्रों में सांप्रदायिक झड़पों ने दंगे का रूप लेना शुरू कर दिया था. पीएसी समेत अर्द्धसैनिक बल उतारने के बाद स्थिति काबू में आ पाई.

दंगे फैलाने के पीछे के कुचक्र का एहसास करते चलें. कानपुर शहर में धार्मिक बैनर फाड़ने की घटना से तनाव की शुरुआत हुई. उसके बाद अफ़वाह फैली कि इसके विरोध में मुहर्रम का जुलूस रोका जाएगा. फिर क्या था, कानपुर में हिंसा शुरू हो गई. मारपीट, पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटनाएं होती रहीं, लेकिन ज़िला पुलिस गलियों में घुसने का साहस नहीं बटोर पाई. शहर में धारा–144 लागू होने के बावजूद हालात बेकाबू थे. चंद्रिका देवी इलाके में इंस्पेक्टर डीके सिंह एवं आरआई एमपी शर्मा दंगाइयों की गोली से जख्मी हुए, लेकिन पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई. कानपुर के डीएम कौशलराज शर्मा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने में ही पूरा ध्यान लगाए रह गए. डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में भी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हिंसा भड़की और लगातार कई दिनों तक जारी रही. फायरिंग में युवक अपूर्व गुप्ता एवं महेश कुशवाहा की मौत के बाद हिंसा और तेजी से भड़की, जो फतेहपुर तक फैल गई. कर्फ्यू के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी. हालत इतनी खराब होने लगी कि सरकार को प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा. प्रमुख सचिव (गृह) देबाशीष पंडा और डीजीपी जगमोहन यादव को सीधे कमान संभालनी पड़ी. उपद्रवियों की हरकतों पर नियंत्रण न हो पाने के बाद कन्नौज शहर को आख़िरकार बीएसएफ के हवाले करना पड़ा. कन्नौज में दुर्गा विसर्जन के दरम्यान लाखन तिराहे के पास यात्रा में शामिल युवकों के साथ मारपीट हुई. बताया गया कि विसर्जन यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों का विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद हिंसा भड़की.

फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के मंडवा गांव में देवी प्रतिमा जुलूस निकालने को लेकर दो गुटों के बीच बवाल हो गया. मुहर्रम और विसर्जन जुलूसों के आमने–सामने पहुंचने पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई. लोगों ने कुछ घरों और वाहनों में आग लगा दी. फायरिंग और पथराव में दर्जन भर लोग घायल हुए. सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ में मंदिर के सामने से ताजिया जुलूस निकालने के दौरान हिंसा भड़क गई. उसके बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई. घटना में गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय सूर्य लाल अग्रहरि की अस्पताल में मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि हिंसा में जख्मी एक और व्यक्ति की बाद में मौत हो गई, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. हिंसक वारदातों में दर्जनों लोग जख्मी हुए. कुशी नगर ज़िले के कसया इलाके में दुर्गा प्रतिमा पंडाल के सामने से ताजिया निकालने को लेकर विवाद हो गया. रास्ता संकरा होने की वजह से दुर्गा प्रतिमा पंडाल कटवा कर जुलूस का रास्ता निकाला गया. हालांकि, प्रशासन ने पहले वहां से ताजिया निकालने की इजाजत नहीं दी थी. दोनों तरफ़ से खूब पथराव हुआ, दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए. पीएसी की तैनाती के बाद से स्थिति नियंत्रण में है. संत कबीर नगर ज़िले के खलीलाबाद में मुहर्रम का जुलूस मंदिर के रास्ते ले जाने को लेकर बवाल हुआ. भीड़ द्वारा पथराव करने से चार पुलिस वाले घायल हो गए. बांदा ज़िले के अतर्रा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रतिमा टूटने की वजह से बवाल हो गया. पथराव में स्थानीय लोगों समेत सीओ अतर्रा और एसडीएम भी घायल हो गए. भीड़ को तितर–बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी. उल्लेखनीय है कि नोएडा के दादरी इलाके में गोमांस को लेकर हुई हत्या और बवाल के बाद मुलायम सिंह के क्षेत्र मैनपुरी के करहल इलाके में भी गाय काटे जाने की अफ़वाह पर हिंसा फैल गई. पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं, पुलिस की जीप फूंक डाली गई. आख़िरकार मैनपुरी में भी पीएसी तैनात करनी पड़ी. ■

feedback@chauthiduniya.com

## ऐसे होती है क़ानून व्यवस्था की समीक्षा!

कई ज़िलों में सांप्रदायिक हिंसा और उन्माद फैलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क़ानून व्यवस्था की समीक्षा करने की ज़रूरत समझी. 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और समीक्षा के नाम पर औपचारिक निर्देश देकर चलते बने. राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि क़ानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान क्या-क्या खामियां पाई गईं और उन्हें दुरुस्त करने के क्या उपाय किए गए. मुख्यमंत्री ने सिर्फ़ समाज में अव्यवस्था फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश देते हुए कहा कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता. क़ानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार किस तरह ज़मीनी हक़ीकत से दूर केवल औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसकी बानगी देखिए... राज्य सरकार अमन-चैन का माहौल कायम रखने के लिए कटिबद्ध है, ताकि प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया जा सके. सरकार ने पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को क़ानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश पहले से ही दे रखे हैं. ऐसे में इन अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करें. उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण प्रदेश है. इसलिए यहां की घटनाओं पर लोगों की निगाह बनी रहती है. क़ानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में पुलिस की प्रमुख भूमिका से अवगत होने के कारण राज्य सरकार पुलिस को सभी ज़रूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है. रात्रिकालीन गश्ती व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की जाए और शहरों के बाहरी इलाकों में गश्त में विशेष सावधानी बरती जाए. ■

## भाजपा का बचाव, राज्यपाल पर निशाना

उत्तर प्रदेश की लगातार खराब होती क़ानून व्यवस्था की स्थिति से सख्ती से निपटने के बजाय समाजवादी पार्टी ने अपना निशाना केवल राज्यपाल राम नाईक पर साध रखा है. राज्यपाल ने सरकार के अलोकतांत्रिक कामकाज पर संवैधानिक प्रश्न खड़ा करके सपा को नाराज़ कर दिया है. अयोग्य एवं विवादास्पद लोगों को विधान परिषद में मनोनीत करने का मसला हो या विवादास्पद व्यक्ति को लोकायुक्त बनाने का, राज्यपाल ने सरकार के रास्ते में संवैधानिक अड़चन लगा रखी है. इससे बौखलाए सपा नेता प्रो. राम गोपाल यादव ने राज्यपाल के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने में आजम खान को पीछे छोड़ दिया है. राम गोपाल ने कहा, राज्यपाल हर घटना पर बयानबाजी करते हैं. वह प्रदेश के गृह मंत्री बन गए हैं, वह मुख्यमंत्री से मुलाकात को भी उजागर कर देते हैं. राज्यपाल पद की गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं. राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं. उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, तो बेहतर होगा, क्योंकि वह सरकार के ख़िलाफ़ रोज़ बयान देते हैं. सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर उठने वाले सवालों पर राम गोपाल ने कहा, अगर 75 में से तीन ज़िलों में बवाल हुआ, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया? सरकार को बदनाम करने के लिए साज़िश हो रही है.

इस बयान के बरक्स ज़मीनी तथ्य यह है कि दादरी कांड के बाद दर्जन भर ज़िलों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं. यदि सांप्रदायिक तनाव से ग्रस्त ज़िलों को भी जोड़ लें, तो यह संख्या और बढ़ जाती है. राज्यपाल पर प्रहार करने वाले राम गोपाल ने भाजपा के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी नहीं की. इस बारे में पूछने पर राम गोपाल बोले कि राज्यपाल की आलोचना पार्टी की ही आलोचना है. अभी कुछ ही दिनों पहले राम गोपाल ने राम नाईक के ख़िलाफ़ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्यपाल को महामहिम कहने में भी उन्हें लज्जा आती है. राम गोपाल के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है. पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सपा महासचिव राम गोपाल यादव प्रदेश की बदहाल क़ानून व्यवस्था पर राज्यपाल की टिप्पणी से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सपा सरकार के मंत्रियों को कुछ नहीं कहते, जो बलात्कार के लिए मोबाइल को ज़िम्मेदार ठहराते हैं. पाठक कहते हैं कि सपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए राज्यपाल को ज़िम्मेदार ठहरा रही है. ■

## छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक स्टांप ड्यूटी प्रकरण

# रियायत की आड़ में करोड़ों लूटने की साज़िश

**कोयले को काला हीरा कहा जाता है. शायद यही वजह है कि हर कोई कोयला खदान हासिल करने की भरपूर कोशिश करता है. यही कोयला कांग्रेस के मौजूदा दुर्दिनों की वजह बना. सबने देखा कि एक राष्ट्रीय पार्टी कैसे देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ गई. लेकिन, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगाने का आदी हो चुका कंपनियों, नेताओं एवं नौकरशाहों का गठजोड़ फिर भी बाज नहीं आया, जिसका ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ है, जहां कोयला खदानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी की आड़ में सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये लूटने की साज़िश रची जा रही है.**

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद कोयला खदानें हासिल करने के लिए देश की बड़ी–बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों, राजनेताओं एवं नौकरशाहों ने कैसे–कैसे तिकड़म आजमाए, यह सब कुछ जनता के सामने आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाकर यूपीए शासनकाल में हुए कोयला खदानों के आवंटन निरस्त हुए. नई सरकार आने के बाद उक्त कोयला खदानों की फिर से नीलामी हुई और उससे क़रीब दो लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. कंपनियों ने ऊंची बोली लगाकर कोयला खदानें हासिल कीं. ज़ाहिर है, यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कोयला तो आख़िर कोयला है. कोयले और विवाद का रिश्ता चोली–दामन जैसा बना दिया गया है. नतीजतन, कोयला खदान आवंटन के छह महीने बाद अब उससे जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा है.

दरअसल, सितंबर 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया, तो उसके बाद आई नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से उनकी नीलामी कराई और ऊंचे दामों पर उक्त कोयला खदानें नीलाम हुईं. नीलामी में कामयाब रहीं कंपनियों को एक अप्रैल से संबंधित खदानों पर कब्जा भी मिल गया, लेकिन छह माह बीत जाने के बावजूद आज तक खनन का काम शुरू नहीं हो सका है, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में क़रीब सौ गुना वृद्धि हो गई है. पहले स्टांप ड्यूटी की गणना खनिज की रॉयल्टी के आधार पर होती थी. जैसे, किसी कंपनी की उत्पादन क्षमता यदि एक मिलियन टन प्रति वर्ष है, तो 100 रुपये प्रति टन रॉयल्टी के हिसाब से उसे स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी. अब चूंकि कोयले की खरीद बोली लगाकर होती है, इसलिए स्टांप ड्यूटी की गणना बोली की रकम पर की जाती है. अब बदले हुए केंद्रीय नियम के मुताबिक, यदि कोई कंपनी 3000 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला खरीदती है और उसकी उत्पादन क्षमता एक मिलियन टन प्रति वर्ष है, तो उसे स्टांप ड्यूटी के रूप में 300 करोड़ और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 225 करोड़ रुपये अदा करने होंगे. यानी पहले जहां चार से पांच करोड़ रुपये में काम चल जाता था, वहां अब कंपनी को 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी.

छत्तीसगढ़ का मामला देखिए. यहां वेदांता के नियंत्रण वाली कंपनी बाल्को ने चोटिया कोयला खदान 3,025 रुपये प्रति टन के हिसाब से ली है, जिसके लिए अब उसे 536 करोड़ रुपये बतौर स्टांप ड्यूटी अदा करने पड़ेंगे. बाल्को का कहना है कि इतनी भारी–भरकम स्टांप ड्यूटी देने से उसके लिए खदान चलाना मुश्किल होगा. हिंडालको ने भी क़रीब 3,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बोली लगाई थी. उसके बाद से ही दोनों कंपनियों ने सरकार पर यह शुल्क कम करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. नतीजतन, हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना स्टांप ड्यूटी नियम बदल डाला. वह भारतीय स्टांप (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश 2015 के ज़रिये मूल अधिनियम की अनुसूची एक (क) में संशोधन करके कोयला खदानों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में छूट देने जा रही है. यहां सवाल उठता है कि जब उक्त कंपनियों को पहले से पता था कि नीलामी की राशि से स्टांप ड्यूटी तय होगी, जिससे उसमें वृद्धि तय है और ज़ाहिर है कि उन्होंने मुनाफ़े का दोबारा आकलन करने के बाद ही नीलामी में हिस्सा लिया होगा, तो फिर अब स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग क्यों की जा रही है?

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years; — The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the amount or value of one and half times the average annual royalty reserved.

(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years; — The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of average annual royalty reserved.

(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years; — The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to five times the amount or value of the average annual royalty reserved.

(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding one hundred years; — The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to eight times the amount or value of the average annual royalty reserved.

(viii) where the lease does not purport to be for any definite term; — The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of the average annual royalty, which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

Provided that nothing contained in clause (b) and (c) of this Article shall be applicable in respect of this clause.

**Explanation**- In case of grant of mining lease on the basis of auction no Stamp Duty shall be chargeable on any amount other than royalty."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि स्टांप ड्यूटी कम करने से संबंधित अध्यादेश लाने से पहले राज्य के महाधिवक्ता से राय–मशविरा किया गया. लेकिन, यहां राय–मशविरा करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस फ़ैसले से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुक़सान नहीं होगा?

एक तरफ़ तो केंद्र सरकार ने पारदर्शी तरीके से कोयला खदानों की नीलामी कराकर क़रीब दो लाख करोड़ रुपये एकत्र किए, वहीं दूसरी तरफ़ आज छत्तीसगढ़ सरकार स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देकर क्यों अपने राजस्व का नुक़सान कराना चाहती है? एक अनुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार के संशोधित स्टांप ड्यूटी अध्यादेश की वजह से कोयला खदानें हासिल कर चुकीं कंपनियों मसलन, बाल्को को 500 करोड़, मोनेट को 1,300 करोड़ और हिंडाल्को को 2,700 करोड़ रुपये का फ़ायदा पहुंच सकता है. यानी इतनी बड़ी रकम का नुक़सान राज्य सरकार को होने जा रहा है. सवाल है कि यह हज़ारों करोड़ रुपये का जो नुक़सान होगा, वह पैसा आख़िर किसका है? राज्य सरकार का या राज्य की जनता का?■

## करछना किसान आंदोलन

# मांगा हक़, मिली लाठियां

अरुण तिवारी feedback@chauthiduniya.com

विकास की शर्त क्या है? क्या किसी समाज या क्षेत्र का विकास वहां रहने वाले लोगों की इच्छा के विरुद्ध किया जाना उचित है. यानि किसी गांव की जमीन विकास के नाम पर उनसे ले लीजिए, वह भी सींचित जमीन, और जब वहां के लोग इसका विरोध करें तो उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया जाए.उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के करछना में किसानों के साथ सरकार का सुलूक कुछ इस तरह का है. यहां पर थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई. इन जमीनों पर प्लांट लगाने का ठेका मिला जेपी कंपनी को और उसके बाद से शुरू हो गई इस इलाके के किसानों के सरकारी दमन की कहानी. किसान अपनी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी राज्य की सरकार अपनी मनमानी करने पर उतारू है.

दरअसल साल 2007 में राज्य की तत्कालीन सरकार ने करछना के आठ गांवों (देवरीकला, कचरी, कचरा, मेरड़ा, टोलीपुर, देलही, भगेसर, भिटार और खई) के किसानों की जमीन को जेपी को प्लांट लगाने के लिए आवंटित कर दिया. इन गांवों के किसानों को जमीन के एवज में नौकरी और मुआवजा देने की पेशकश की गई. हालांकि किसानों ने शुरुआत से ही सरकार के मंसूबे ताड़ लिए थे और उसी साल से इस भूमि अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया. किसानों ने प्रदर्शन किए लेकिन प्रशासन ने इसकी अनदेखी करते हुए लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखी जिससे आजिज आकर किसानों ने साल 2008 में इस पूरी योजना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी. न्यायालय ने भूमिअधिग्रहण को स्थगित कर दिया. लेकिन किसानों को न्यायालय की तरफ से मिली इस राहत के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपनी कागजी कार्रवाई जारी रखी और गड़बड़झाला करते हुए किसानों की 17 सौ हेक्टेयर सींचित भूमि को बंजर दिखा दिया और उस जमीन को जेपी को हस्तांतरित कर दिया. यह याद रखने वाली बात है कि यह सारी कार्रवाई प्रदेश की तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार की थी.

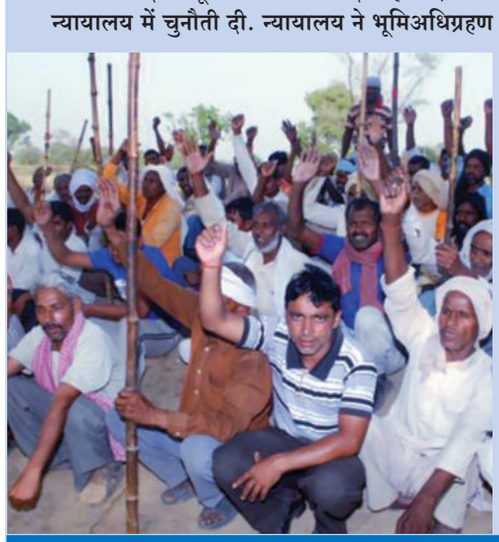

किसानों के विरोध जारी रखने के कारण सरकार ने उनके खिलाफ 28 जून 2010 को कार्रवाई की और 16 किसानों व 150 अज्ञात किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. नाराज किसानों ने 2011 में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया. तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस बारे में अनशनकारी रहे राज बहादुर पटेल का कहना है कि उस वक्त अनशन स्थल पर तमाम किसान, महिलायें, बच्चे मौजूद थे तथा 14 दिन से आमरण अनशन पर लोग बैठे थे. पहुंचते ही अनशनकारियों तथा वहां उपस्थित लोगों के ऊपर अधिकारियों की अगुआई में पुलिस ने हमला किया. टेंट गिरा दिया गया, लोगों को मारा–पीटा गया. यहां तक कि महिलाओं–बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया. अनशनकारियों को खींचना शुरू कर दिया गया. उपस्थित लोगों ने विरोध किया जिसपर दोनों तरफ से संघर्ष शुरू हो गया. इस बीच पीएसी के जवान रेल लाइन पर पहुंचे तथा वहां से लोगों पर पत्थर फेंकने लगे और यहां तक कि देवरी तथा कचरी गांवों में घुसकर ग्रामवासियों, महिलाओं को पीटा तथा अपमानित किया गया. इन घटनाओं को देखकर किसान भी उग्र हो गये. पीएसी एवं पुलिस के रेल ट्रैक पर कब्जा कर लेने के नाते रेल मार्ग बंद हो गया. इस पर भी पुलिस, पीएसी तथा आरएएफ का मन नहीं भरा उन्होंने लोगों पर लाठी–डण्डे चलाये, रबर की गोलियां दागीं तथा आंसू गैस छोड़ीं. इस पूरी घटना में तमाम महिला–पुरुष घायल हुए और एक स्थानीय किसान गुलाब विश्वकर्मा की मौत हो गयी. राज बहादुर पटेल आगे बताते हैं कि गुलाब की मौत की खबर सुनकर किसान आपा खो बैठे और उन्होंने दिल्ली–हावड़ा रेल मार्ग पर कब्जा करके इस रेल लाइन का चक्का जाम कर दिया. सैकड़ों लोग लहुलुहान थे. इसमें पुलिस के लोगों को भी चोटें आयीं थी. घायलों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी. आंदोलनकारी प्रशासन के इस कृत्य को जनता पर अघोषित युद्ध की संज्ञा देते हैं. इसमें एक स्थानीय किसान गुलाब की मौत भी गई. स्थितियां बिगड़ते देख तत्कालीन डीएम मामले को शांत करने के लिए किसानों की लिखित मांग स्वीकृत की और मृत किसान को पांच लाख रुपये का चेक दिलवाया.

**किसानों के विरोध जारी रखने के कारण सरकार ने उनके खिलाफ 28 जून 2010 को कार्रवाई की और 16 किसानों व 150 अज्ञात किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. नाराज किसानों ने 2011 में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया. तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस बारे में अनशनकारी रहे राज बहादुर पटेल का कहना है कि उस वक्त अनशन स्थल पर तमाम किसान, महिलायें, बच्चे मौजूद थे तथा 14 दिनों से आमरण अनशन पर लोग बैठे थे.**

पॉवर प्लांट के नाम पर 1920 किसानों से जमीन ली गई थी लेकिन मुआवजा सिर्फ 1850 किसानों ने लिया और 70 किसानों ने इसे लेने से मना कर दिया. आखिरकार 13 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया और किसानों की जमीन वापस करने का आदेश दिया. इसके बाद से ही किसानों ने अपनी जमीन वापस मांगना शुरू कर दिया जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि मुआवजा वापस करो और जमीने ले जाओ. किसानों का कहना है कि हमारी जमीन पर हमने कई सालों से खेती नहीं की. हमें नुकसान हुआ है. सरकार ने हमें तीन लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया था. इतना तो हम खेती करके कमा लेते.

हालिया घटनाक्रम में बीते 9 सितंबर को पुलिस और पीएसी ने धरना स्थल पर पहुंच कर कब्जा कर लिया. इसके बाद पुलिस ने गांवों में घुसकर लोगों की बेहरमी के साथ पिटाई की. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ अत्याचार किया गया. कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस स्टोरी के संदर्भ में जब जिले के डीएम और एसएसपी से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो इन दोनों में किसी ने फोन तक नहीं उठाया. इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश का प्रशासन जनता की शिकायतों को लेकर कितना गंभीर होगा.

अब प्रदेश सपा शासन से यह साधारण सा सवाल बनता है कि किसानों की भूमि यदि हाईकोर्ट ने वापस करने का आदेश दिया है तो किसानों पर यह अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं. क्या प्रदेश में न्यायपालिका के आदेशों के बावजूद भी ऐसी अराजक स्थिति बन गई है कि लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है. प्रदेश सरकार को बर्बरतापूर्वक किसानों की आवाज को दबाने के बजाए उन्हें न्याय देने के लिए चेतना होगा.■

अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं-सहयोगियों की सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी और रात की तो बात न करें. अपनी बात रखने के लिए लोगों को एकत्र करना भी एक चुनौती होती है और भोज एवं खान-पान का इंतजाम इस चुनौती से निपटने का एक आसान तरीका है. भोज के बहाने प्रत्याशियों ने मतदाताओं के सामने अपनी बात रखी. छोटे या टिकट पाने में नाकाम रहे नेताओं ने भोज के सहारे अपने लिए आगे की रणनीति तैयार कर ली. भोज आयोजन को लेकर ऐसे नेताओं की दिलचस्पी देखने लायक थी.

# खइबे तबे न वोटवा देबे

**चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन समाज के ग़रीब-वंचित वर्ग के लिए भरपेट मनचाहा भोजन करने का मौक़ा ही सबसे बड़ा पर्व है. नतीजतन, राजनेताओं ने इस कमज़ोरी को अपना हथियार बनाते हुए पेट के रास्ते मतदाताओं के दिल में सेंधमारी करने के लिए भोज का रास्ता अख्तियार कर लिया. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जगह-जगह भोज का आयोजन इसका जीता-जागता प्रमाण है.**

दिव्या त्रिपाठी

बिहार में महीनों बिना लग्न के ही रोज़ भोज-भात की महफिल नेताओं के घरों में सजती रही. विधानसभा चुनाव 2015 का नज़ारा किसी महोत्सव से कम नहीं था. पार्टी दफ्तर हो या चुनाव क्षेत्र, हर जगह त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला. चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे. उनके खान-पान की बेहतर व्यवस्था सिर्फ़ पार्टी दफ्तर में नहीं थी, बल्कि चुनाव क्षेत्र के हर प्रखंड में दिन होली, रात दीवाली जैसा नज़ारा था. वोट कैसे मिले और लोगों का विश्वास कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए तरह-तरह के प्रयास होते दिखे. बिहार में चुनाव का माहौल किसी शादी-विवाह से कम नहीं होता. यानी सुबह से लेकर देर रात तक स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार. कौन कितना बेहतर भोज देगा, इसकी भी प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिली. कौन कितने ज़्यादा व्यंजन खिला रहा है और कितनी बार, ये सब बातें चुनाव पर असर डालती हैं.

चुनाव की घोषणा होते ही राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न ज़िलों में स्थित विभिन्न पार्टियों के दफ्तरों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा. कार्यकर्ताओं के आने-जाने, खाने-पीने और उनकी सुविधा-असुविधा का पूरा ख्याल रखा गया. प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही शुरू हो गया भोज का दौर, जो मतदान के दिन तक जारी रहा. प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में भोज के ज़रिये प्रचार में चार से पांच लाख रुपये का खर्च आता है. कहां और कैसे हो रही है चुनावी भोज की तैयारी, यह जानने के लिए दौरा करते समय कई बातें सामने आईं. कहीं शाकाहारी भोज, तो कहीं मांसाहारी और कहीं दोनों तरह की व्यवस्था. शाकाहारी में भी कहीं लाल किला चावल, तो कहीं बासमती की खुशबू. सिर्फ़ खाने का नहीं, पीने का भी पूरा इंतजाम. शराब का हर ब्रांड मौजूद, देशी लें चाहे अंग्रेजी. एक कार्यकर्ता ने बताया कि अगर शराब की व्यवस्था नहीं होगी, तो लोग खाने नहीं आएंगे.

भोज के मेन्यू में भी इस बार खासा बदलाव दिखा. बासमती चावल, अरहर की दाल, घी, फूलगोभी की सब्जी, चटनी, पापड़, तरह-तरह के पकौड़े. सुबह पूरी-सब्जी के साथ दही और रसगुल्ले. अरे खइबे तबे न वोटवो देबे, जे जेतना अच्छा खिलैते ओकरे वोट परते जैसी बातें जगह-जगह सुनाई पड़ीं. मंदा पड़ा धंधा भी भोज की बहार के चलते खूब कमाई करता रहा. सब्जी विक्रेता मनोज ने कहा कि सब्जियों की मांग इतनी थी कि दाम चढ़ाकर बेचने पर भी माल कम पड़ जाता था. फूलगोभी एवं टमाटर की मांग सबसे ज़्यादा रही. प्याज महंगा होने के बावजूद जमकर बिका. कई जगहों पर तो पेटी ठेकेदारों को सारी व्यवस्था सौंप दी गई.

महिलाओं ने कहा कि घर में खाना बनाने का मौक़ा नहीं मिला, रोज़ भोज़ का मजा. सुनीता कहती हैं कि घर के पुरुष एवं बच्चे तो भोज में चले जाते थे, लेकिन महिलाएं नहीं, क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता. लोग महिलाओं के लिए खाना घर भिजवा देते थे, जैसा कि शादी-विवाह में होता है.

खान-पान की व्यवस्था उन जगहों पर ज़्यादा दिखी, जहां किसी जाति विशेष की आबादी अधिक थी. जाति विशेष के मतदाताओं को लुभाने का कोई भी मौक़ा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा. कई जगह तो चेहरा देखकर खिलाया गया. यानी जिसके घर में अधिक वोट थे, उसकी ख़ातिरदारी जमकर हुई. नमक का फर्ज चुकाना है, नेता जी को जिताना है, यह नारा सुनने में अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसे नारे हर भोज में सुनने को मिले. कभी मुखिया जी का भोज, तो कभी जाति विशेष के छोटे नेताओं द्वारा खान-पान की व्यवस्था. जिसके पास जितने अधिक वोट, उसकी तरफ़ से भोज. खाना-पीना हो जाने के बाद नमक का वास्ता. संजीव यादव ने टिप्पणी की कि हर नेता खाना खिलाकर वोट पाने की चाहत रखता है और वोट किसी एक को देना है. ऐसे में नमक हलाली कैसे संभव है? कई लोगों ने कहा कि भोज देकर कोई वोट नहीं खरीद सकता. जो बेहतर उम्मीदवार होगा, उसी को जिताएंगे.

अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं-सहयोगियों की सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी और रात की तो बात न करें. अपनी बात रखने के लिए लोगों को एकत्र करना भी एक चुनौती होती है और भोज एवं खान-पान का इंतजाम इस चुनौती से निपटने का एक आसान तरीका है. भोज के बहाने प्रत्याशियों ने मतदाताओं के सामने अपनी बात रखी. छोटे या टिकट पाने में नाकाम रहे नेताओं ने भोज के सहारे अपने लिए आगे की रणनीति तैयार कर ली. भोज आयोजन को लेकर ऐसे नेताओं की दिलचस्पी देखने लायक थी. और, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए था, सो आज यहां भोज, तो कल वहां. यही नहीं, श्राद्ध का भोज भी दोबारा किया गया. जाने ऐसे कितने बहाने खाने और खिलाने के निकाले गए. मकसद सबका एक रहा, मतदाताओं को लुभाना. देखना दिलचस्प होगा कि किसका भोज कारगर साबित हुआ और कौन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

# अधिकारियों की कमी से जूझ रहा आयकर विभाग

**भारत में आयकरदाताओं की संख्या चार करोड़ से कम है, जो कुल आबादी का चार प्रतिशत भी नहीं है. इनमें भी तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या नौकरीपेशा लोगों की है, जिनकी आयकर कटौती वेतन स्रोत से अनिवार्य रूप से की जाती है. देश में सेवा क्षेत्र और स्वयं का कारोबार करने वाला एक ऐसा बड़ा वर्ग है, जो आयकर के दायरे से दूर है.**

चौथी दुनिया ब्यूरो

पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे आयकर विभाग के कंधे पर काला धन अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) क़ानून, 2015 का बोझ आ गया है. विभाग में वरिष्ठ अधिकारी न के बराबर हैं. इस क़ानून के लागू होने से पहले आयकर विभाग किसी तरह अपना काम चला रहा था. ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि वह किस तरह इस चुनौती का सामना करता है. इस क़ानून को लागू करने के संबंध में भी कई सवाल खड़े हुए थे. दरअसल, नियम जितने सख्त होते हैं, छेड़छाड़ की आशंकाएं भी उतनी अधिक होती हैं. काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए इस क़ानून को लागू करने के लिए अधिक और सक्षम कार्यबल की आवश्यकता है. आयकर विभाग का कहना है कि इस क़ानून को लागू करने की ज़िम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी और मुख्य रूप से संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को इस काम में लगाया जाएगा, ताकि जांच के दौरान आवश्यक एवं ठोस निर्णय लिए जा सकें.

जानकारी के अनुसार, देश भर में मुख्य आयुक्त के 60 से ज़्यादा पद रिक्त हैं. यही नहीं, संयुक्त आयुक्त के कुल 1,500 स्वीकृत पदों में से 80 फ़ीसद पद रिक्त हैं. ऐसे में नया क़ानून लागू करने के लिए विभाग आवश्यक कार्यबल कहां से लाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि 1982 बैच के आईआरएस अधिकारियों की प्रोन्नति के आदेश जारी न होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई. देश भर में मुख्य आयुक्तों के रिक्त पदों की संख्या देखते हुए अब 1983 बैच के अधिकारियों की प्रोन्नति की संभावनाएं बढ़ गई हैं. आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त स्तर पर भी अधिकारियों की कमी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है. मौजूदा स्थितियों में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने में तीन-चार महीने का समय लग सकता है.

मोदी सरकार ने गठन के बाद कालेधन के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है, लेकिन जिस महकमे को कालेधन पर रोक लगाने के लिए बने नए क़ानून को लागू करना है, उस महकमे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए. उदारहण के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या और प्रमोशन को ही लें, सरकार को अधिकारियों कमी के बारे में पूरी जानकारी है बावजूद इसके अधिकारियों के प्रमोशन लंबे समय से अधर में लटके हैं. काला धन क़ानून के तहत जांच प्रक्रिया को आयकर क़ानून की तुलना में तेज करना होगा. इसके लिए निश्चित तौर पर ज्यादा कार्यबल की आवश्यकता होगी. एक आकलन के मुताबिक आयकर विभाग में वर्तमान में अधिकारियों के जितने पद स्वीकृत हैं वे भी जरूरत के हिसाब से कम हैं.

गौरतलब है कि इस साल टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीखों में कई बार बढ़ोत्तरी की जा चुकी है, सीधे तौर पर इसका प्रमुख कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी है. लोगों की बढ़ती आमदनी के बावजूद देश में आयकर चुकाने वालों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है. हालांकि टैक्स जमा करने वालों की संख्या में हर वर्ष इज़ाफा हो रहा है. ऐसे में सरकार को आयकर महकमे को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. यदि ऐसा नहीं होगा तो सुशासन का दावा करने वाली मोदी सरकार कई मोर्चों पर असफल साबित होगी. क्योंकि देश की योजनायें टैक्स कलेक्शन पर ही टिकी हैं, यदि यह काम प्रभावशाली तरीके से नहीं होगा तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की योजनाओं पर पड़ेगा.

भारत में आयकरदाताओं की संख्या चार करोड़ से कम है, जो कुल आबादी का चार प्रतिशत भी नहीं है. इनमें भी तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या नौकरीपेशा लोगों की है, जिनकी आयकर कटौती वेतन स्रोत से अनिवार्य रूप से की जाती है. देश में सेवा क्षेत्र और स्वयं का कारोबार करने वाला एक ऐसा बड़ा वर्ग है, जो आयकर के दायरे से दूर है. ऊंची विकास दर के साथ शहरीकरण की ऊंची वृद्धि दर के कारण देश में मध्यवर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि इस समय मध्यवर्ग के 17 करोड़ लोग पूरे देश में 46 फीसदी क्रेडिट कार्ड, 49 फीसदी कार, 52 फीसदी एसी तथा 53 फीसदी कंप्यूटर के मालिक हैं, पर इनमें से बड़ी संख्या में लोग आयकर नहीं देते. विभिन्न श्रेणी के दुकानदार अच्छी आय होते हुए भी आयकर देने से बचते हैं, आयकर देने को वे अपना कर्तव्य नहीं मानते. विभिन्न प्रकार के दुकानदारों, उद्यमियों और सेवा प्रदाताओं में से नए आयकरदाता खोजकर कर आधार बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आयकर के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए आयकर विभाग ने एक नया अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत उसने मौजूदा वित्तवर्ष में एक करोड़ नए लोगों से कर वसूलने के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य तय किया गए हैं. मसलन, अलग अलग राज्यों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. अच्छी आय होने के बावजूद आयकर का भुगतान न करने वाले लोगों की पहचान करने से लेकर उनसे जुर्माना वसूलने तक का काम वर्तमान में उपलब्ध कार्यबल के भरोसे नहीं किया जा सकता और न ही देश से कालेधन को बाहर जाने से रोका जा सकता है. इसलिए सरकार को वरीयता के आधार पर आयकर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को अविलंब पूरा करना चाहिए.

केवल आयकर विभाग ही ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कर्मचारियों की कमी है. सीबीआई की हाल भी कुछ ऐसी ही है. ये दोनों विभाग देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, यदि इस तरह के प्रमुख विभाग कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से जूझेंगे तो मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के वादे खोखले साबित होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

वाटर प्योरिफायर एक बेहतर विकल्प है, जिसकी पहल नवलगढ़ में मोरारका फाउंडेशन ने की है. शादियों एवं अन्य समारोहों में आजकल प्योरिफाइड पेयजल का चलन तेजी से बढ़ रहा है. गांवों में ऐसा पानी मंगाना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी सप्लाई सुदूर कस्बों से होती है. इसलिए हर गांव का अपना कियोस्क होना फ़ायदे का सौदा साबित होगा. कस्बों एवं शहरों में ऐसे कियोस्क लगाना और घरों में पानी की सप्लाई का काम आज व्यवसाय का रूप ले चुका है. स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक का हक़ है. मोरारका फाउंडेशन की यह योजना ग्रामीण अंचलों में पेयजल के प्रति जागरूकता पैदा करेगी.

# राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास का खुला खत

# शर्म से मेरा सिर झुक गया

22 अक्टूबर, 2015–विजया दशमी

**माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री,**

मैं भारी मन से यह खुला खत ऐसे समय में आपको लिख रहा हूं, जब हमारे प्यारे देश एवं लोगों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारी साझी विरासत के समक्ष ख़तरा उत्पन्न हो गया है. आज़ादी के तुरंत बाद ही 15 साल की उम्र में मैंने भारत के सशस्त्र बल में अपनी सेवाएं देना शुरू किया और भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में (1990 से 1993 तक) काम करता रहा. इस दौरान भारत में कई बदलाव देखने को मिले, जिनका मैं गवाह रहा हूं. ये बदलाव आज़ादी के समय के भयानक दंगों से लेकर आज की डिजिटल कनेक्टिविटी की बिल्कुल अलग दुनिया से जुड़े हुए हैं.

मैं यह खत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी लिख रहा हूं, जो हिंदू धर्म के विश्वासों के साथ पला–बढ़ा है. हालांकि, जिस हिंदू धर्म को मैंने जाना और अनुभव किया, वह कोमल, समावेशी और असाधारण विविधता से भरा हुआ था. मेरे धर्म ने मुझे सभी प्राणियों के लिए प्यार और सम्मान जैसे मूल्य सिखाए. मेरा हिंदू धर्म कभी भी इस तरह की हिंसा और असहनशीलता से कभी नहीं भरा था, जैसा कि आज हिंदुत्व ब्रांड के लोग देश भर में विभाजन और भय की लपटों को हवा दे रहे हैं. जिस तरह से हमारे देशवासियों, खासकर अल्पसंख्यकों एवं दलितों पर हमले हुए हैं, उससे आज उम्र के 80वें पड़ाव पर मेरा सिर शर्म से झुकने पर मजबूर हो गया है. हमारा सशस्त्र बल, जिसकी 45 सालों तक सेवा करने का गौरव मुझे हासिल है, वह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार की जीती–जागती मिसाल है. चाहे विमान हो या पनडुब्बी या फिर लड़ाई का मैदान, हम जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते. हम साथ प्रशिक्षण लेते हैं, खाना खाते हैं, लड़ते हैं और मरते हैं.

एडमिरल एल. रामदास (रिटायर्ड)

आख़िर क्यों मई 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश भर में अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि हुई है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ समुदायों पर विशेष ध्यान देने के लिए हो रहा है. आज मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है और बार–बार उनके खाने, उनके पूजा स्थलों, उनकी बुनियादी स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं. एकतरफ़ा भीड़ के व्यवहार से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उकसाए जाने की घटनाएं हो रही हैं. दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से बहुसंख्यकवादी सिंगल प्वाइंट एजेंडा यानी भारत में हिंदू राष्ट्र एजेंडा लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है और यह सब आरएसएस एवं उसके नेटवर्क ग्रुप के नेतृत्व में हो रहा है, जिससे अस्थिरता का माहौल बन रहा है. भीड़ के व्यवहार का एक ख़तरनाक पैटर्न सामने आया है, जिसमें वह सिर्फ़ अफ़वाहों के आधार पर लोगों को मार देती है. यह क़ानून के शासन के ठीक उलट है. जिन लोगों पर क़ानून लागू करने–कराने की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कई मामलों में ज़बरदस्त पक्षपातपूर्ण प्रवृत्तियों और व्यवहार का प्रदर्शन किया है.

सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश में शीर्ष पर बैठे लोगों की तरफ़ से ऐसे कार्यों एवं व्यवहार की कोई स्पष्ट निंदा नहीं की गई. अफ़सोस की बात है कि हर बार सरकार की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है, रटी–रटाई होती है, जो निश्चित रूप से उदासीनता प्रदर्शित करती है. सरकार में बैठे लोगों की प्रतिक्रिया ऐसे गंभीर एवं ख़तरनाक आरोपों को सिर्फ़ दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण बताकर पल्ला झाड़ लेती है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि समाज इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा. सांसद, कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री ऐसी टिप्पणियों में आगे हैं. इससे यह विश्वास बढ़ता है कि सत्तारूढ़ पार्टी एवं उसके सहयोगी संगठन क़ानून और शालीनता के सभी मानदंडों की अवमानना करते हुए किसी योजना के लिए काम कर रहे हैं.

मैं आज देश के शीर्ष नेतृत्व को यह बताने की ज़रूरत नहीं समझता कि यह एक ऐसे राष्ट्र में आग के साथ खेलने जैसा है, जहां अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम, ईसाई, दलित एवं आदिवासी पहले से खुद को हाशिये पर मान रहे हैं और भेदभाव का शिकार महसूस कर रहे हैं. इस विविधता को अपनी ताकत मानने के बजाय आज हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संकीर्ण, असहिष्णु, नस्लवादी एवं फासीवादी माने जा रहे हैं. कमज़ोर वर्गों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा से भारत की छवि ऐसी बनी है कि यहां असहमति के सभी स्वरों को हतोत्साहित किया जा रहा है और मानवाधिकारों का हनन हो रहा है. प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रियों को भारत के राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है और उनसे भारतीय संविधान को बनाए रखने का वचन लिया है. इन घटनाओं से उनके द्वारा अपनी शपथ पूरी करने में विफलता दिखती है. यह एक गंभीर मामला है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

केंद्र एवं राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं की स्पष्ट निंदा करनी चाहिए, तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दोषी दंडित हों और पीड़ितों को न्याय मिले. यह क़दम उन सभी लोगों के लिए एक कठोर संदेश होगा, जो ऐसी बयानबाजी या ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जो हमारे पारंपरिक लोकाचार और समन्वयवादी संस्कृति के ख़िलाफ़ है. भारत लगातार बदलती और गतिशील प्रक्रिया के तहत पिछले 5,000 वर्षों के दौरान विकसित लोगों एवं संस्कृतियों का एक अनूठा मिश्रण है. यह विविधता, हमारे समाज एवं लोगों की अद्वितीय प्रकृति शायद इस धरती पर कहीं भी दोहराई नहीं जा सकती है. एकल धार्मिक पहचान या एकल सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस प्राचीन सभ्यता एवं विरासत के लिए अपमान की बात है.

माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, आप दोनों ने ही संविधान में उल्लेखित नागरिक अधिकारों, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूजा करने के अधिकार के सम्मान की शपथ ली है. एक पूर्व सैनिक एवं आपकी तरह एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में मैंने भी देश का संविधान मानने और उसका मान रखने का वादा किया है. यह इस देश की निर्वाचित सरकार का परम कर्तव्य है कि वह संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बातों, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान करे. सुप्रीम कमांडर और मुख्य कार्यकारी के रूप में आपको स्वयं में निहित उस शक्ति, जो भारत के लोगों द्वारा दी गई है, के ज़रिये यह सब सुनिश्चित और क्रियान्वित करना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बहुत देर हो जाएगी. वास्तव में हम भारत के लोग आपकी ओर देख रहे हैं कि आप लोकतंत्र में विश्वास की बहाली के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाएं और हर नागरिक के लिए गरिमा, भ्रातृत्व एवं समानता लाने का वादा पूरा करें.

*एडमिरल एल. रामदास (रिटायर्ड)*
**पूर्व नौसेना प्रमुख**

## वाटर एटीएम

# स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मुहिम

**पानी के मामले में ग़रीब कहा जाने वाला राजस्थान भारत के सबसे सूखे राज्यों में से एक है, जहां सालाना 100 मिमी से भी कम वर्षा होती है. थार रेगिस्तान की इस भूमि पर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. पानी की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह सवाल स्थानीय लोगों को काफी समय से मथ रहा था, जिसका समाधान खोजा है मोरारका फाउंडेशन ने, जो राजस्थान के नवलगढ़ में किसानों, ग्रामीणों, ग़रीबों एवं पिछड़े परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है.**

**तरुण फोर**

जल मनुष्य की बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, लेकिन दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं. कहा जाता है कि वर्ष 2025 के बाद विश्व की 50 फ़ीसद आबादी को भयंकर जल संकट झेलना पड़ेगा. यह भी कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा. हमारे देश में शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों में पानी के लिए विवाद की ख़बरें आए दिन सुनने–पढ़ने को मिलती हैं. सवाल यह है कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में जल स्रोत कितने बढ़ रहे हैं? वे नष्ट और लुप्त तो नहीं हो रहे? तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इमारतों के जंगल खड़े हो रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक स्रोतों का लगातार दोहन जारी है. नतीजतन, स्रोत सीमित होते जा रहे हैं.

पानी के मामले में ग़रीब कहा जाने वाला राजस्थान भारत के सबसे सूखे राज्यों में से एक है, जहां सालाना 100 मिमी से भी कम वर्षा होती है. थार रेगिस्तान की इस भूमि पर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. पानी की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह सवाल स्थानीय लोगों को काफी समय से मथ रहा था, जिसका समाधान खोजा है मोरारका फाउंडेशन ने, जो राजस्थान के नवलगढ़ में किसानों, ग्रामीणों, ग़रीबों एवं पिछड़े परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है. मोरारका फाउंडेशन ने स्वयं सहायता समूह, रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, सौर ऊर्जा, कम्युनिटी गैस कनेक्शन एवं बंधेज आदि हस्तकलाओं के विकास सरीखे प्रोजेक्ट पर कार्य करके ज़रूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता हासिल की है. नई–नई परियोजनाएं लाकर, नए–नए रोज़गारों का सृजन करके फाउंडेशन ने लोगों का जीवन खुशहाल बनाया.

**मोरारका फाउंडेशन की तरफ़ से सबसे पहले प्रमोद पटवारी की दुकान के सामने वाटर एटीएम लगाया गया. लोग कार्ड लेकर वाटर एटीएम के पास जाते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी निकाल लेते हैं. अधिकांश ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्तर पर पेयजल की सुविधा नहीं है. लोग आज भी कुओं से पानी लेकर उसका भंडारण करते हैं.**

फाउंडेशन अब नवलगढ़ में प्योरिफाइड वाटर कियोस्क (पीने का शुद्ध पानी) योजना के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ–साथ इसे रोज़गार का माध्यम बनाने की पहल कर रहा है. अभी तक एटीएम का मतलब आप ऑल टाइम मनी जानते होंगे. एटीएम आपको लाइन में खड़े होकर बैंक से पैसे निकालने की टेंशन से मुक्त रखता है. कहीं भी, कभी भी एक छोटे–से कार्ड में पैसे लेकर घूम सकने की आज़ादी आजकल हर किसी को पसंद है, पर अभी तक आपने एटीएम से पैसे की जगह पानी निकलना शायद नहीं देखा होगा. नवलगढ़ में मोरारका फाउंडेशन ने वाटर एटीएम के रूप में एक नई योजना शुरू की है, जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके. वाटर एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड जारी किया जाता है, जिसे समय–समय पर रिचार्ज कराना पड़ता है. वाटर एटीएम से एक लीटर पानी दो रुपये में, पांच लीटर पानी 10 रुपये में, 15 लीटर पानी 20 रुपये में और 20 लीटर पानी 25 रुपये में बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है. जैसे ही आप अपना कार्ड मशीन में लगाएंगे, पानी की मात्रा लिखेंगे, पैसे अपने आप कट जाएंगे और पानी आपके बर्तन में आने लगेगा. वाटर एटीएम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है.

मोरारका फाउंडेशन की तरफ़ से सबसे पहले प्रमोद पटवारी की दुकान के सामने वाटर एटीएम लगाया गया. लोग कार्ड लेकर वाटर एटीएम के पास जाते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी निकाल लेते हैं. अधिकांश ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्तर पर पेयजल की सुविधा नहीं है. लोग आज भी कुओं से पानी लेकर उसका भंडारण करते हैं. जहां सरकार की ओर से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, वहां लोग घर की टंकियों में उसका भंडारण करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. कुओं का पानी प्राकृतिक तो है, पर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते उसमें जो प्राकृतिक तत्व कम या ज़्यादा हो रहे हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाता. सरकारी पेयजल में क्लोरीन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है, साथ ही लापरवाही के चलते वह पीने योग्य नहीं रह जाता.

ऐसे में वाटर प्योरिफायर एक बेहतर विकल्प है, जिसकी पहल नवलगढ़ में मोरारका फाउंडेशन ने की है. शादियों एवं अन्य समारोहों में आजकल प्योरिफाइड पेयजल का चलन तेजी से बढ़ रहा है. गांवों में ऐसा पानी मंगाना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी सप्लाई सुदूर कस्बों से होती है. इसलिए हर गांव का अपना कियोस्क होना फ़ायदे का सौदा साबित होगा. कस्बों एवं शहरों में ऐसे कियोस्क लगाना और घरों में पानी की सप्लाई का काम आज व्यवसाय का रूप ले चुका है. स्वच्छ पेयजल प्रत्येक नागरिक का हक़ है. मोरारका फाउंडेशन की यह योजना ग्रामीण अंचलों में पेयजल के प्रति जागरूकता पैदा करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोराका

सुप्रीम कोर्ट को ज्यूडिशियल स्टेट्समैनशिप का प्रदर्शन करना चाहिए. उसे यह कहना चाहिए था कि कम से कम एक ज्यूडिशियल मेंबर भी उस कमेटी में रहे. मौजूदा व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं है. दुनिया के किसी भी हिस्से में जजों को जज नियुक्त नहीं करते. न तो अमेरिका में, न तो ब्रिटेन में और न यूरोप में, जहां से हमने अपना संविधान लिया है. जज, जज की नियुक्ति बिल्कुल नहीं करते. मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी को इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए.

# न्यायिक व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास हों

संसद द्वारा पारित नेशनल ज्यूडिशियल अप्वायंटमेंट कमीशन एक्ट को अमान्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले को अलग-अलग हलकों में न्यायपालिका की आज़ादी के पक्ष में बताया जा रहा है और उसकी तारीफ़ की जा रही है. लेकिन, यह सही नहीं है. 26 जनवरी, 1950 को संविधान अपनाते समय संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई थी. इस संविधान में न्यायपालिका की आज़ादी के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे गए. एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की बहाली हो गई, तो उसे उस समय तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक संसद के दोनों सदनों से उसके ख़िलाफ़ दो तिहाई बहुमत से महाभियोग पारित नहीं हो जाता. इतनी अधिक सुरक्षा या कहें एहतियात न्यायपालिका की आज़ादी के लिए पर्याप्त है कि जजों को सरकार आसानी से नहीं हटा सकती. एक बेंच के सभी जज अपना-अपना फ़ैसला देने के लिए स्वतंत्र होते हैं. यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जजों से यह नहीं कह सकते कि आपको अमुक विचार रखना है या इस तरह का फ़ैसला देना है. हर मुक़दमा एक बेंच द्वारा सुना जाता है और उसका फ़ैसला आख़िरी होता है. अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी फ़ैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो सरकार जजों के फ़ैसलों को कैसे प्रभावित कर सकती है. जहां तक न्यायपालिका की आज़ादी का सवाल है, तो इतनी संवैधानिक सुरक्षा काफी है. सवाल यह उठता है कि जजों की नियुक्ति कैसे हो? संविधान की धारा 124 इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है और उसकी व्याख्या करने में कोई भी उलझाव नहीं है. उसके मुताबिक, एक जज की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी. बीच में एक ऐसा समय आया, जब इस सलाह की प्रक्रिया को कार्यपालिका ने महज औपचारिकता भर बना दिया. सलाह-मशविरे के बाद सरकार की जो मर्जी होती थी, वही होता था.

1995 में जस्टिस जेएस वर्मा ने एक मामले में फ़ैसला दिया कि जज के नाम का निर्णय चीफ जस्टिस और दो या तीन वरिष्ठ जजों को मिलाकर बनाए गए कॉलेजियम द्वारा होगा. इसके लिए वास्तव में संविधान में संशोधन की ज़रूरत थी. यह संविधान की सही व्याख्या नहीं थी. लेकिन जैसा कि कहा गया है कि संविधान की व्याख्या में किसी भी तरह का उलझाव होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ही अंतिम और मान्य होगी, उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जस्टिस वर्मा ने यह व्यवस्था (कॉलेजियम) बनाई और जो ये लोग कहें, उसे सरकार को स्वीकार करना है, राष्ट्रपति को उसे नियुक्त करना है. अब संविधान की यह व्याख्या किसी भी तार्किक व्यक्ति के लिए अतार्किक ही है. न्यायपालिका को आज़ाद होना चाहिए, इसे लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता. कार्यपालिका से लेकर आम आदमी और मीडिया तक इस बात को मानता है. सब इस बात से सहमत हैं कि न्यायपालिका को आज़ाद होना चाहिए. मुश्किल तब आती है, जब इस काम के

लिए सबसे बेहतर का चुनाव करना हो, उसे कैसे चुना जाए? मैं मानता हूं कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, वह काफी है. सरकार कुछ नामों को चीफ जस्टिस के पास सलाह के लिए भेजे और अगर चीफ जस्टिस को कोई आपत्ति न हो, तो उन व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाए. तब आप समवर्ती सूची की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से वह भी अच्छा है. उसमें क़ानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस मिलकर फ़ैसला ले सकते हैं. लेकिन, अभी जो फ़ैसला आया है, वह न तो न्यायपालिका को और न न्याय प्रक्रिया को कोई श्रेय देता है. अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बहुत सारे अयोग्य या ग़लत या कम योग्यता वाले जजों की नियुक्तियां हुई हैं. जैसा कि सरकार ने बिल्कुल सही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सम्मान किया जाएगा, लेकिन बहस जारी रखनी चाहिए.

मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ज्यूडिशियल स्टेट्समैनशिप का प्रदर्शन करना चाहिए. उसे यह कहना चाहिए था कि कम से कम एक ज्यूडिशियल मेंबर भी उस कमेटी में रहे. मौजूदा व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं है. दुनिया के किसी भी हिस्से में जजों को जज नियुक्त नहीं करते. न तो अमेरिका में, न तो ब्रिटेन में और न यूरोप में, जहां से हमने अपना संविधान लिया है. जज, जज की नियुक्ति बिल्कुल नहीं करते. मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी को इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए. इस मुद्दे का परीक्षण होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति का सबसे बेहतर तरीका कौन-सा होगा? देश सबके लिए है, सबको एक बेहतर न्याय व्यवस्था चाहिए. दरअसल, अनगिनत न्यायिक सुधारों की ज़रूरत है, जिन्हें किया जाना बाकी है. मिसाल के तौर पर जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते. वे ऐसे काम करके पैसा बना रहे हैं, जिन्हें करना निषिद्ध है. जो काम वे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वे काम उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? वे अपनी राय देकर पैसा कैसे कमा सकते हैं? इस तरह की प्रथा ख़त्म करने के लिए हमें अमेरिकी प्रथा देखनी चाहिए. वहां एक बार जो जज बन जाता है, वह पूरी ज़िंदगी के लिए जज रहता है. उसे रिटायरमेंट की चिंता नहीं रहती है. भारत में भी एक ऐसा सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिसमें जज के रिटायर होने के बाद भी उसे पूरा वेतन और भत्ता मिले, ताकि उसे और कोई काम करने की ज़रूरत न पड़े.

आप एक ऐसा तरीका निकाल सकते हैं, जिसमें एक जज को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके. लेकिन, हम जो बात कर रहे हैं, वह बहुत छोटी चीज है और वह है, जजों की नियुक्ति का तरीका. अख़बारों में जो भी आलेख आ रहे हैं, उनमें न्यायिक स्वतंत्रता की बात आ रही है और इस अधिनियम को समाप्त करने वाले फ़ैसले की तारीफ़ की जा रही है, जो ठीक नहीं है. इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि न्याय मिलने में होने वाली देरी कैसे ख़त्म की जाए और त्वरित न्याय मिले. बेवजह की पीआईएल से कैसे छुटकारा मिले. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर विचार होना चाहिए. जहां तक जजों की नियुक्ति का सवाल है, तो जजों द्वारा जजों की नियुक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है. भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र को एक बेहतर सिस्टम कैसे मिले, इसके लिए काम होना चाहिए. आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में प्रयास करेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

# जब तोप मुक़ाबिल हो

# प्रधानमंत्री जी, वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता

**प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है, कम से कम भारत का विपक्ष तो चुनौती नहीं है. तो फिर चुनौती उनके सामने अपना समय है, अपनी सोच है, उनका अपना मंत्रिमंडल है, उनके अपने वे साथी हैं, जिनसे वह सलाह-मशविरा करते हैं और देश के भविष्य पर निगाह रखने वाले वे ईमानदार विशेषज्ञ, जिन्हें वह तलाश नहीं पा रहे. चुनावों की चिंता छोड़कर उन्हें देश की चिंता करनी चाहिए और चुनावों का ज़िम्मा पार्टी की राज्य इकाइयों और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ देना चाहिए कि वे चुनावों की क्या रणनीति बनाते हैं, क्या भाषा बोलते हैं.**

चलिए चुनाव ख़त्म हो गया. चुनाव की अदावत, चुनाव की भाषा और चुनाव में लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप सामान्य लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेंगे. लेकिन, राजनेता यह सब भूल जाएंगे और वे यह भी भूल जाएंगे कि उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके कितने लोगों के मन में अच्छी राजनीति की संभावनाओं की आशा समाप्त की है. इन परिणामों की वजह से बिना मन को परेशान किए सभी को अपने-अपने काम पर लौटना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं. उनकी सरकार विश्व बैंक में भारत की रैंकिंग में सुधार का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन विश्व बैंक की रैंकिंग का आधार भारतीय उद्योग या पूंजी बाज़ार में पूंजी के बैलेंस पर टिका होता है, उसका कोई रिश्ता भारतीय जनता के जनजीवन से नहीं होता. वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता की क्रय शक्ति कम हो रही है और आमदनी घट रही है. नौकरियां हैं नहीं और हमारा निर्यात कम हो रहा है. नतीजतन, भारत में न तो सामान्य आदमी खुश है और न वे खुश हैं, जिनके पास पैसा है. मुझसे ऐसे लोग कई बार टकराते हैं, जिनका बड़ा या छोटा व्यापार है. वे कहते हैं कि उनके पास पूंजी समाप्त हो रही है. पूंजी समाप्त होने का एक ही कारण वे बताते हैं कि बाज़ार अनियंत्रित, बेलगाम और अराजक स्थिति में पहुंच रहा है. कौन दिशा निर्धारित कर रहा है, कौन दिशा भटका रहा है, यह सब नज़रों से ओझल हो गया है.

मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े बिजनेस न्यूज चैनल द्वारा आयोजित मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में गया था. वहां जितने लोग थे, वे सब उपस्थित मंत्रियों को खुश करने वाले सवाल पूछ रहे थे. मेरे सवाल के जवाब में मंत्री थोड़ा सकपकाए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन, उसके बाद के छोटे-से ब्रेक में ज़्यादातर कंपनियों के मालिक या उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बधाई दी. उन्होंने कहा कि आप ही ने सही सवाल पूछा है, हम तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मंत्री सामने हैं. हमारे ख़िलाफ़ बदले की कार्यवाही हो सकती है. एक बिजनेस न्यूज चैनल के कार्यक्रम में देश के बड़े आर्थिक संगठनों के नेता शामिल थे. उनमें से एक ने बहुत साफ़गोई से कहा कि विकास का एजेंडा कहीं भटक गया है. हम छोटे-छोटे सेरेमोनियल फंक्शन को विकास का मुखौटा पहना रहे हैं. हालांकि, अपनी दूसरी टिप्पणी में वह थोड़े सावधान हो गए और उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, विकास का एजेंडा तो इस सरकार का मुख्य एजेंडा है. पर ये स्थितियां बताती हैं कि इस देश में कोई खुश नहीं है. सवाल यह उठता है कि लोगों को खुश करने की ज़िम्मेदारी आख़िर किसकी है?

देश के मशहूर लेखक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी जब यह कहते हैं कि इस सरकार में कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, तो वह कुछ हद तक सही कहते हैं, बल्कि बड़ी हद तक सही कहते हैं. मैं यह मानता हूं. आप विशेषज्ञों को संपूर्ण अधिकार मत सौंपिए, लेकिन देश के विशेषज्ञों को बुलाएं, जो विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करें और सुझाए भी कि देश को इस स्थिति से निकालने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए. हालांकि

**आज हालत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की कोई दिशा ही नहीं है. दिशा का एक संकेत बजट से मिलता है और बजट यह बताता है कि उसमें 70 प्रतिशत भारत शामिल नहीं है. यह कहा जा सकता है कि अभी तो दो साल पूरे होने वाले हैं और हम अगले दो सालों में खेती का, किसानों का, ग्रामीण भारत का ध्यान रखेंगे, लेकिन तब तक शहरों पर आधारित अर्थव्यवस्था लुढ़कने लगेगी. इसलिए देश के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कड़े फ़ैसले करना चाहते हैं, तो उन्हें वे कड़े फ़ैसले पूंजी बाज़ार को ध्यान में रखते हुए देश के सामान्य लोगों के पक्ष में करने चाहिए.**

यह मुश्किल है, लेकिन देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि विभिन्न पहलुओं पर राय रखने वाले विभिन्न विशेषज्ञों को एकत्र किया जाए और उनके साथ गंभीरतापूर्वक चर्चा करके देश के विकास की दिशा तय की जाए. राजनीति अपनी भाषा बोलती रहेगी, आलोचनाएं-प्रति आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन सरकार कम से कम कोई दिशा तो देखे और उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू करे. आज हालत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था की कोई दिशा ही नहीं है. दिशा का एक संकेत बजट से मिलता है और बजट यह बताता है कि उसमें 70 प्रतिशत भारत शामिल नहीं है. यह कहा जा सकता है कि अभी तो दो साल पूरे होने वाले हैं और हम अगले दो सालों में खेती का, किसानों का, ग्रामीण भारत का ध्यान रखेंगे, लेकिन तब तक शहरों पर आधारित अर्थव्यवस्था लुढ़कने लगेगी. इसलिए देश के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कड़े फ़ैसले करना चाहते हैं, तो उन्हें वे कड़े फ़ैसले पूंजी बाज़ार को ध्यान में रखते हुए देश के सामान्य लोगों के पक्ष में करने चाहिए. लेकिन, क्या उनके पास कड़े फ़ैसले लेने के लिए वक़्त है? प्रधानमंत्री को हम जैसे साधारण लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, पर सुझाव देना ज़रूर चाहते हैं. आप अगर आज नहीं सोचेंगे, तो फिर आपका वह वाक्य मज़ाक लगने लगेगा कि देश ने 60 साल कांग्रेस को दिए, तो 15 साल हमें क्यों नहीं दे सकता? प्रधानमंत्री जी, देश नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले 60 सालों में जो प्रगति नहीं हुई, वह पिछले 10 सालों में नहीं हुई, वह अब हो रही है. सारे लोग सूचनाओं से भरे हुए हैं और वे थोड़े समय के लिए दिमाग़ी तौर पर भटक सकते हैं, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं. ग़रीब, चाहे शहर में हो या गांव में, उसके सामने भविष्य अंधकारमय है और यह उसे डराता है. कोशिश कीजिए कि वह अपनी उस निराशा के गर्त में न डूबे, क्योंकि निराशा के गर्त में डूबने से व्यक्ति हिंसा की तरफ़ बढ़ता है और हिंसा देश के लिए ख़तरनाक होती है.

प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है, कम से कम भारत का विपक्ष तो चुनौती नहीं है. तो फिर चुनौती उनके सामने अपना समय है, अपनी सोच है, उनका अपना मंत्रिमंडल है, उनके अपने वे साथी हैं, जिनसे वह सलाह-मशविरा करते हैं और देश के भविष्य पर निगाह रखने वाले वे ईमानदार विशेषज्ञ, जिन्हें वह तलाश नहीं पा रहे. चुनावों की चिंता छोड़कर उन्हें देश की चिंता करनी चाहिए और चुनावों का ज़िम्मा पार्टी की राज्य इकाइयों और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ देना चाहिए कि वे चुनावों की क्या रणनीति बनाते हैं, क्या भाषा बोलते हैं. और, उनसे कह देना चाहिए कि चुनाव में गली-गली, गांव-गांव में सभा करने के लिए उन्हें न उलझाएं. अपना कुछ काम पार्टी और पार्टी के नेता भी करें. यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देश सचमुच प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा करता है कि वह देश को चौमुखी आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाएंगे. कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, वक़्त को ज़्यादा इंतज़ार मत कराएं. अभी वक़्त है, कल वक़्त नहीं होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

# खादी अब ग़रीबों को लूटने के लिए है

**इस आलेख में आप पाएंगे कि किस तरह मज़दूरों को शोषण से बचाने के लिए जन्मी खादी अब मज़दूरों का भरपूर शोषण कर रही है. पांच ज़िलों के खादी आश्रमों के क्षेत्रीय कार्यालय मगहर में खादी कार्यकर्ताओं का हाल जानने जब मैं गया, तो वहां की अमानवीय स्थितियों को देख स्तब्ध रह गया. खादी आश्रम के नाम पर मिला एक यंत्रणा शिविर, जहां ज़्यादातर कर्मचारियों की हालत बंधुआ मज़दूरों की तरह थी. जो न्याय मांगने की हिम्मत करते थे, उन्हें गोलियों का शिकार बनना पड़ता था.**

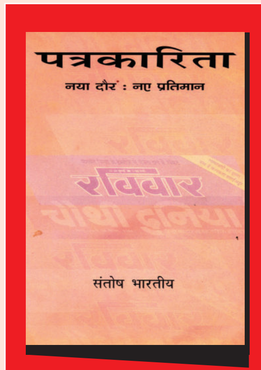


**आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.**

खादी का जन्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में हुआ था. 1920 में गांधी जी ने कहा था कि स्वराज का काम आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बीस लाख चरखे हों, कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य हों और एक करोड़ का तिलक स्वराज-कोष हो. गांधी जी के आह्वान पर बहुत जल्द एक करोड़ का तिलक स्वराज-कोष इकट्ठा हो गया तथा उसकी ज़्यादातर रकम खादी के काम में खर्च की गई. इस पूंजी से 1925 में चरखा संघ की स्थापना हुई तथा 1934 में खादी को ग्रामोद्योग से जोड़ने के लिए ग्रामोद्योग संघ बना. उन दिनों खादी आज़ादी की भावना का प्रतीक थी तथा इसका काम करने वाला सादगी से रहने में गर्व महसूस करता था. उत्तर प्रदेश में मेरठ खादी का पहला बड़ा केंद्र बना, बाद में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी केंद्र बने. संस्था का नाम रखा गया, श्री गांधी आश्रम. आज गांधी आश्रमों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जो हालत है, उसे देखकर यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि खादी कभी राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक थी. आज तो यह शोषण एवं ग़ुलामी का प्रतीक बन गई है और खादी के कार्यकर्ता गांधी के नाम का घृणित व्यापार कर रहे हैं. श्री गांधी आश्रम, मगहर की जो कथा हम यहां बयान करने जा रहे हैं, उसे खादी के पतन का एक दृष्टांत ही मानना चाहिए.

मगहर में खादी के काम की शुरुआत 1952 में हुई. देवरिया के राम निवास सिंह सीताराम यादव का मकान 45 रुपये महीना किराये पर लेकर यहां रहते थे. यही खादी आश्रम का प्रारंभिक कार्यालय था. कत्तिनों से सूत लेकर मगहर, कठतहरा और धौरेहरा में ठेके पर खादी बुनवाई जाती थी. एक धोती की बुनवाई ढाई रुपये दी जाती थी. जुलाहे के लिए यह दो दिन का काम था. गांधी आश्रम के व्यवस्थापक आठ आना रोज़ पर मज़दूरों की भर्ती करते थे. सूत की रंगाई इन्हीं दैनिक मज़दूरों से कराई जाती थी. 1954 में दीप नारायण उपाध्याय व्यवस्थापक बनकर आए तथा उन्होंने संस्था के लिए ज़मीन खरीदी. बाद में अकबरपुर से आए राम नाथ चौबे ने सन् 1955 में विचित्र नारायण शर्मा के हाथों गांधी आश्रम के मकान का शिलान्यास कराया. उन्हीं दिनों अंबर चरखे की योजना भी बनी. साथ ही रंगाई, छपाई, सरंजाम विभाग, सिलाई, तेलघानी, स्टोर एवं कुंदी विभाग भी खुले. कार्यकर्ताओं की भर्ती शुरू हुई. एक अनुमान के अनुसार, 1954-55 में स्टोर विभाग में 40, रंगाई विभाग में 15 तथा सरंजाम विभाग में छह लोग भर्ती किए गए. वेतन था एक रुपये रोज़. हर महीने दस रुपये या पांच रुपये जमानत के काट लिए जाते थे.

सन् 1956 में नंदलाल तिवारी ने आश्रम का मकान पूरा कराया तथा सन् 1957 में स्टोर इंचार्ज लक्ष्मी नारायण द्विवेदी ने और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की. पढ़े-लिखे कार्यकर्ताओं से सूत की खरीद-बिक्री और अनपढ़ों से रंगाई-धुलाई कराई जाती थी. शिक्षित कार्यकर्ताओं में से कुछ को तीस रुपये तथा कुछ को साढ़े सैंतीस रुपये महीना वेतन दिया जाता था. लेकिन, नियुक्ति-पत्र किसी को भी नहीं दिया गया. सन् 1957 से पहले कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को ही 12 रुपये वेतन मिलता था. उन्हें कुछ और भत्ते मिलाकर कुल 41 रुपये मिलते थे. बाकी कर्मचारियों की हालत तो और भी खराब थी. गांधी आश्रम में कार्यकर्ताओं की तीन श्रेणियां होती थीं- कार्यकर्ता, साधारण श्रमिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय साधारण कार्यकर्ता. स्थानीय साधारण कार्यकर्ता को व्यवस्थापकों ने नाम दिया था, नेट कार्यकर्ता. सन् 1959 में उनका वेतन तीस रुपये महीना था. कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता था. साधारण श्रमिक कार्यकर्ता कुछ सुविधाएं पाता था, पर नेट कार्यकर्ता की स्थिति तो बिल्कुल बंधुआ मज़दूर की-सी थी. यह सब सन् 1962 तक चला. सन् 1962 में मज़दूरों ने आश्रम के शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तब उन्हें 30 तथा 35 रुपये महीने पर नियुक्तियां दी गईं. यह पहला अवसर था, जब खादी आश्रम ने साधारण कार्यकर्ताओं के नाम बाकायदा नियुक्ति-पत्र जारी किए. ■

*जारी...*

feedback@chauthiduniya.com

# देश नए राजनीतिक बदलाव की ओर

**पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जो आम आदमी की समस्याओं के प्रति स्थानीय लोगों की चिंताएं ज़ाहिर करती हैं. यह हैरान करने वाली बात है और भ्रामक भी. क्या भारत एकदम से असहिष्णु हो गया है? क्या भारत को एक नई विचारधारा की ओर धकेला जा रहा है?**

मेघनाद देसाई

महान भारतीय इतिहासकार रंजीत गुहा सबाल्टर्न (अधीनस्थ) इतिहास लेखन की अग्रणी पंक्ति के इतिहासकारों में से एक हैं. सबाल्टर्न इतिहास वह इतिहास है, जिसका निर्माण आम लोग करते हैं, न कि संभ्रांत वर्ग, जहां नेता निर्णय लेता है कि पूर्व में क्या हुआ था. पिछले वर्ष जबसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, तबसे सबाल्टर्न राजनीति में जैसे उछाल आ गया है. पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हुईं, जो आम आदमी की समस्याओं के प्रति स्थानीय लोगों की चिंताएं ज़ाहिर करती हैं. यह हैरान करने वाली बात है और भ्रामक भी. दरअसल, एक राष्ट्र के साथ एक विचारधारा (नेहरूवादी) की धारणा को चुनौती मिली है. तो क्या भारत एकदम से असहिष्णु हो गया है? क्या भारत को एक नई विचारधारा की ओर धकेला जा रहा है? नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की विचारधारा बदल कर समावेशी विकास करना चाहते हैं. उन्होंने इसी नारे पर चुनाव जीता था. उनकी जीत न केवल भाजपा की मजबूती और कांग्रेस की कमज़ोरी उजागर करती है, बल्कि हिंदी माध्यम में प्रशिक्षित एक राजनीतिक समाज की रचना की ओर भी इशारा करती है.

अब सेंट स्टीफेन और ऑक्सफोर्ड की कुलीन भाषा का वर्चस्व नहीं रहा. इस बदलाव का पता विभिन्न सरकारी संस्थाओं (जैसे, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष) के पदों पर हुई नियुक्तियों से चलता है. इन पदों पर नियुक्त लोगों के नाम पुराने कुलीन बुद्धिजीवियों को नहीं मालूम थे, इसलिए ऐ अच्छे नहीं हो सकते. उन्होंने अपने विदेशी मित्रों से इसकी शिकायत शुरू कर दी, जबकि नए नेता ने अपना सबाल्टर्न एजेंडा प्रतिपादित करना शुरू कर दिया है. अब भारत एक डबल डेकर सवारी बन गया है. ऊपर वाले डेकर में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं सहकारी संघवाद आदि हैं, तो नीचे वाले डेकर में घर वापसी, लव जिहाद, गौ-रक्षा एवं मुस्लिम विरोध. इस तरह की सबाल्टर्न राजनीति लोकसभा चुनाव जीतने के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी. पिछले साल एक हद तक इसे दबाकर रखा गया था, लेकिन हालिया दिनों में शायद बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से यह एक बार फिर मुखर हो गई है. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का नियंत्रण संगठन के निचले क्रम पर नहीं है, इसलिए उस पर काबू पाने में वह उतना असरदार नहीं है. मामला केवल हिंदू-मुस्लिम तनाव का नहीं है, दलित विरोधी हिंसा में भी वृद्धि हो रही है. अभी हाल में हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में दो दलित बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया.

सबाल्टर्न राजनीति का दूसरा नमूना सिखों की मौजूदा जातीय लड़ाई है. अकाल तख़्त ने जिस तरह मामले को लिया, उससे वह और भी बिगड़ गया. इससे ज़ाहिर होता है कि नेता ज़मीनी कार्यकर्ताओं से कैसे अपना संपर्क खो रहे हैं या फिर उनका जुनून समझ नहीं पा रहे हैं. पंजाब सरकार स्थिति संभालने में नाकाम रही है. ज़ाहिर है, यह स्थिति पंजाब सरकार द्वारा नहीं पैदा की गई, लेकिन लोकतंत्र में सरकार हर घटना के लिए ज़िम्मेदार होती है. भारत में हालांकि बाहरी सतह पर विचारधारा सेकुलरिज्म की थी, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक कोई बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश नहीं की गई. इसलिए जातीय झगड़े एवं सांप्रदायिक तनाव सतह के नीचे बने रहे. जाति प्रथा की ग़ैर-बराबरी ख़त्म नहीं की गई, बल्कि मंडल आयोग के ज़रिये उसे प्रोत्साहित किया गया. सेकुलरिज्म अल्पसंख्यकों का रक्षा कवच बन गया. नई स्थितियों में उन पर हमले हो रहे हैं. लोकतंत्र में बहुत दिनों से दबे-कुचले और हाशिये पर छोड़े गए लोग सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं. वे न तो सेक्युलर हैं और न उदारवादी, बल्कि वे भारतीय हैं. उनकी भाषा हमेशा से अलग रही है. उनका मानना है कि वे सत्ता में हैं. देश और सभी भारतीयों के लिए उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा काम है. ■

**भारत में बाहरी सतह पर विचारधारा सेकुलरिज्म की थी, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक कोई बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश नहीं की गई. इसलिए जातीय झगड़े एवं सांप्रदायिक तनाव सतह के नीचे बने रहे. जाति प्रथा की ग़ैर-बराबरी ख़त्म नहीं की गई, बल्कि मंडल आयोग के ज़रिये उसे प्रोत्साहित किया गया.**

feedback@chauthiduniya.com

# जीवन का ज्ञान

अलसी और मुलेठी को समभाग लेकर कूट लें. 40-50 ग्राम चूर्ण को मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें 1 लीटर उबलता जल डालकर ढक लें. एक घंटे बाद छानकर, इसमें 25 से 30 ग्राम तक कलमी शोरा मिलाकर बोतल में रख लें. तीन घंटे के अंतर से 25 से 30 मिली तक इस का सेवन करने से 24 घंटे में ही पेशाब की जलन, पेशाब का रुक-रुक कर आना, पेशाब में खून आना, मवाद आदि बहना, सुरसुराहट होना आदि शिकायतें दूर हो जाती हैं.

# अलसी

**3 ग्राम अलसी बीजों को मोटा कूटकर 250 मिली उबलते हुए जल में भिगो दें और एक घंटा ढक कर रख दें. तत्पश्चात छानकर थोड़ी शक्कर मिलाकर सेवन करने से भी शुष्क कास व श्वास रोग की घबराहट दूर होती है, मूत्र साफ होता है.**

अलसी की खेती समस्त भारतवर्ष में बहुतायत में की जाती है. इसका तेल सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है.

### आयुर्वेदीय गुण–कर्म एवं प्रभाव

1 अलसी के बीच मधुर, मंद गंध–युक्त, स्निग्ध, उष्ण, चरपरे, गुरु, बलकारक, कामोद्दीपक, अल्प मात्रा में मूत्रकारक, शोथहर, अधिक मात्रा में रेचक, वातशामक तथा वातरक्त, कुष्ठ, व्रण, पृष्ठशूल, शुक्र, कफ व पित्त शामक होते हैं.

2 अलसी तेल–मधुर, पिच्छिल, वातशामक, मंदगंधि, कुछ कसैला बलकारक, भारी, गर्म, मलकारक, स्निग्ध, ग्राही, कफशामक, कासनाशक तथा त्वक– दोषहर है.

3 अलसी पत्र–कास, श्वास, कफ तथा वातशामक, इसके ताजे हरे पत्तों की शाक वातग्रस्त रोगियों के लिए विशेष लाभदायक है.

4 अलसी पुष्प–रक्त– पित्त शामक होता है.

### औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

**शिरो रोग:**

1. शिरोवेदना– अलसी के बीजों को शीतल जल में पीसकर लेप करने से, सूजन के कारण होने वाले सिर दर्द, माथे की पीड़ा तथा सिर के घावों का शमन होता है.

**नेत्र रोग:**

1. नेत्राभिष्यंद– अलसी के बीजों को पानी में फुलाने से बने लुआब से नेत्रों का आश्च्योतन (बूंद डालने) करने से नेत्राभिष्यंद (आंख आना) तथा आंखों की लालिमा में लाभ होता है.

**नासा रोग:**

1. प्रतिश्याय – अलसी के बीज का धूमपान जुकाम में हितकर है.

**कर्ण रोग:**

1. कर्णशोथ– अलसी को प्याज के रस में पकाकर, छानकर 1–2 बूंद कान में टपकाने से कान की सूजन मिटती है.

**कण्ठ रोग:**

1.गण्डमाला– समभाग अलसी, शमी सरसों, सहिजन बीज, जपा पुष्प तथा मूलीबीज को तक्र से पीसकर बनाए कल्क का गले की गांठों आदि पर लेप करने से शीघ्र लाभ होता है.

**वृक्ष रोग:**

1.श्वास कास– 5 ग्राम अलसी के बीजों को 50 मिली पानी में भिगोकर रखें और 12 घंटे बाद जल पी लें. प्रात:काल भिगोया हुआ सायंकाल और शाम को भिगोया हुआ सुबह को पी लें. इस जल के सेवन से दमा रोगी को बहुत शक्ति मिलती है. परन्तु पथ्य–अपथ्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए.

2. 5 ग्राम अलसी बीजों को कूट–छानकर जल में उबालें. इसमें 20 ग्राम मिश्री मिलाकर (यदि शीतकाल हो तो मिश्री के स्थान पर शहद मिलाएं) प्रात: सायं सेवन करने से भी कास–श्वास में लाभ होता है.

3. 3 ग्राम अलसी बीजों को मोटा कूटकर 250 मिली उबलते हुए जल में भिगो दें और एक घंटा ढक कर रख दें. तत्पश्चात छानकर थोड़ी शक्कर मिलाकर सेवन करने से भी शुष्क कास व श्वास रोग की घबराहट दूर होती है, मूत्र साफ होता है.

4. 25 ग्राम अलसी के बीजों को पीसकर रातभर ठंडे जल में भिगोकर रखें, प्रात:काल छानकर इस जल को कुछ गर्मकर, इसमें नींबू का रस मिलाकर, पिलाने से टी.बी. के रोगी को बहुत लाभ होता है.

5. अलसी के बीजों को भूनकर शहद के साथ चाटने से खांसी मिटती है.

6. महीन पिसी अलसी को साफ कर मंद आंच से तवे पर भून लें. जब अच्छी तरह भुन जाय, गंध आने लगे तब समभाग मिश्री मिला लें. जुकाम में 5–5 ग्राम तक उष्ण जल के साथ दोनों समय देने से आराम होता है. इस प्रयोग से खांसी में भी लाभ होता है.

7. **कास**–भुने बीज से बनाए 2–3 ग्राम चूर्ण में मधु या मिश्री मिलाकर प्रात: सायं सेवन करने से खांसी का शमन होता है.

8. अलसी के बीजों से बनाए हिम अथवा क्वाथ का प्रात: सायं सेवन श्वास–कास में हितकर है. शीतकाल में मधु तथा ग्रीष्म में मिश्री मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए.

9. 3 ग्राम अलसी चूर्ण को 250 मिली उष्ण (उबले हुए) जल में डालकर, 1 घंटे तक छोड़कर फिर थोड़ी शर्करा मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी तथा सांस फूलने में लाभ होता है.

10. **वातकफजविकार**– 50 ग्राम भुनी अलसी चूर्ण में समभाग मिश्री तथा चौथाई भाग मरिच मिलाकर, 3–5 ग्राम की मात्रा में प्रात: काल मधु के साथ सेवन करने से वातकफज विकारों में लाभ होता है.

**उदर रोग :**

1. **विबन्ध**–5–7 मिली अलसी तैल का सेवन करने से मल का निर्हरण होकर कब्ज तथा बवासीर में लाभ होता है.

**यकृत्प्लीहा रोग :**

1. **प्लीहा वृद्धि**–2–5 ग्राम भुने बीजों से बनाए चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से प्लीहा वृद्धि में लाभ होता है.

**वृक्कवस्ति रोग :**

1. **मूत्र–विकार** –50 ग्राम अलसी, 3 ग्राम मुलेठी, दोनों को दरदरा कूटकर 250 मिली जल के साथ मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर पकाएं. जब 50 मिली जल शेष रह जाए तो छानकर 2 ग्राम कलमी शोरा मिलाकर 2 घंटे के अंतर से 20–20 मिली की मात्रा में पिलाने से मूत्रकृच्छ्र (मूत्र–त्याग की कठिनता) में बहुत आराम मिलता है. अधिक मात्रा में बनाकर 10–15 दिन तक ले सकते हैं.

2. अलसी और मुलेठी को समभाग लेकर कूट लें. 40–50 ग्राम चूर्ण को मिट्टी के बर्तन में डालकर उसमें 1 लीटर उबलता जल डालकर ढक लें. एक घंटे बाद छानकर, इसमें 25 से 30 ग्राम तक कलमी शोरा मिलाकर बोतल में रख लें. तीन घंटे के अंतर से 25 से 30 मिली तक इसका सेवन करने से 24 घंटे में ही पेशाब की जलन, पेशाब का रुक–रुक कर आना, पेशाब में खून आना, मवाद आदि बहना, सुरसुराहट होना आदि शिकायतें दूर हो जाती हैं.

3. 10 ग्राम अलसी और 6 ग्राम मुलेठी, दोनों को खूब कुचल कर एक लीटर जल में मिलाएं, आधा भाग शेष रहने तक पकाएं. तीन घंटे के अंतर से लगभग 25 काढ़े में 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करने से जलन तत्काल दूर होकर मूत्र साफ होने लगता है.

4. प्रमेह–अलसी का तैल प्रमेह में उपयोगी है.

5. मूत्रदाह–10–12 ग्राम अलसी बीज चूर्ण में 5–6 ग्राम मिश्री मिलाकर 3–3 घंटे पर सेवन करने से मूत्र की जलन कम होती है.

**प्रजननसंस्थान रोग:**

1. सुजाक–अलसी तेल की 4–6 बूंदों को मूत्रेन्द्रिय के छिद्र में डालने से सूजाक में लाभ होता है.

2.वीर्य–पुष्टि– काली मिर्च और शहद के साथ अलसी का सेवन कामोद्दीपक तथा वीर्य को गाढ़ा करने वाला होता है.

**अस्थिसंधि रोग:**

1. संधिशूल– अलसी बीजों को ईसगोल के साथ पीसकर लगाने से जोड़ो के दर्द में लाभ होता है.

2. कटिशल– अलसी के तेल को गर्म कर इसमें शुंठी चूर्ण मिलाकर मालिश करने से कमर दर्द दूर होता है.

3. गठिया– अलसी के तेल की पुल्टिस को गठिया की सूजन पर लगाने से लाभ होता है.

4. वातरक्त– अलसी को दूध के साथ पीसकर लेप करने से वातप्रधान वातरक्त में वेदना का शमन होता है.

5.संधिवात– अलसी तैल अथवा अलसी एवं ईसबगोल के बीच कल्क का लेप करने से संधिगत–शूल एवं शोथ का शमन होता है.

**त्वचा रोग :**

1. फोड़ा– अलसी को जल में पीसकर उसमें थोड़ा जौ का सत्तू तथा खट्टी दही मिलाकर फोड़े पर लेप करने से फोड़ा पक जाता है.

2. वात प्रधान फोड़े में अगर जलन और वेदना हो तो तिल और अलसी को भूनकर गाय के दूध में उबालकर, ठंडा होने पर उसी दूध में उन्हें पीसकर फोड़े पर लेप करने से लाभ होता है.

3. अग्निदग्ध– शुद्ध अलसी तेल और चूने का निथरा हुआ जल दोनों को समभाग लेकर अच्छी प्रकार घोट लें. यह श्वेत मलहम जैसा हो जाता है. इसको आग से जले हुए स्थान पर लगाने से शीघ्र ही घाव की पीड़ा दूर हो जाती है.

**सर्वशरीर रोग:**

निद्रा–नाश– अलसी तथा एरंड तैल को समभाग मिलाकर कांसे की थाली में कांस्य पात्र से ही खूब घोंटकर आंख में सुरमे की तरह लगाने से नींद अच्छी आती है.

**प्रयोज्यांग:** पन्चाग

**मात्रा:** चूर्ण 2–5 ग्राम अथवा चिकित्सक के परामर्शानुसार

आचार्य बालकृष्ण

# विधायक कोष : आपके विधायक जी ने कितना काम किया?

क्या आपको यह पता चलता है कि विधायक जी को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए जो करोड़ों रुपये सरकार की तरफ़ से मिलते हैं, वो कहां जाते हैं? आपके क्षेत्र के विकास में विधायक फंड का कितना इस्तेमाल हुआ? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे. लेकिन आप यही सारे सवाल अपने विधायक से नहीं पूछते. वजह चाहे जो भी हो. लेकिन, सवाल नहीं पूछ कर आप एक तरह से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं. ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें, ताकि व्यवस्था और आपके विधायक जी पर भी दबाव बन सके.

## विधायक/सांसद विकास निधि का विवरण

**सेवा में,**
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

**विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.**

**महोदय,**

कृपया.....विधनसभा/संसदीय क्षेत्र के विधायक/सांसद विकास निधि के सम्बंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. .....से .....के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के विधायक/सांसद के निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से कराए गए सभी कार्यों से सम्बंधित निम्नलिखित विवरण दें:

क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की स्थिति अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
ञ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बंधित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं

RIGHT TO INFORMATION

3. उपरोक्त प्रतिनिधि को वर्तमान वित्त वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित हुई है तथा पिछले वित्त वर्ष से कितनी राशि शेष रही है?

4. उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितने कार्यों के लिए और कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है.

5. उपरोक्त कार्यों में से किन–किन कार्यों के लिए और कितनी राशि स्वीकृत होनी है?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

**भवदीय**

नाम:
पता:
फोन नं:

**संलग्नक:**
**(यदि हो)**

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

**चौथी दुनिया**
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

**नवाज़ शरीफ के मौजूद यात्रा के दौरान एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तानी पत्रकारों के विरोध के बीच नवाज़ शरीफ को एक पत्रकारों से खचा-खच भरे प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई. अमेरिकी विदेश मंत्री ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में नवाज़ शरीफ से लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. एक पाकिस्तानी पत्रकार सामी अब्राहम के मुताबिक जॉन केरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उनका नाम नवाज़ लेकर मुख़ातिब किया. हालांकि पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है.**

# फीका रहा नवाज़ शरीफ का अमेरिका दौरा

**अमेरिका को यह मालूम है कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की कोई खास अहमियत नहीं होती. खास तौर पर जिन मामलों में फ़ौज और आईएसआई प्रत्यक्ष रूप से शामिल हों. इसीलिए नवाज़ शरीफ के अमेरिका पहुंचने पर जिस तरह की गर्मजोशी की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वह देखने को नहीं मिली. इसके उलट पाकिस्तानी मीडिया ने नवाज़ शरीफ की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी जो आवाभगत हुई उसको लेकर खुल कर मजाक उड़ाया. पाकिस्तानी उर्दू न्यूज़ चैनल ने नवाज़ शरीफ के एयरपोर्ट पर स्वागत को शर्मनाक करार दिया.**

शफ़ीक आलम

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ का अमेरिका दौरा पाकिस्तान के लिए कई लिहाज़ से महत्वपूर्ण था. हालांकि अमेरिकी विशेषज्ञों ने इस दौरे को लेकर कोई बहुत उत्साह नहीं ज़ाहिर किया, लेकिन फिर भी कुछ समीक्षक इसे बहुत महत्व दे रहे थे. पाकिस्तान में भी इस यात्रा से बहुत उम्मीदें थीं. पिछले एक दशक से पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में काफी खटास पैदा हुआ है. 9/11 के न्यूयॉर्क के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में शामिल तो हुआ, लेकिन तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में उसकी भूमिका अमेरिका की नज़र में हमेशा संदिग्ध रही. बाद में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमेरिकी ड्रोन हमलों, सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिकी हमले, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के कम से कम 25 जवान मारे गए, ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी और अमेरिकी खुफिया फौजी करवाई में उसकी मौत ने दोनों देशों के बीच सर्द पड़ रहे रिश्तों को अपने निचले स्तर पर पहुंचा दिया. पाकिस्तान की आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की गंभीरता की कलई पूर्व राष्ट्रपति और फौजी शासक परवेज़ मुशर्रफ ने खोल दी. उन्होंने अपने एक हालिया बयान में कहा कि ओसामा बिन लादेन उनका हीरो है और पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा को प्रशिक्षण दिया है.

बहरहाल, अमेरिका को यह मालूम है कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की कोई खास अहमियत नहीं होती. खास तौर पर जिन मामलों में फ़ौज और आईएसआई प्रत्यक्ष रूप से शामिल हों. इसीलिए नवाज़ शरीफ के अमेरिका पहुंचने पर जिस तरह की गर्मजोशी की लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वह देखने को नहीं मिली. इसके उलट पाकिस्तानी मीडिया ने नवाज़ शरीफ की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी जो आवाभगत हुई उसको लेकर खुल कर मजाक उड़ाया. पाकिस्तानी उर्दू न्यूज़ चैनल ने नवाज़ शरीफ के एयरपोर्ट पर स्वागत को शर्मनाक करार दिया. हालिया दिनों में जब भी कोई पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के दौरे पर गया है, तो उसके स्वागत की तुलना 1960 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा पाकिस्तान के फौजी तानाशाह अयूब खान के स्वागत से की जाती है, जिसमें एयरपोर्ट पर ही उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया था. लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि अयूब खान का ज़माना शीतयुद्ध का ज़माना था और अमेरिका दक्षिण एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना चाहता था. शीतयुद्ध के ज़माने से आज तक गंगा से बहुत पानी बह चूका है. लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के निति निर्धारक और मीडिया अभी भी उसी पुरानी विदेश नीति की सोच पर काम कर रहे हैं. इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख को न सिर्फ बट्टा लगा है, बल्कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान बिलकुल अलग-थलग पड़ गया है.

नवाज़ शरीफ की मौजूदा यात्रा के दौरान एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तानी पत्रकारों के विरोध के बीच नवाज़ शरीफ को पत्रकारों से खचा-खच भरे प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई. अमेरिकी विदेश मंत्री ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में नवाज़ शरीफ से लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया. एक पाकिस्तानी पत्रकार सामी अब्राहम के मुताबिक जॉन केरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उनका नाम नवाज़ लेकर मुख़ातिब किया. हालांकि पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है. पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और एकेडमिक अकबर अहमद ने पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के मुश्किल दौर की पृष्ठभूमि में इस यात्रा को कामयाब यात्रा करार दिया. उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाक़ात की, पेंटागन में गए, राष्ट्रपति ओबामा से उनकी लंबी बातचीत हुई, जिसमें बहुत से सांकेतिक भाव भी व्यक्त किए गए, जैसे नवाज़ शरीफ ने ओबमा की मां की वह तस्वीरें भेंट की जो उस ज़माने की थीं, जब वह पाकिस्तान में एक सहायता कर्मी थीं. पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद भी इस दौरे को कामयाब दौरा करार देते हैं. हालांकि पाकिस्तानी विपक्ष ने इस दौरे को आड़े हाथों लेते हुए नवाज़ शरीफ पर भारत-पाकिस्तान मामले में पाकिस्तानी पक्ष को मजबूती से नहीं रखने का आरोप लगाया.

**तालिबान के साथ बातचीत की प्रकिया में भारत को शामिल नहीं किया गया है. साझा बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्तों पर भी जोर दिया गया. लशकर-ए-तैयबा के विरुद्ध करवाई की मांग भारत बहुत दिनों से कर रहा है. हालांकि साझा बयान में पाकिस्तान ने लश्कर और उसे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, उसकी आतंकवाद विरोधी नीति पर किसी को भरोसा नहीं है.**

बहरहाल, कुल मिलाकर देखा जाए, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बैठक के बाद जो साझा बयान जारी किया गया उसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता, परमाणु सुरक्षा, तालिबान का मसला, व्यापार और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शामिल थे. लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, तो नवाज़ शरीफ कोई बड़ी चीज़ लेकर अमेरिका से वापस नहीं आए. सबसे पहले, तो उन्हें सिविल न्यूक्लियर सहयोग के मुद्दे पर नाकामी हाथ लगी, जिसके लिए पाकिस्तान वर्षों से कोशिशें कर रहा है. पाकिस्तान यह चाहता था कि अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग के लिए अपनी भारत के साथ 123 समझौते की तरह पाकिस्तान के साथ भी सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर समझौता करे. अमेरिका यह भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों के ज़खीरे में कमी लाए.

ओबामा-शरीफ के साझा बयान में जो भारत के सरोकार वाले मुद्दे हैं, उनमें अमेरिका ने पाकिस्तान के उर्जा आपूर्ति की कोशिशों में दियामर-भाषा बांध परियोजना में पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया है. यह प्रोजेक्ट पाक-अधिकृत कश्मीर में है. भारत इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति जताता रहा है. साझा बयान में पाकिस्तान से आतंकवाद खासतौर पर हक्कानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा पर कार्रवाई करने और तालिबान को अफगानिस्तान सरकार के साथ सीधी बातचीत के टेबल पर लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है, जिसके लिए राष्ट्रपति ओबामा ने पाकिस्तान की तारीफ की है. तालिबान के साथ बातचीत की प्रकिया में भारत को शामिल नहीं किया गया है. साझा बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्तों पर भी जोर दिया गया. लशकर-ए-तैयबा के विरुद्ध करवाई की मांग भारत बहुत दिनों से कर रहा है. हालांकि साझा बयान में पाकिस्तान ने लश्कर और उसे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, उसकी आतंकवाद विरोधी नीति पर किसी को भरोसा नहीं है. पाकिस्तान हमेशा अपने वादों से मुकरता रहा है.

जहां तक नवाज़ शरीफ के अमेरिका दौरे का सवाल है, तो जैसा की ऊपर ज़िक्र किया जा चूका है कि अमेरिका यह भली भांति जानता है कि आंतरिक सुरक्षा, न्यूक्लियर मुद्दा, आतंकवाद, विदेश नीति का निर्धारण फ़ौज करती है. बहुत सारे मामलों में नवाज़ शरीफ का आश्वासन कोई खास महत्व नहीं रखता और असल मुद्दे पर बात पाकिस्तान सेना के अध्यक्ष जनरल राहील शरीफ के प्रस्तावित अमेरिका दौरे पर होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

## अंतरराष्ट्रीय अपराधी

# सीरियल किलर हुआंग योंग

सन् 1974 में हुआंग योंग का जन्म चीन में हुआ था. हुआंग योंग दिखने में, तो मध्यम कद काठी और चेहरे से भोली सूरत वाला था. लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके इसी भोली सूरत के पीछे एक भयानक चेहरा छिपा हुआ है. सन् 2001 से ही हुआंग योंग एक खतरनाक सीरियल किलर के नाम से लोगों के बीच विख्यात होने लगा. वह वीडियो हॉल, इंटरनेट कैफे, वीडियो गेम की जगह घूमने वाले बेरोज़गार युवाओं से मिलता और उनको पैंसे और नौकरी दिलाने की लालच देकर अपने घर ले जाता. अपने घर ले जाकर युवाओं को ड्रग्स देकर उन्हें उसकी बुरी लत लगा देता था और उसके बाद उन्हें अपनी बुरी मानसिकता का शिकार बनाता. वह बहला फुसला कर जिन लोगों को अपने घर लेकर आता उनका पहले शारीरिक शोषण करता और अंत में उनका गला घोंट कर उन्हें बेहरहमी से मार देता. जानकार बताते हैं कि हुआंग योंग ने अपनी खतरनाक मानसिकता के चलते 17 किशोरों को मौत के घाट उतार चुका था. हुआंग योंग के हाथों से नौजवान लड़के और लड़कियों के मरने का सिलसिला यू हीं चलता रहता, लेकिन सन् 2003 में 16 साल का जांग लिआंग सीरियल किलर हुआंग योंग को चकमा देकर उसकी गिरफ्त से भाग निकला. हुआंग योंग की गिरफ्त से निकलते ही जांग लिआंग पुलिस थाने गया. लिआंग ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. जांग लिआंग ने बताया कि हुआंग योंग उसे नौकरी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया, घर पहुंचते ही हुआंग योंग ने उसका गला घोटना चाहा, जिससे वो तीन बार बेहोश हो गया. जब वह बेहोशी से उठा, तो हुआंग योंग ने उससे कहा कि वह अब तक 25 युवाओं को बेहरहमी से मौत के घाट उतार चुका है और अब 26वां नंबर तुम्हारा है, जिसे मैं मौत की घाट उतारने वाला हूं. जांग लिआंग के बयान पर पुलिस अधिकारियों ने हुआंग योंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया. हुआंग योंग पर 25 युवाओं को मारने के आरोप पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई. कानूनी कार्रवाई के दौरान हुआंग योंग ने अपना अपराध कबूलते हुए कहा कि मैं बचपन से ही हत्यारा बनना चाहता था, लेकिन मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला. हुआंग योंग युवाओं को मौत के घाट उतार देने के बाद स्मृति चिन्ह के लिए मरने वाले युवाओं का बेल्ट संभालकर रखता था. कानूनी कार्रवाई में हुआंग योंग पर लगे सारे आरोप साबित हुए और न्याय प्रणाली ने हुआंग योंग को 9 दिसंबर 2003 को फांसी की सजा सुना दी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

## संक्षिप्त ख़बरें

### इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन

भारत में कई हत्याओं के केस में आरोपी राजेंद्र सदाशिव निखलांजे जिसे दुनिया अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम से जानती है, उसे इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है. सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा ने राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सीबीआई ने इंटरपोल से आग्रह किया था, जिस पर बाली पुलिस ने छोटा राजन को गिरफ्तार किया है. बाली पुलिस के प्रवक्ता हेरी वियानतो ने एएफपी को बताया कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर इंडानेशियाई अधिकारियों ने रविवार को राजन को सिडनी से बाली के एक चर्चित रिजॉर्ट में जाते हुए हिरासत में लिया. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छोटा राजन को गिरफ्तार करने के भारत सरकार के प्रयासों की यह बड़ी सफलता है और इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया को धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार लंबे समय से उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी और इस सिलसिले में इंटरपोल से आग्रह किया गया था. यह पूछने पर कि राजन को कब भारत लाया जाएगा तो राजनाथ ने कहा कि सीबीआई और दूसरी एजेंसियां इंडोनेशिया के अधिकारियों के संपर्क में हैं और सभी चीजों पर काम हो रहा है. 55 साल का गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन मुंबई का रहने वाला है और कई हत्याओं और अवैध हथियार रखने एवं उनके इस्तेमाल का आरोपी है. वह दो दशकों से भारत से फरार था और साल 1995 से ही इंटरपोल ने उसे वॉन्टेड लिस्ट में डाल रखा था. हैरी वियानतो ने कहा है कि, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जल्द ही भारत के हवाले कर दिया जाएगा. ■

### 14 साल बाद पाकिस्तान से घर लौटी गीता

करीब डेढ़ दशक पहले दुर्घटनावश सीमा पार करके पाकिस्तान चली गई मूक-बधिर भारतीय लडकी गीता आखिरकार अपने देश भारत लौट आई है. पाकिस्तान में गीता की देख रेख कर रहे परिवार के लोग भी उसके साथ दिल्ली आए थे. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं हिंदुस्तान की बेटी का हिंदुस्तान की सरजमीं पर स्वागत करती हूं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमने गीता के माता-पिता की तलाश रोकी नहीं है, गीता ने अभी किसी को पहचाना नहीं है. उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि गीता सांकेतिक भाषा सीखे. उसका परिवार मिलने के बाद भी हम चाहते हैं कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने. गीता करीब 14 साल पहले पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी समझौता एक्सप्रेस में अकेली बैठी मिली थी, तब उसकी उम्र महज सात या आठ साल की थी. गीता को एदी फाउंडेशन की बिलकिस एदी ने अपनाया और वह कराची में उनके साथ रहने लगी. अब गीता 23 साल की हो चुकी है. गीता के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे पाकिस्तानी राजनयिक ने उम्मीद जताई है कि भारत यहां की जेलों में बंद पाकिस्तानी नागरिकों के साथ भी ऐसा ही ख्याल रखेगा. वहीं गीता के पिता होने का दावा कर रहे बिहार के रहने वाले जर्नादन महतो का कहना है कि मैं बहुत खुश हूं और उसके लौटने से गांव में तो दिवाली जैसा माहौल है. पांच बेटे और दो बेटियों के पिता महतो कहते हैं कि गीता ही उनकी सबसे बड़ी बेटी हीरा है, जो कि साल 2004 के मेले में खो गई थी. नई दिल्ली जाने के लिए विमान में सवार होने से पहले बेहद खुश नजर आ रही गीता ने पाकिस्तानी जनता का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतने साल तक उसका ख्याल रखा. एदी फाउंडेशन के फैज़ल एदी ने संवाददाताओं को बताया कि वे सोशल मीडिया के जरिए गीता के संपर्क में बने रहेंगे और यहां तक कि उससे मिलने भी आया करेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

लोगों की मान्यता के अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकारित हो रही है. इस मंदिर के पुजारी सहित इस नगर के लोग भी भगवान नरसिंह के इस शालिग्राम की मूर्ति के बारे में उनसे जुड़ी अनेक बाते बताते हैं. मंदिर के पुजारी पंडित लक्ष्मी प्रसाद डिमरी कहते हैं कि जब कभी इस हिमालयी क्षेत्र में अकाल सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो लोकमान्यताओं के अनुसार जनसमूह द्वारा भगवान श्री की प्रतिमा को गर्म जल से स्नान कराया जाता है, इस स्नान के बाद भगवान श्री के मूर्ति में अचानक फफोले निकल आते हैं.

साई वंदना

# सद्गुरु घट-घट में व्याप्त हैं

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

***क्या बाबा की पूजा करने के बाद किसी और की पूजा करने की आवश्यकता है ?***

नहीं, क्योंकि श्री साईंनाथ पूर्ण ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त कर चुके थे. बाबा ने कहा था–

मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट–घट में व्याप्त हूं. मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाए हुए हैं. मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता व संचालक हूं. मैं ही उत्पत्ति स्थिति व संहारकर्ता हूं. मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है. समस्त जंतु चीटियां तथा दृश्यमान परिवर्तन और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं.

गुरु ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पर सद्गुरु यदि एक बार मिल चुके हों, तो फिर अन्य को ढूंढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए. बाबा ने विजयानंद को भी एक स्थान पर स्थिर रहकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा था. केवल सद्गुरु ही जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं और एक सद्गुरु में अनेक गुरुओं को देखा जा सकता है. जैसे मुले शास्त्री को बाबा में अपने कैलाशवासी गुरु घोलपस्वामी दिखाई दिए.

आज भी श्री साईंनाथ जी की कृपा पाने के बाद अन्य गुरु धारण करने वाले बहुत कम हैं. जिन्होंने भी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए अन्य गुरु धारण किया है, यह समझना होगा कि उन्होंने वास्तविक भक्ति से श्री साईंनाथ को भी धारण ही नहीं किया. उनकी भक्ति वस्तुत: एक दिखावा थी. कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो किसी भी व्यक्ति को गुरु मानकर उन्हें श्री साईंनाथ के समान मानने का प्रयास करते हैं. सद्गुरु के समकक्ष सद्गुरु ही हैं. उनकी समानता किसी अन्य से नहीं हो सकती. मेहरबाबा ने भी कहा था ''बाबा के समय में पांच सद्गुरु थे''.

***बाबा की पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा क्यों आवश्यक नहीं है?***

इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है.

'श्री साईं सच्चरित्र', जिसमें बाबा के द्वारा दिए गए उपदेशों को यदि अच्छी तरह पढ़ा जाए, तो यह पता चलेगा कि बाबा ने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न–भिन्न प्रकार का रास्ता दिखाया. बाबा ने यह कहा था ईश्वर के पास पहुंचने के अनेक पंथ हैं. यहां से भी एक मार्ग है. जब मेघा मंदिर में शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करके आया, तो बाबा ने उससे कहा कि उसने वहां जाकर पूजा क्यों नहीं की. बहुत भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे. जैसे सब नदियां समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सद्गुरु की शरण में जाकर किसी भी देवी देवता की पूजा करे, आखिर में उन्हीं में विलय होगा. जन्मों0के संस्कार अथवा परिवार से उत्पन्न संस्कारों के कारण कुछ भक्त अन्य देवी–देवताओं के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं. यह गलत नहीं है, पर यह उद्देश्य नहीं है. ये केवल मार्ग हैं. वेदों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान की अलग–अलग रूपों में पूजा होती है किंतु सद्गुरु की सभी रूपों एवं गुणों द्वारा–चाहे वे किसी भी रूप में हो–पूजा की जा सकती है. इसलिए जो बाबा के प्रति अनन्य आश्रित भाव रखता है, वह अवश्य ही समस्त देवी–देवताओं को अगर इच्छा भी है, तो उन्हीं के अंदर देखेगा. बाबा इसके बारे में पर्याप्त संकेत दे चुके हैं.

**मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट–घट में व्याप्त हूं. मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाए हुए हैं. मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता व संचालक हूं. मैं ही उत्पत्ति स्थिति व संहारकर्ता हूं. मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है. समस्त जंतु चीटियां तथा दृश्यमान परिवर्तन और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं. गुरु ढूंढ़ने का प्रयास करना चाहिए.**

''जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है, वह सदैव मेरा दर्शन पाता है. उसके लिए मेरे बिना संसार ही सूना है. वह केवल मेरा ही लीलागान करता है. वह सतत् मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति (आत्मोपलब्धि) प्रदान करके चुका दूंगा. जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख–प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं. जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है, जिस तरह नदियां समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

**साई भक्तों!**

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

## जोशीमठ में स्थित है

# भगवान नरसिंह की अद्भुत मूर्ति

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

देवभूमि हिमालय के पावन जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक दिव्य शालिग्राम की ऐसी स्वंयभू मूर्ति है, जो कला, धर्मिक विश्वास और मान्यताओं का बेजोड़ नमूना है. यह मूर्ति आदि जगतगुरू शंकराचार्य द्वारा पूजित उनकी तपोस्थली ज्योर्तिमठ में नारायण धाम के रूप में विख्यात है. जगतगुरू शंकराचार्य को ज्ञान–ज्योति मिलने के कारण ज्योर्तिमठ के रूप में विख्यात शहर को अब जोशीमठ के नाम से पुकारा जाता है. ढाई हजार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत से जब आदि जगतगुरू शंकराचार्य हिमालय सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए और यहीं पर कठिन तपस्या की, तपस्या के दौरान उन्हें इसी प्रतिमा के माध्यम से ज्ञानज्योति के दर्शन हुए. इस मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदिगुरू शंकराचार्य जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें अचानक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञानज्योति प्राप्त हुई. भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रौद्ररूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया. इसी पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल के समय में छ:माह तक उनकी पूजा की जाती है. पूजारी के अलावा किसी भक्त द्वारा नरसिंह भगवान का स्पर्श पूर्ण वर्जित है. इस मूर्ति को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं हैं, जिसके अनुसार ऐसी मान्यता है कि यहां अवस्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे–धीरे पतला होता जा रहा है. इसके संदर्भ को लेकर लोगों में ऐसी मान्यता है कि जिस दिन मूर्ति से हाथ का वह हिस्सा अलग हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित जय–विजय पर्वत भी आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा. भविष्य में भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ से 22 किमी आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे. अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह भगवान के हाथ का वह हिस्सा सूई के गोलाई के बराबर रह गया है. भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यता के अनुरूप भविष्य बद्री में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी आकारित हो रही है. इस मंदिर के पुजारी सहित इस नगर के लोग भी भगवान नरसिंह के इस शालिग्राम की मूर्ति के बारे में उनसे जुड़ी अनेक बाते बताते हैं. मंदिर के पुजारी पंडित लक्ष्मी प्रसाद डिमरी कहते हैं कि जब कभी इस हिमालयी क्षेत्र में अकाल सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो लोकमान्यताओं के अनुसार जनसमूह द्वारा भगवान श्री की प्रतिमा को गर्म जल से स्नान कराया जाता है, इस स्नान के बाद भगवान श्री के मूर्ति में अचानक फफोले निकल आते हैं. उसके बाद वर्षा होती है, पुजारी डिमरी सहित अनेक लोगों की जुबानी अनेक चमत्कारिक किस्से सुने जाते हैं, जिसमें पुजारी डिमरी जी आत्म अनुभव बताते हुए कहते हैं कि भगवान नरसिंह का स्वरूप पूरी तरह से शांत रूप के साथ लोककल्याण कारी है, यहां पूजन से सभी मनोरथ के साथ ही सहज रूप से मानव को सिद्धि भी प्राप्त होती है.

जोशीमठ में आज भी आदि जगतगुरू शंकराचार्य की तपस्थली स्थित है, जो एक अति प्राचीन कल्पवृक्ष के साथ लगी हुई है. इसी वृक्ष के नीचे आदिगुरू ने कठोर तप किया था. इस कल्पवृक्ष के बारे में जानकार लोग बताते हैं कि यह एक शहतूत का वृक्ष है. आदिगुरू के तप के प्रभाव के कारण इसे भी दीर्घ जीवन का सौभाग्य प्राप्त है. इस वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव विराजमान हैं, जिनके मंदिर के एक भाग में आदि जगतगुरू शंकराचार्य द्वारा जलाई गई लोककल्याण के लिए एक अखंड ज्योति आज भी यहां आने वाले भक्तों के जीवन में प्रकाश भर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

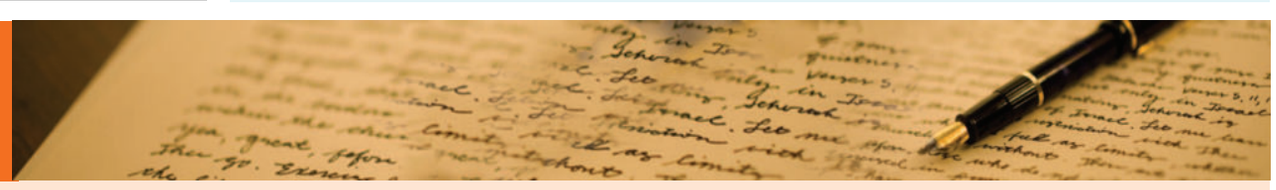

**सरकार की पोल खोल दी**

जब तोप मुकाबिल हो में सम्पादक जी ने पूछा है कि सम्पादकीय गलत है, तो हमें सच्चाई बताइए. इस सम्बंध में लिखने के लिए सम्पादक जी को बधाई. लेख में दिए गए सभी तथ्य सच्चाई के आस–पास ही हैं. अच्छे दिनों का वादा कर आने वाली मोदी सरकार में महंगाई बेकाबू है. दालों में 70 रुपये किलो मिलने वाली अरहर दाल 130 रुपये प्रतिकिलो तथा 15 रुपये किलो मिलने वाली प्याज की कीमत 50 रुपये ऊपर है. तिलहन में शुद्ध सरसो तेल दुर्लभ है. ये तथ्य तो बानगीभर हैं. इसी तरह अन्य तथ्यों ने सरकार की पोल खोल दी है. जन सरोकारों को प्राथमिकता देकर सच्चाई से रूबरू कराने के लिए चौथी दुनिया अखबार को पुन: साधुवाद!

*–सत्य प्रकाश शिक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

**चुनाव प्रचार से मुद्दे गायब**

बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया. इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने विरोधियों के लिए एक से बढ़कर एक भाषा का इस्तेमाल किया. नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में सारी मर्यदाओं को तोड़ दिया. कोई नेता किसी को ब्रह्मपिशाच और नरभक्षी कहता है, तो कोई किसी को शैतान कहता है, लेकिन जनता के हित की बात कोई नहीं करता. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी लालू यादव और नीतीश कुमार के आरोपों और उनके हमलों का ही जवाब देते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अरहर की दाल की कीमत पर भी बोलना चाहिए, जो खुले बाजार में 200 रुपये प्रति किलो मिल रही है. यह जरूर है कि प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, लेकिन जनता को महंगाई और अन्य किए गए वादों पर भी जवाब चाहिए. हम मानते हैं कि अभी मोदी सरकार को केवल डेढ़ साल हुआ है, लेकिन जनता जवाब चाहती है. बिहार विधानसभा में जादू, टोना और तंत्र मंत्र का भी खूब जिक्र हुआ. लालू यादव ने कहा कि भाजपा जादू, टोना, तंत्र मंत्र वाली पार्टी है, तो नरेन्द्र मोदी ने नीतीश के साथ तांत्रिक वाले वीडियो को लेकर नीतीश और लालू पर प्रहार किया. अगर हम पूरे बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को देंखे, तो चुनाव प्रचार से असल मुद्दा गायब रहा है.

*–वशिष्ठ नारायण तिवारी, बक्सर, बिहार.*

**आर पार की लड़ाई**

कवर स्टोरी–बिहार विधानसभा चुनाव, अंतिम दो चरण निर्णायक होंगे(26 अक्टूबर–01 नवंबर, 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. यह बिल्कुल सही है कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर टिकी है. बिहार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान के बाद से पिछड़ों का वोट महागठबंधन के पाले में चला गया. इस चुनाव में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट डाले हैं और महिलाओं का वोट किससे पक्ष में गया है इसका कोई आकलन नहीं कर पा रहा है. लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम दो चरणों का मतदान ही राज्य विधानसभा की तस्वीर तय करने वाला साबित होगा, क्योंकि इन्हीं के दौरान महा–गठबंधन के माय समीकरण की परीक्षा होनी है, इन्हीं दो चरणों में पप्पू यादव एवं ओवैसी जैसे नेताओं की ताकत का आकलन भी होना है. चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चला पाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा.

*–रामकिशोर यादव, दरभंगा, बिहार.*

**मीडिया का संक्रमण काल**

लोकतंत्र का चौथा खंभा कमजोर हो रहा है( (26 अक्टूबर–01 नवंबर, 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. कमल मोरारका ने बिलकुल सही कहा है कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले दस सालों से कुछ समाचार–पत्रों को छोड़कर, अधिकांश समाचार–पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यवसायिक घराने के हो गए हैं. इसलिए समाचार चैनल और समाचार पत्र व्यवसाय का जरिया बन गए हैं और हम सभी जानते हैं कि जहां व्यवसाय होगा वहां पत्रकारिता नहीं हो सकती. व्यवसायी किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता और न ही लिख सकता है, क्योंकि उसे पैसा कमाने के लिए अपना व्यवसाय चलाना है. यही हाल आज के मीडिया का है. कमल मोरारका के इस बात से भी मैं सहमत हूं कि बहुत से लोग हैं, जो हिंदी या अंग्रेजी तो जानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं के बराबर जानते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मीडिया का संक्रमण काल चल रहा है.

*–कृष्णकांत ओझा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

**यह है असली पत्रकारिता**

चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र का मुझे हर सप्ताह बेसब्री से इंतजार रहता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र एक तथ्यपरक समाचार पत्र है. मैं इस समाचार पत्र को चार साल से पढ़ता आ रहा हूं. इसमें मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया ही पढ़ने को मिलता है.चौथी दुनिया समाचार पत्र में संतोष भारतीय द्धारा लिखा गया जब तोप मुकाबिल हो हमेशा किसी ने किसी अलग मुद्दों पर आधारित और जनता से जुड़ा होता है. संतोष भारतीय बहुत बेबाकी से मुद्दों को उठाते हैं. कमल मोरारका का आलेख हमेशा बेहद प्रभावित करता है और हर बार एक नई जानकारी देता है. अगर हम सही मायने में कहें, तो चौथी दुनिया असली पत्रकारिता कर रहा है. चौथी दुनिया समाचार पत्र ने कई घोटालों को उजागर किया है और हमें उम्मीद है कि आगे बड़े घोटालों को उजागर करेगा.

*–अमित त्रिपाठी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

# अराजकता का लाइसेंस नहीं स्वायत्तता

अनंत विजय

समकालीन भारतीय साहित्य इन दिनों संघर्ष, विरोध, प्रतिरोध, प्रदर्शन, प्रति प्रदर्शन, पुरस्कार वापसी आदि जैसे शब्दों से गूंज रहा है. शुक्रवार को तो इन शब्दों से दिल्ली के रवीन्द्र भवन का परिसर भी गूंजा. कहना न होगा कि शब्दों में ताकत होती है, लिहाज़ा इस ताकत के आगे साहित्य अकादमी कुछ झुकती हुई नजर आई. साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के तौर पर की गई थी और इसकी स्थापना करनेवालों ने इस संस्था को लेकर एक सपना देखा था. उनका सपना कितना साकार हो पाया, इसपर लंबी बहस हो सकती है. होनी भी चाहिए. आगे इस लेख में इस पर चर्चा होगी. अबतक करीब तीन दर्जन से ज्यादा लेखक साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटा चुके हैं. इस स्तंभ में इसकी वजहों को लेकर चर्चा हो चुकी है. पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों के दबाव में अकादमी की कार्यकारिणी ने कलबुर्गी हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की. अकादमी ने तीसरी बार कलबुर्गी की हत्या की निंदा की. यह अच्छी बात है कि एक लेखक की मौत पर साहित्य अकादमी, दबाव में ही सही, तीन बार निंदा करने को बाध्य हुई. हालांकि विरोध कर रहे लेखकों की तरफ से यह बात प्रचारित की गई थी कि अकादमी ने कलबुर्गी की हत्या पर शोक सभा, संदेश आदि नहीं किया. साहित्य अकादमी ने शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि–अपनी विविधताओं के साथ भारतीय भाषाओं के एकमात्र स्वायत्त संस्थान के रूप में, अकादमी भारत की सभी भाषाओं के लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूरी दृढ़ता से समर्थन करती है और देश के किसी हिस्से में, किसी भी लेखक के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के अत्याचार या उनके प्रति क्रूरता की बेहद कठोर शब्दों में निंदा करती है. हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपराधियों के ख़िलाफ़ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं और यह भी कि लेखकों की भविष्य में भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. अकादमी का बयान यहां तो ठीक था लेकिन उसके बाद उसने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए मांग कर डाली कि केंद्र और राज्य की सभी सरकारें हर समाज और समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का माहौल बनाए रखें. साहित्य अकादमी लेखकों की राजनीति के बीच में पार्टी बनती नजर आ रही है. अकादमी इशारों में वो बातें करना चाहती है जो कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ती हैं. अशोक वाजपेयी, नयनतारा सहगल और कई लेखकों ने अखलाक की हत्या का मुद्दा भी उठाया था. समाज में सहिष्णुता आदि की मांग करना उसी दबाव का नतीजा है. साहित्य अकादमी का केंद्र और राज्य सरकारो से ये मांग करना अपने दायरे से बाहर निकलने जैसा है. लोकतंत्र में हर संस्था की एक निश्चित मर्यादा होती है. इस मर्यादा का अतिक्रमण कर साहित्य अकादमी ने एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत कर दी है जिसका रास्ता उसको राजनीतिकरण की तरफ ले जा सकता है.

अकादमी ने अपने बयान में अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी का समर्थन भी किया– कार्यकारी मंडल, अकादमी के अध्यक्ष के सतर्क और कर्मठ नेतृत्व में साहित्य अकादमी की गरिमा, परंपरा और विरासत को बरकरार रखने के लिए उनके प्रति सर्वसम्मति से अपना समर्थन व्यक्त करता है. अब इन दो पंक्तियों पर गौर करने की जरूरत है. इस वक्त यह आवश्कता क्यों महसूस की गई कि कार्यकारिणी अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी के पक्ष में समर्थन का प्रस्ताव पारित करें. क्या विश्वनाथ तिवारी पर कोई खतरा है या फिर उनको लेकर सरकार में कुछ चल रहा है जिसको कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है. कुछ तो है जिसकी परदादारी है. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की ही अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक ने उनके ही समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया. इतिहास ने एक बार फिर से अपने को दुहराया. कोलकाता में वर्तमान सामान्य सभा के सदस्यों के चुनाव की अध्यक्षता भी प्रोफेसर तिवारी ने ही की थी. उनकी ही अध्यक्षता में हुई बैठक में उनको अध्यक्ष चुना गया था. उस वक्त इसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ये बातें दब कर रह गई थीं. अब वक्त आ गया है कि साहित्य अकादमी के संविधान में बदलाव किया जाए. सामान्य सभा के सदस्यों के चुनाव को मतपत्रों के जरिए चुना जाना चाहिए. हाथ उठाकर हर भाषा के अपने अपने चहेतों को चुन लेने की परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए. इसी तरह से सामान्य सभा के सदस्यों को लेकर भी एक बड़ी खामी है. इस वक्त सामान्य सभा में असम, गुजरात, नगालैंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सदस्यों की जगह खाली है. अकादमी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन जगहों को भरा जाए. अगर किसी भी कारणवश किसी भी राज्य के किसी नुमाइंदे की जगह खाली रहती है तो वो पूरे पांच साल तक खाली रहेगी. अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष आदि को कई बार व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर इस बारे में अनुरोध किया गया लेकिन इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया गया. इसकी क्या वजह हो सकती है यह तो अकादमी के कर्ताधर्ता ही जानें. इसके पहले कि साहित्य अकादमी फिर से किसी विवाद में घिरे सामान्य सभा के सदस्यों को इस बाबत विचार करना चाहिए.

**साहित्य अकादमी भले ही स्वायत्त संस्था है पर ये करदाताओं के पैसे से चलती है. स्वायत्तता का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी जबावदेही किसी के प्रति नहीं है. जिस तरह से संसदीय समिति ने अकादमी के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए थे वो किसी भी संस्था की जांच के लिए पुख्ता आधार प्रदान करती है. यहां यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद साहित्य अकादमी पर कब्जे को लेकर सरकार कोशिश कर रही है. उक्त रिपोर्ट तो सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की थी. उस रिपोर्ट के बाद बनी हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया यह ज्ञात होना शेष है.**

साहित्य अकादमी भले ही स्वायत्त संस्था है पर ये करदाताओं के पैसे से चलती है. स्वायत्तता का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी जबावदेही किसी के प्रति नहीं है. जिस तरह से संसदीय समिति ने अकादमी के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए थे वो किसी भी संस्था की जांच के लिए पुख्ता आधार प्रदान करती है. यहां यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद साहित्य अकादमी पर कब्जे को लेकर सरकार कोशिश कर रही है. उक्त रिपोर्ट तो सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की थी. उस रिपोर्ट के बाद बनी हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया यह ज्ञात होना शेष है. साहित्य अकादमी पर लंबे समय तक प्रगतिशील साहित्यकारों का कब्जा रहा. उस दौरान साहित्य अकादमी चंद लोगों की मर्जी की गुलाम बनकर रह गई थी. प्रगतिशील लेखकों ने जो परंपरा शुरू की थी वो अब भी बरकार है. सांस्कृतिक यात्राओं के नाम पर विदेश यात्रा में लेखकों के चुनाव को लेकर भी पारदर्शिता होनी चाहिए. अध्यक्ष इस बारे में अंतिम फैसला करते हैं लेकिन कई बार अध्यक्ष और सचिव मिलकर नाम को तय कर लेते हैं. पिछले दिनों सामान्य सभा के कई सदस्यों ने विदेश यात्राएं की. विदेश यात्राओं के नाम पर अपने–अपने को दे कि परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए. इसके अलावा अकादमी विदेशों में आयोजित होनेवाले पुस्तक मेल में भागीदारी करती है. यह अच्छी बात है लेकिन इन पुस्तक मेलों में क्या हासिल होता है इस बारे में दस्तावेज अकादमी की बेवसाइट पर अपलोड किए जाने की आवश्यकता है. जैसे आगामी महीनों में फ्रैंकफर्ट में पुस्तक मेला होगा. उसमें अकादमी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा. अकादमी की वेबसाइट पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम होने चाहिए और वहां उन लोगों ने क्या किया और क्या नतीजा रहा इस बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाई जानी चाहिए. सूचना तो सामान्य सभा की बैठकों में लिए गए फैसलों और चर्चाओं की भी होनी चाहिए. लेकिन इसके लिए इस तरह के बैठकों में चर्चा करनी होगी. पिछले दिनों अकादमी की सामान्य सभा की एक बैठक गुवाहाटी में हुई थी. बताया जाता है कि वो बैठक बमुश्किल आधे घंटे चली. देशभर से चौबीस भाषाओं के प्रतिनिधियों के अलावा करीब सौ सवा सौ लोगों को वहां बुलाया गया और आधे घंटे में बैठक खत्म! करदाताओं के लाखों रुपये फूंकने से हासिल क्या होता है इसपर विचार होना चाहिए. गतिविधियों को अगर बेवसाइट पर अपलोड किया जाए तो उसको रोका जा सकता है.

दूसरी बात यह कि अकादमी में युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है. सामान्य सभा में युवाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं है. इस वक्त भारत विश्व के सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सामान्य सभा में युवा लेखकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अकादमी के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए. दरअसल अकादमी में काबिज चंद लोग इसको होने नहीं दे रहे. सदस्यों और अफसरशाहों का गठजोड़ अकादमी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है. इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. प्रगतिशील जमात कुछ नहीं पा रही है क्योंकि गड़बड़ियों की जनक वही है. इस वजह से ही अकादमी के अध्यक्ष सीना ठोंककर अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है. मैं जुबान खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा. तिवारी जी आप हिंदी भाषा से पहले अध्यक्ष हुए हैं, कृपया जुबान खोलकर पूर्व में हुई गड़बड़ियों को उजागर करिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं. ■

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*
anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

## कुर्रतुल ऐन हैदर

कुर्रतुल ऐन हैदर को साहित्य विरासत में मिला था. उनके पिता सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू कहानी की बुनियाद रखने वाले अग्रणी लेखकों में शामिल थे. अगर कुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू का सर्वकालिक महान उपान्यासकार कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी. उनके पात्र भारतीय उपमहाद्वीप के संभ्रांत वर्ग से संबंध रखने वाले होते हैं. खास तौर पर विघटित सामंती व्यवस्था से संबंध रखते थे. आग का दरिया उनका शाहकार उपन्यास है जिसमें उन्होंने भारत की गंगा–जमुनी तहजीब की जड़ें प्राचीन काल से लेकर देश विभाजन के समय तक तलाश करने की कोशिश की है. स्ट्रीम ऑफ कांसशनेस की तकनीक में लिखा गया यह उपन्यास आज भी उर्दू का सबसे बड़ा उपन्यास माना जाता है. उनके बहुमूल्य साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था.वे कुछ समय तक मशहूर अंग्रेजी पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली की संपादक भी रहीं. इनकी अन्य कृतियों में कारे जहां दराज है, आखिरी शब्द के हमसफर, मेरे भी सनमखाने, पतझड़ की आवाज, चांदनी बेगम, चाय के बाग शामिल हैं. ■

# चिरई मनवा काहे उदास

*गांवों में पंचायत चुनाव. विकास के नारे और वादों के शोरगुल. चुनावी हथकंडे और आम आदमी के नजरिये को मुकम्मल बयां करती कहानी.*

शिवा शंकर पांडेय

अहीर टोले में गहमा–गहमी है. कोहारन मोहल्ले में भी सुबह से हलचल मची है. समूचा गांव देखते–देखते जाति बिरादरी में बदल चुका है. गांव की सम्मति और सहमति संदेह के घेरे में फंस गई है. लाइन पार की झुनका कोहारिन बड़बड़ा रही हैं–'बप्पा रे, परधानी का अइसा चुनाव...लड़कपन मा तो हथ–उठौव्वल परधान चुना जात रहा, वाह रे जमाना.... चुनावी ताप की सुरहरी में हैं गांव. वोटरों के जी का जंजाल. चुनाव लड़ने वाले दुआर घेरे हैं. साक्षात देवपुरुष के अवतार में. जुबान में मिसरी, मिठास घोलती बोली. खेत में बकरी चरा रहे धुन्नी भगत दोनों हाथ से पुट्ठा पीट खिसकढ़ी करते हैं–'जय हो काली माई, जय भैरो बाबा, गांवन का अइसेन रखा महराज बारहो महीने.

मुंशी जी की चिंता इन सबसे अलग है. पिछले दस साल में सबसे ज्यादा तबाह हुआ तो वह है किसान. डेहरी उदास, बखरी उदास. वे बिसूर रहे हैं, जनता के हमदर्द बनने वाले इन देव पुरुषों की भीड़ चुनाव बाद कहां लापता हो जाती है. चमरौटी टोले में बेवा पुरबहिन काकी के घर तीन दिन से चूल्हा नहीं जल रहा. 'चुनाव तक तो जलबै करेगा चूल्हा' हंसते हुए तंज कसते हैं लहटन चौधरी. पिछले परधान को वोट न देने की सजा सत्तर वर्षीय पुरबहिन को मिली है. बीपीएल कार्ड नहीं बना. चुनावी आपाधापी में मनसुख दादा की बात कौन सुने. डंके की चोट पर कहते हैं–भइया, गांवों में भ्रष्टाचार रग–रग में समा चुका है. एक पुरबहिन छोड़िए, यहां तो हर गांव में अइसे पुरबहिनों की भरमार है. ये सब शापित जीवन जीने को विवश हैं. बूढ़े नईम चचा, नरोत्तम तेली, गनेशी, पुरबहिन काकी जैसे तमाम बुजुर्ग अभाव में जिंदगी घिसट रहे हैं. सजाते रहो सरकारी फाइलों में उपलब्धियों के आंकड़े. सरकारी कॉलोनी आई, शौचालय आए, गरीबों को फ्री राशन भी आए पर मिले किनको? परधान के कुकुर बिलार तक हर महीने विधवा पेंशन पा रहे हैं. अचानक बमक पड़ते हैं मनसुख–कौन से नंबर का चश्मा पहनते हैं, काहे नाहीं दिखता ई सब. सरकारी योजनाओं में लाखों का घोटाला फिर पकड़े भी नहीं जाने की गारंटी. ठगहारों का मजबूत रैकेट और जांच से बचाने को उससे भी मजबूत रैकेट.

रात को मनसुख का मन बड़ा उदास रहा. नई साड़ी पहने ठकुराइन चहक रही हैं. परसों एक उम्मीदवार रात में साड़ी बांटकर वोट सेट कर गया. दूसरे ने सुना तो महुए वाली कच्ची चलवा दी. तीसरे उम्मीदवार ने नौजवानों को साधने के लिए चिलम की चकाचक व्यवस्था चौबीस घंटे कर रखी है. 'लाखों रुपये बहा दो, रुपिया तो फिर कमा लेंगे पर वोट चाहिए वोट'–गुर्रीदार मूंछ ऐंठते बोल रहे हैं ठेकेदार अविनाश पांडे. बगल खड़े गजाधर भइया मौका देख दो चूड़ी और कस देते हैं–धत मरदे! हियां मरजाद फंसी बा रुपिया सिरज के का होई. प्रत्याषी से ज्यादा घर घराना, टोला, पुरवा, बिरादरी की मरजाद फंसी है. रात को मनसुख ने सपना देखा–गांव में आदमी तेजी से खत्म हो रहे हैं चारों तरफ लाशें ही लाशें. मुर्दे में तब्दील लंबी कतार. लोगों के दरवाजों पर भीड़ जुटी है, चारों तरफ रोना पीटना मचा है. झटके में आंख खुल जाती है मनसुख की. बगल सोई घरैतिन को जगाते हैं. मनसुख को पसीने से तर बतर देख घरैतिन भी घबरा जाती हैं. पूंछती हैं, इतने हड़बड़ाए काहे हो. मनसुख बताते हैं, बड़ा ही डरावना सपना आया था. घरैतिन कहती हैं, सो जाइए, सपना तो सपना ही होता है. चुपचाप चारपाई पर लेटते मनसुख मन ही मन सोचते हैं, तू क्या जाने औरत जात, हर सपना झूंठा कहां होता है भला. ■

*(परधानी लागै आग सजनी उपन्यास का एक अंश)*

feedback@chauthiduniya.com

कविता

## माता

मां हर बेटे का मंगल चाहे,
संतानें ही स्वार्थी हो जातीं.

कोई शैतान कहे, कोई नरभक्षी,
सुनकर फटती मां की छाती.

देवी कन्या बलात्कार झेलें,
विरोध करें तो होगी राजनीति.

दल अब दस्यु गिरोह हो गए,
जनता काश इसे समझ पाती.

सत्ता के लिए अफवाह फैला,
मानवता की बलि दी जाती.

पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाते,
माता कुमाता नहीं हो जाती.

अब तो ऐसा एक लाल दे दो,
बचा सके भाईचारे की थाती.

*–गुलाम कुंदनम्*

अगर आप दुभाषिए या अनुवादक के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आपको दो या दो से अधिक भाषाएं आनी चाहिए. अनुवादक का काम किसी के बोले हुए शब्दों को दूसरी भाषा में बदलकर समझाना और नोट करना होता है. बहुत जरूरी है कि दोनों भाषाओं पर ही आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो. साथ ही मौखिक संचार कौशल भी अच्छा होना चाहिए. अनुवादक का काम कई तरीकों से होता है. कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और स्पीच वगैरह में तुरंत अनुवाद करने की जरूरत होती है. इस दौरान अनुवादक को एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठाया जाता है.

## सैर-सपाटा

# ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है माजुली

असम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है माजुली, जो इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए है. माजुली एक आध्यात्मिक स्थान भी है. माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि यह असम में नए वैष्णव धर्म का केन्द्र भी है. एक ओर जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है. वहीं दूसरी ओर सतरा इसे सांस्कृतिक पहचान दिलाता है. माजुली जोरहट से सिर्फ 20 किमी दूर है और नाव के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है.

माजुली में अक्सर बाढ़ आती रहती है और पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ता रहता है. बावजूद इसके वहां जीवन उमंगों से भरा हुआ है. आज माजुली जिस रूप में है, वह यहां के धर्म और संस्कृति की वजह से ही संभव हो पाया है. यहां की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था सतरा इस द्वीप की जीवनरेखा है. इस द्वीप पर कम से कम 25 सतरें हैं, जो मठ और धरोहर की तरह काम करते हैं. यहां आने वाले पर्यटकों की इनमें खास दिलचस्पी होती है.

सतरा सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जहां असम के अग्रणी धार्मिक गुरु श्रीमंत शंकरदेव के नए वैष्णव धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है. इन सतरों को देखे बिना माजुली की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी. यहां के हर सतरों की अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं और अलग-अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जो असमिया संस्कृति और परंपराओं के बारे में होती हैं. ऐसा माना जाता है कि ये सतरें नए वैष्णव धर्म और संस्कृति का गढ़ हैं, जिसे सबसे पहले असमिया संत श्रीमंत शंकरदेव ने बढ़ावा दिया था. उसके बाद उनके अनुयायी माधवदेव ने इसे आगे बढ़ाया. ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ वैष्णव धर्म का ही प्रचार-प्रसार किया जाता है, दरअसल माजुली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सत्तरिया का भी गढ़ है.

### कैसे पहुंचे

माजुली नदी से बना एक द्वीप है, जिसके कारण यहां नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है. नाव की सेवा जोरहट के नीमाती घाट से उपलब्ध रहती है. जोरहट ट्रेन या बस के द्वारा जाया जा सकता है.

### माजुली का मौसम

माजुली के मौसम को आप नापसंद कर सकते हैं. यहां बरसात का समय काफी लंबे समय तक रहता है. यहां गर्मी भी खूब पड़ती है और मौसम में काफी उमस रहती है. हालांकि ठंड का मौसम काफी आरामदायक होता है और माजुली घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## करियर

# विदेशी भाषा में बनाएं शानदार करियर

अच्छी भाषा कौशल का होना किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बेहद कारगर होता है. इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन के बाद जबसे मल्टीनैशनल कंपनियां भारत में आने लगी हैं, तो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स की डिमांड काफी बढ़ गई है. आप लैंग्वेज स्किल्स को ही अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं. करियर के तौर पर अपनाने के लिए यह काफी बड़ा क्षेत्र है. इस फील्ड में आपके पास कई अवसर मौजूद हैं. आप टूर ऑपरेटर से लेकर दुभाषिए और अनुवादक तक कई रूपों में काम कर सकते हैं. जहां दुभाषिया किसी के स्टेटमेंट्स को एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करता है, वहीं अनुवादक कई डॉक्युमेंट्स को एक भाषा से दूसरे में अनुवाद करता है.

### कहां हैं संभावनाएं

#### टीचिंग

जिस विदेशी भाषा पर आपकी पकड़ है, उसे पढ़ाना बहुत अच्छा विकल्प है. यह किसी भारतीय भाषा को पढ़ाने जैसा ही है. विदेशी भाषा में करियर संवारने के लिए शुरुआत टीचिंग से करनी चाहिए. माना जाता है कि एक टीचर के रूप में शुरुआत करने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करने के कई मौके आते हैं.

#### अनुवादक

अगर आप दुभाषिए या अनुवादक के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो आपको दो या दो से अधिक भाषाएं आनी चाहिए. अनुवादक का काम किसी के बोले हुए शब्दों को दूसरी भाषा में बदलकर समझाना और नोट करना होता है. बहुत जरूरी है कि दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो. साथ ही मौखिक संचार कौशल(verbal communication skills) भी अच्छा होना चाहिए. अनुवादक का काम कई तरीकों से होता है. कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और स्पीच वगैरह में तुरंत अनुवाद करने की जरूरत होती है. इस दौरान अनुवाद को एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठाया जाता है. वह संबंधित व्यक्ति की स्पीच सुनकर उसी समय माइक्रोफोन के जरिए उसे दूसरे भाषा में बदल देता है. अन्य तरीके में स्पीकर से आवाज आने के कुछ समय बाद अनुवादक उसी बात को दूसरी भाषा में समझाता है. तीसरे तरीके का प्रयोग ऐसे दो लोगों के बीच बातचीत के लिए किया जाता है, जो एक-दूसरे की भाषाएं नहीं समझ पाते.

#### प्रोफेशनल कोर्सेज

कई विश्वविद्यालय विदेशी भाषाओं में कोर्स कराते हैं. विदेशी भाषा में 10+2 के बाद तीन साल का ग्रैजुएशन कोर्स किया जा सकता है. ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं. कई निजी संस्थान, दूतावास आदि भी विदेशी भाषाओं के कोर्स कराते हैं. इनमें बेसिक और एडवांस, दोनों तरह के कोर्स शामिल होते हैं.

#### कहां से करें पढ़ाई

- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
- दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली.
- जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली.
- वर्धमान यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल.
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, उत्तर प्रदेश. ■

# यू-ट्यूब के शॉर्टकट्स

श्याम सुन्दर प्रसाद
Smart7973@gmail.com

आज कल हम कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते समय ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स का प्रयोग करते हैं और यह अच्छा भी है. शॉर्टकट्स के प्रयोग से काफी समय की बचत होती है. पर अब ऑनलाइन काम करते समय भी ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट प्रयोग करने का चलन काफी बढ़ गया है, आइए जानते हैं यू-ट्यूब पर वीडियो देखते समय शॉर्टकट्स का प्रयोग कर आप यू-ट्यूब के वीडियो को और भी आसानी से नियंत्रित सकते हैं.

- यू-ट्यूब पर चल रहे वीडियो के साउंड को अगर अचानक आपको म्यूट करना पड़े तो, तो आप M बटन को प्रेस कर साउंड को म्यूट कर सकते हैं और एक बार फिर M बटन प्रेस कर आप वापस साउंड को सुन सकते हैं.
- आप UP बटन को प्रेस कर वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और DOWN बटन को प्रेस कर साउंड को कम कर सकते हैं. अगर साउंड कम होते-होते निचले स्तर पर आ गया हो, तो एक बार और वही बटन दबा कर साउंड को म्यूट भी किया जा सकता है.
- यू-ट्यूब में वीडियो को आप F की प्रेस करके फुल स्क्रीन में स्विच कर सकते हैं और फिर दोबारा F बटन प्रेस कर आप सामान्य मोड में वापस आ सकते हैं. इसके अलावा आप Esc बटन प्रेस करके भी फुल स्क्रीन से सामान्य मोड में आ सकते हैं.
- यू-ट्यूब में वीडियो को चलाने और बंद करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बार या K बटन को दबा सकते हैं, इनमें से किसी भी बटन को ज्यादा देर तक प्रेस करके वीडियो को धीमी गति से चला सकते हैं.
- अगर आप किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या फास्ट बैकवर्ड करना चाहते हैं या 5 सेकंड के अंतराल में वीडियो को आगे या पीछे करके देखना चाहते हैं, तो आप राइट एरो की को आगे के लिए और लेफ्ट एरो की को बैक के लिए प्रेस करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आप इससे भी ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप Ctrl बटन के साथ लेफ्ट/राइट एरो की को प्रेस करें. इससे 10 सेकंड के अंतराल में वीडियो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा.
- यू-ट्यूब में 0(जीरो) बटन को प्रेस करके आप किसी वीडियो के शुरू में जा सकते हैं, इसके साथ ही आप कीबोर्ड से होम बटन को दबा कर वीडियो के स्टार्ट में जा सकते हैं.
- आप एंड (End) बटन को प्रेस कर वीडियो के आखिरी में जा सकते हैं, अगर आप किसी प्ले लिस्ट को प्ले कर रहे हैं, तो एंड बटन को दबा कर आप अगले वीडियो को चला सकते हैं.
- अगर आप अपने वीडियो को कुछ परसेंट के हिसाब से आगे बढ़ाकर देखना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड के नंबर सेक्शन से 1 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग कर सकते हैं, उदहारण के तौर पर अगर आप 1 प्रेस करते हैं, तो कुल वीडियो का दस परसेंट वीडियो मूव हो जाएगा. वैसे ही आप 3 प्रेस करते हैं, तो 30 प्रतिशत वीडियो मूव हो जाएगा. ■

## खाना पीना

# छठ पर्व पर बनाएं ठेकुआ का प्रसाद

बिहार अपने संस्कृति, इतिहास और विवधता के लिए जाना जाता है और बिहार का व्यंजन सबसे अधिक लोगों को पसंद आता है. नालंदा जैसी ऐतिहासिक शिक्षण व्यवस्था और अपनी गौरवपूर्ण इतिहास के चलते दुनिया भर में पहचान बनाने वाले बिहार प्रदेश में ऐसे कई लज़ीज व्यंजन हैं, जो स्वाद के मुरीदों का दिल जीतने का दम रखते हैं. ऐसा ही एक व्यंजन है ठेकुआ जो छठ पूजा के अवसर पर बनाया जाता है. छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है. छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित है. ठेकुआ एक स्नैक के रूप में जाना जाता है. आप इसे चीनी या गुड़ से बना सकते हैं. छठ पूजा के दौरान इसे बना कर भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है. यह कई शेप और साइज में बनाया जाता है. जिन्हें मीठा बहुत पसंद है, उन्हें ठेकुआ भी बहुत पसंद आएगा.

#### सामग्री

500 ग्राम आटा, 300 ग्राम गुड़, 50 ग्राम नारियल, घी, 1.5 कप पानी, खजूर.

#### बनाने की विधि

गुड़ या चीनी को पानी के साथ मिलाकर, उसका घोल बना लें. इस घोल को घी और नारियल को आटे में मिलाएं और आटा को अच्छी तरह गूंथ लें. जब आटा अच्छी तरह गूंथ लें, तो इसे सांचे में दबाकर रख लें. जब यह सांचे में पूरी तरह ढल जाए, तो इसे तेल में धीमी आंच पर ब्राउन होने तक तलें. ठंडा होने पर सर्व करें. ■

## फैशन

मास्को में आयोजित फैशन वीक के दौरान रूसी डिजाइनर यूलिया प्रोखोरोवा द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों का प्रदर्शन करतीं मॉडल्स

कुछ भी असंभव नहीं है. आप डट कर खेलिए, भले ही आपके सामने विश्वचैंपियन ही क्यों न हो. प्रणय के सामने जब लिन डेन था तब भी मैंने उससे यह कहा था कि वह खेल के लीजेंड हैं. लेकिन जब वह मैदान में हैं तब वह आपके प्रतिद्वंदी हैं. आपको वहां उनका सम्मान नहीं करना है उन्हें पटखनी देने की पुरजोर कोशिश करनी है. कोर्ट में यह बात दिमाग़ में नहीं लानी है कि वह दो बार के ओलंपिक चैंपियन और पांच बार के विश्व चैंपियन हैं. अगर आपके पास कुछ कर गुजरने के लिए आत्मविश्वास और साहस है तो सब कुछ संभव है.

## रियो ओलंपिक में बैडमिंटन

# एक से ज्यादा पदक जीतेगा भारत

# मधुमिता बिष्ट

पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट आज भारत की नेशनल बैडमिंटन कोच हैं. मधुमिता ने अपने करियर में आठ एकल, नौ युगल और 12 मिक्स डबल्स खिताब जीते. आज वह भारत की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं. सायना नेहवाल, पीवी संधु और अन्य खिलाड़ी उनके और गोपीचंद के दिशानिर्देश में सफलता की बुलदियों को छू रहे हैं. इंडियन बैडमिंटन लीग के दूसरे संस्करण की घोषणा के मौके पर उन्होंने चौथी दुनिया संवाददाता नवीन चौहान से भारतीय बैडमिंटन के विभिन्न पहलुओं पर बात की...प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश.

**भारत के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने की संभावनायें कितनी प्रबल हैं?**

बहुत प्रबल हैं, आप देखिए खिलाड़ियों के खेल में बहुत सुधार आया है. खिलाड़ियों की काबिलियत और प्रदर्शन को देखते हुए हम निश्चित तौर पर ज्यादा पदकों की आशा कर रहे हैं. हमारे खिलाड़ी अब दुनिया के टॉप प्लेयर्स को हरा रहे हैं. पीवी सिंधू ने विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कैरोलीना मारीन को हराया. पिछली ओलंपिक चैंपियन ल्यू ज्यूरी को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया, एचएस प्रणय ने लिन डेन को हराया, ऐसा किदंबी श्रीकांत ने भी किया. साइन लगातार ऐसा कर रही हैं. ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को क्वालीफाई करना होता है, जबकि सुपर सीरीज में जगह बनाना उससे ज्यादा कठिन है. सुपर सीरीज में खेलने के लिए आपको वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर रहना होता है, इसलिए मुझे महसूस होता है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतने में सक्षम हैं. इसलिए हम इस बार ज्यादा पदक जीतने की आशा कर रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे. लेकिन बहुत सी चीजें ड्रॉ पर भी निर्भर करती हैं, दूसरा आपके खेल पर सब कुछ निर्भर होता है. मानसिक और शारीरिक तौर पर आप कितने फिट हैं इसका भी हार–जीत पर असर पड़ता है.

**यदि हम महिला खिलाड़ियों की बात करें तो सायना नेहवाल और पीवी सिंधु बहुत अच्छा कर रही हैं, अधिकांश मौकों पर फाइनल्स में जगह बनाने के बाद भी वे खिताब नहीं जीत पाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है?**

हम ऐसा नहीं कह सकते कि वे जीत नहीं पा रही हैं. सायना की बात करें तो उन्होंने इस साल लखनऊ में जीपी गोल्ड जीता, इसके बाद इंडिया सुपर सीरीज, पिछले साल चाइना सुपर सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सुपर सीरीज जीती, लेकिन आप विश्व के दूसरे टॉप प्लेयर्स को भी देखिए. ये भी सारे टूर्नामेंट थोड़े ही जीत रही हैं, हर प्रतियोगिता जीत पाना संभव नहीं है. हर महीने एक से दो प्रतियोगिताएं होती हैं, कैरोलीना मारिन दो बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, लेकिन इस बार वो सिंधु से हार गईं. सभी प्लेयर्स ऐसे ही हैं क्वार्टर, सेमीफाइनल हार जाते हैं. हमारी आशायें होती हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे प्लेयर्स जीतें. यह ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक और मानसिक दक्षता का समन्वय जरूरी होता है. खिलाड़ी भी इंसान हैं चोटें लगती हैं परेशानियां होती हैं. लेकिन हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं.

**सायना के विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के एटीट्यूड में क्या बदलाव आया है, साथ ही भारतीय खिलाड़ियों के प्रति दूसरे देशों के खिलाड़ियों के नज़रिए में क्या बदलाव आया है?**

बिलकुल, पूरे विश्व का नजरिया भारतीय बैडमिंटन को लेकर बदला है. भारत बैडमिंटन में अच्छा कर रहा है. दूसरे देशों की नज़रें भारत पर बनी हुई हैं, कुछ दिनों पहले मैं डेनमार्क में थी, वहां एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि कैसे भारतीय बैडमिंटन में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया है. मैंने जबाव दिया कि देखिए भारतीय खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं. उनका रिस्ट वर्क नेचुरल है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं. प्रकाश पादुकोण इसमें माहिर थे, हम उस स्किल को आगे लेकर जा रहे हैं. हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं लेकिन हम अब इस पर भी काम कर रहे हैं. आज हमारे पास विश्व स्तरीय सपोर्ट स्टाफ है, फीजियो हैं. हमारे समय में ऐसा नहीं होता था. तब और अब के समय में बहुत बदलाव आ गए हैं, हम बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ गए हैं. अब हर कोई जानता है कि भारत में नए खिलाड़ी आ रहे हैं और वे विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. भारत ने विश्व बैडमिंटन के सफलता के शिखर पर अपना नाम दर्ज करा लिया है.

**कुछ साल पहले तक भारतीय खिलाड़ी चीनी और मलेशियाई खिलाड़ियों के सामने हथियार डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. खिलाड़ियों के खेल और रवैये में कौन से बदलाव आए हैं जिससे यह संभव हो पाया, राष्ट्रीय कोच होने के नाते आप खिलाड़ियों को इसके लिए क्या बताती है ?**

बतौर कोच, मैं खिलाड़ियों से यही कहती हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है. आप डट कर खेलिए, भले ही आपके सामने विश्वचैंपियन ही क्यों न हो. प्रणय के सामने जब लिन डेन था तब भी मैंने उससे यह कहा था कि वह खेल के लीजेंड हैं. लेकिन जब वह मैदान में हैं तब वह आपके प्रतिद्वंदी हैं. आपको वहां उनका सम्मान नहीं करना है उन्हें पटखनी देने की पुरजोर कोशिश करनी है. कोर्ट में यह बात दिमाग़ में नहीं लानी है कि वह दो बार के ओलंपिक चैंपियन और पांच बार के विश्व चैंपियन हैं. अगर आपके पास कुछ कर गुजरने के लिए आत्मविश्वास और साहस है तो सब कुछ संभव है.

**ओलंपिक में हम कितने पदक जीत पाएंगे?**

यह तो हम तभी बता पाएंगे कि कितने खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं. हमें लगता है कि दो खिलाड़ी पुरुष एकल, दो महिला एकल, एक महिला युगल और एक पुरुष युगल के लिए ओलंपिक में क्वालीफाई कर लेंगे. हम इस बार बैडमिंटन में निश्चित रूप से एक से ज्यादा पदक जीतने में सफल होंगे. महिला एकल में सायना और संधु दोनों पदक जीतने की दावेदार हैं, पुरुष एकल में भी आशा है. महिला युगल में ज्वाला और अश्विनी भी जीत की दावेदार होंगी. जिस तरह का स्कोरिंग सिस्टम आज बैडमिंटन में है, अपने अच्छे दिन भारतीय खिलाड़ी विश्व के किसी भी खिलाड़ी को हराने की क्षमता रखते हैं. दूसरी तरफ विरोधी कितने दबाव में है इसका भी असर भी परिणाम पर पड़ेगा. पदकों के लिए दावा नहीं किया जा सकता है लेकिन एक से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद की जा सकती है.

**आप लंबे समय से बतौर खिलाड़ी और कोच बैडमिंटन से जुड़ी रही हैं, इतने लंबे समय में बैडमिंटन को लेकर भारत के लोगों के नज़रिए में क्या बदलाव आया है? बैडमिंटन इंडिया अब तक या आईबीएल छोटे शहरों तक नहीं पहुंच पाया है ऐसा क्यों?**

यह आईबीएल का दूसरा संस्करण है, कुछ वजहों से इसके आयोजन में देरी हुई. पहले संस्करण के दौरान बैडमिंटन लोकप्रिय हुआ. लेकिन तत्काल छोटे शहरों में इसका पहुंच पाना संभव नहीं है. वहां हमें आधारभूत ढाचे की आवश्यक्ता होगी. उन शहरों में आधारभूत सुविधाएं हैं या नहीं इसके बिना वहां पहुंचपाना संभव नहीं है. वहां मीडिया भी हो ताकि दुनिया भर के लोगों तक सूचना पहुंच सके. यह कहना जल्दबाजी होगी कि हमें छोटे शहरों में जाना चाहिए. बात में हो सकता है और फ्रेंचाइजी आएं और इसका दायरा बढ़े.

**आईबीएल किस तरह भारत के ओलंपिक पदकों के सपने को पूरा करने में सहायक होगा?**

हमारे रियो ओलंपिक ड्रीम आईबीएल पर निर्भर नहीं हैं. भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आईबीएल बैडमिंटन को भारत में और ज्यादा लोकप्रिय बनाने में मददगार साबित होगा. लोग टीवी में इसे देखेंगे खासकर बच्चे. बच्चों के खेल के प्रति आकर्षित होने पर ही युवा खिलाड़ियों की नई खेप तैयार होगी. भारत और विश्व के टॉप प्लेयर्स आईबीएल में खेलेंगे. उन्हें अपने सामने खेलता देख युवाओं के मन में उनके जैसा बनने की रुचि पैदा होगी और वे बतौर करियर बैडमिंटन को अपनाएंगे. ऐसे भी भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के बाद बच्चों और अभिभावकों का रुझान बैडमिंटन की ओर बढ़ लगातर रहा है.

**सायना का विमल कुमार को अपना पर्सनल कोच बनाने का निर्णय सुर्खियों में रहा. ऐसा लगा कि चीफ नेशनल कोच गोपीचंद और सानिया के बीच दूरियां बढ़ गईं हैं. क्या ऐसी घटनाओं का असर खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच के रिश्तों पर पड़ता है?**

ऐसा कुछ नहीं है. किसी के बीच कोई दूरी नहीं है. मुझे जो जानकारी है सायना ने गोपीचंद के विरोध में कभी कुछ नहीं कहा. जो कोई भी ऐसा कह रहा है वह गलत है. आज जो खिलाड़ी जहां ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है वहां उसे भेजा जाता है, सायना ने कोच बदला यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. यह बदलाव के लिए है. दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है. मैं सायना के मैच में जाती हूं वहां उसे सलाह भी देती हूं, और वह सुनती है.

**हर खेल प्रेमी चाहता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन जब किसी स्टार खिलाड़ी से जुड़ी नकारात्मक खबरें आती हैं तो लोगों को लगता है कि ये सफलता का नशा है, क्या यहां कोई अहम की लड़ाई तो नहीं है?**

नहीं, यहां ऐसी कोई बात नहीं है, मामले को बेवजह तूल दिया गया. यह पिछले साल अगस्त में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद की बात है. वह कोच बदलकर कोशिश करना चाहती थी. जब दिल्ली में थॉमस और उबेर कप हुआ, तब विमल हमारे यहां बतौर कोच आए हुए थे लेकिन तब सायना उनके साथ नहीं थीं. तब विमल ने सबको प्रेक्टिस करवाई. उन्होंने कोच बदलने का निर्णय अपने प्रदर्शन में और सुधार के लिए किया. यह इंडीविजुवल खेल है और कोई भी खिलाड़ी अपने लिए पर्सनल कोच रख सकता है. हम सभी चाहते हैं कि सायना अच्छा करें और भारत का नाम रोशन करे. गोपी भी यही चाहते हैं. सबको सही बातों की जानकारी नहीं है इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं.

**सायना और संधु अभी अच्छा कर रही हैं, 2016 के बाद सायना कॉन्टिन्यू करेंगी या नहीं, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों की जगह आगे कौन सी या कौन से खिलाड़ी लेंगे?**

हमारे पास इसके लिए योजनाएं हैं. हमारे पास कई प्रतिभाशाली लड़के–लड़कियां हैं. रुतविका शिवानी और रितुपर्णा एकल में अच्छी हैं, इसके बाद सब जूनियर में जाएंगे. देखते हैं उन्हें कैसे ग्रूम करना है. लड़कों में सलिल वर्मा है डबल्स में कई बच्चे अच्छे हैं. सात्विक और कृष्ण प्रसाद, एमआर अर्जुन, चिराग सेट्टी जैसे कई नए खिलाड़ी प्रतिभाशाली हैं. इसलिए भविष्य भी अच्छा है.

**भारत सरकार खेलों में सुधार के लिए काम कर रही है. वह खिलाड़ियों की टॉप्स जैसी योजनाओं के जरिए मदद कर रही है? प्रशिक्षकों की फीस में बढ़ोत्तरी की है. इन सबका खिलाड़ियों को कितना फायदा मिल रहा है ?**

जब मैं और गोपी खेलते थे, उस समय सरकार खेलों के लिए ज्यादा फंड नहीं देती थी, केवल हमें हवाई यात्रा का खर्च मिलता था. लेकिन अब सरकार हर चीज का ख्याल रख रही है. नई सरकार के आने के बाद खिलाड़ियों के लिए कई नई घोषणायें हुई हैं, इसलिए विभिन्न खेलों में खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं. खिलाड़ियों के मन में अब यह बात है कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है तो हमें भी देश के सम्मान का ख्याल रखना है. उनके प्रदर्शन में भी इसका सकारात्मक असर दिखाई पड़ रहा है. जो सुविधायें हमें बतौर खिलाड़ी नहीं मिलीं अब बतौर कोच उससे अच्छी सुविधायें मिल रही हैं. हम पांच सितारा–सात सितारा होटल में ठहरते हैं. अब लॉजिंग–बोर्डिंग हर चीज की ख्याल रखा जाता है और इसके लिए आपको अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना है.

**आईबीएल का आयोजन अब लगातार बिना किसी अवरोध के होगा, आपको इसकी कितनी आशा है?**

पूरी आशा है कि इसका लगातार आयोजन होगा. हम लगातार पांच साल से सुपर सीरीज का आयोजन कर रहे हैं. हमने विश्व चैंपियनशिप का हैदराबाद में आयोजन किया. दिल्ली में थॉमस–उबेर कप के फाइनल्स का आयोजन किया. उसमें हमने मेडल्स भी जीते. फेडरेशन चाहती है कि बैडमिंटन लोकप्रिय हो, इसलिए जितनी प्रतियोगिताओं का भारत में आयोजन करेंगे, उतना बैडमिंटन लोकप्रिय होगा और युवा पीढ़ी बैडमिंटन को अपनाएगी.■

navinonline2003@gmail.com

# इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में होगया दिमाग़ का दही

**फिल्म आधिकारिक रूप से विश्व के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स के लिए नामांकित हुई है. इस बारे में फौजिया अर्शी का कहना है कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि मेरी फिल्म विश्व के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स के लिए नामांकित हुई है. मुझे इन फिल्म फेस्टिवल्स में होगया दिमाग़ का दही की स्क्रीनिंग और विदेशी दर्शकों की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है.**

16 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म होगया दिमाग़ का दही की निर्देशक फौजिया अर्शी दुनिया भर में हंसी फैलाने जा रही हैं. फिल्म आधिकारिक रूप से विश्व के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स के लिए नामांकित हुई है. इस बारे में फौजिया अर्शी का कहना है, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि मेरी फिल्म विश्व के विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स के लिए नामांकित हुई है, मुझे इन फिल्म फेस्टिवल्स में होगया दिमाग़ का दही की स्क्रीनिंग और विदेशी दर्शकों की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म अमेरिका के बोस्टन में आयोजित होने वाले 16वें आइरिश फिल्म फेस्टिवल, 6वें एनुअल क्वीन वर्ल्डस् फिल्म फेस्टिवल, 20वें कंसास एनुअल फिल्म फेस्टिवल,17वें एनुअल थ्रू विमेंस आई(यूएसए), कनाडा में होने वाले तीसरे एनुअल शार्ट इंटरनेशनल कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल, पांचवें एनुअल टोरंटो बीचेस फिल्म फेस्टिवल(कनाडा), चौथे एनुअल विमेंस इंडीपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल(अमेरिका), पांचवें एनुअल लंदन लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल(यूके), दूसरे एनुअल कैलीफोर्निया विमेंस फिल्म फेस्टिवल(विंटर) (अमेरिका) के लिए नामांकित हुई है. नबंबर में शुरू हो रही इस फिल्म की विश्वयात्रा अगले साल जुलाई में समाप्त होगी. फिल्म हो गया दिमाग़ का दही एक कॉमेडी ड्रामा है. इसमें बॉलीवुड के जाने माने पांच हास्य कलाकारों ने अभिनय किया है. फौजिया अर्शी ने फिल्म के निर्देशन के साथ फिल्म की कहानी और संवाद भी लिखे हैं, और फिल्म में संगीत भी दिया है. फिल्म के डायलॉग्स और संवाद की हर जगह प्रशंसा हो रही है. सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि लोग इस फिल्म के छोटे-छोटे डायलॉग्स का अपनी रोजमर्रा की बात-चीत में उपयोग कर रहे हैं. फिल्म को डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड के बैनर तले संतोष भारतीय और फौजिया अर्शी ने प्रोड्यूस किया है.■

# आसिन बनेंगी दुल्हन

**असिन 26 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा के साथ सात फेरे लेने जा रही हैं. दोनों की शादी नई दिल्ली में एनएच-8 पर बने एक होटल में होगी.**

बॉलीवुड एक्ट्रेस आसिन के फैन्स के लिए एक अच्छी खबर है. वह जल्द ही विवाह बधंन में बधंने जा रही हैं. आसिन 26 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा के साथ सात फेरे लेंगी. दोनों की शादी नई दिल्ली में एनएच-8 पर बने एक होटल में होगी. शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी दिल्ली के ही वेस्ट एंड ग्रीन्स फॉर्म हाउस में 27 नवंबर को होगी, यह वही फॉर्म हाउस है जहां अभिनेता शाहिद कपूर की मीरा राजपूत से शादी हुई थी. इसके बाद 28 नवंबर को मुंबई में भी एक रिसेप्शन पार्टी रखी गई है जिसमें आसिन और राहुल के नजदीकी दोस्त और रिश्तेदार शामिल होंगे. आसिन और राहुल की मुलाकात दो साल पहले हुई थी. दोनों की मुलाक़ात बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार ने करवाई थी. अक्षय कुमार और राहुल शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं. साल 2008 में जब राहुल की कंपनी बाजार में मोबाइल फोन लेकर आई थी तब अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने उनका बहुत सपोर्ट किया था. राहुल जानी-मानी भारतीय मोबाइल कंपनी माइक्रो मैक्स के को-फाउंडर और सीईओ हैं. राहुल ने नागपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा उन्होंने सस्कैचेवान यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में भी ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की है.■

# मुग्धा को इश्क़ ने क्रेजी किया रे

सुपरहिट फिल्म फैशन से हजारों जवां दिलों की धड़कन बनीं अभिनेत्री मुग्धा गोडसे एक बार फिर अपने प्रशंसकों सहित सभी को क्रेजी करने के लिए तैयार हैं. अपनी आने वाली फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे से जुड़े अनुभवों के बारे में उन्होंने चौथी दुनिया से बात की...प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश.

**अपनी आने वाली फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे के बारे में कुछ बताइए. क्या इस फिल्म में आप फैशन जैसी भूमिका में देखने को मिलेंगी?**

यह फिल्म 30 नबंबर को रिलीज होने जा रही है. इसमें फैशन जैसी मुग्धा देखने को नहीं मिलेंगी. दोनों फिल्मों के सब्जेक्ट अलग-अलग हैं. लेकिन दोनों ही फिल्में शो-बिज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. मैं इस फिल्म में शो-बिज़ क्वीन का रोल अदा कर रही हूं. जिसे फिल्म के हीरो से प्यार हो जाता है. फिल्म एक प्रेम कहानी है.

**इस फिल्म की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा क्रेजी करती है?**

बिना किसी शंका के इस फिल्म का संगीत बहुत बेहतरीन है. खासकर मीत ब्रदर्स का गाया गीत यंग यंग लौंडे बहुत शानदार है, और मैंने अपने डायरेक्टर से शिकायत भी की, कि आपने मुझे इस सॉन्ग पर क्यों नहीं फिल्माया. यह अलग बात है, फिल्म एक कहानी के आधार पर शूट होती है, लेकिन इस फिल्म का संगीत बहुत अच्छा है.

इंटरव्यू

**फिल्म के निर्देशक के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा ?**

सुपर्ब, नरेश मलहोत्रा हमारी इंडस्ट्री के बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये दिल्लगी जैसी फिल्म बनाई, निश्चित रूप से उनके साथ काम करना गर्व की बात है.

**फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा क्रेजी कौन है?**

हा हा हा...मेरे डायरेक्टर, जिस तरह से नरेश जी ने इस फिल्म में मेहनत की, उसे देखकर हम सब ने कहा कि नरेश जी इज क्रेजी.

**इस फिल्म के निर्माताओं के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?**

कुछ क्यों, बहुत कुछ कहना है. संतोष जी, आलोक सिंह जी व राधेश्याम जी इन तीनों ने इस फिल्म में पैसा तो लगाया है, साथ ही उन्होंने अपना बहुत समय भी दिया. इन्होंने बड़े शौक और पैशन से इस फिल्म को बनाया है. यूनिट के सदस्यों को ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी नए प्रोडयूसर्स के साथ काम कर रहे हैं. तीनों बहुत मेहनती और अच्छे शख्स हैं.

**इस फिल्म से जुड़े किसी खास पहलू के बारे में बताना चाहेंगी?**

जी हां, यह एक म्यूजिकल फिल्म है इसलिए कई बार हम इसके संगीत में इतना खो जाते थे कि नरेश जी के कट बोलने पर भी संगीत चलता रहता था, और हम सभी शूटिंग में इनवॉल्व रहते थे.

**संगीत से बहुत लगाव है आपको?**

बेशक और मुझे और मुझे ही क्यों, हर आर्टिस्ट को है, ये जीवन भी तो एक संगीत है और आप मेरी इस फिल्म में संगीत के कई दिग्गजों जैसे श्रवण कुमार, ललित पंडित, शेरान प्रभाकर, समीर सेन, मीत ब्रदर्स, इत्यादि को फिल्म में देख सकेंगे.

**अपने प्रशंसकों से आप क्या कहना चाहेंगी?**

यह एक ऐसी फिल्म जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, तो फिल्म देखिए और क्रेजी हो जाइए.■

# बाहुबली-3

**राजामौली ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा,फिल्म बाहुबली-3 बननी है. लेकिन फिल्म के पहले दो भाग के लिए लिखी गई कहानी को तीसरे भाग के लिए जबरदस्ती आगे नहीं खींचा जाएगा. यह कहानी दूसरे भाग के साथ ही समाप्त हो जाएगी.**

## ऐसे बनाएंगे जिसका अनुभव दर्शकों को नहीं होगा: राजामौली

दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने फिल्मकार एसएस राजामौली अपनी सुपरहिट फिल्म बाहुबली का तीसरा संस्करण भी बनाने जा रहे हैं. इस शृंखला की पहली फिल्म बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की है. राजामौली ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, फिल्म बाहुबली-3 बननी है. लेकिन फिल्म के पहले दो भाग के लिए लिखी गई कहानी को तीसरे भाग के लिए जबरदस्ती आगे नहीं खींचा जाएगा. यह कहानी दूसरे भाग के साथ ही समाप्त हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बाहुबली-3 इस तरह बनाई जाएगी, जिसका दर्शकों ने पहले कभी अनुभव नहीं लिया होगा. राजामौली नवंबर के मध्य या दिसंबर की शुरुआत में बाहुबली-2 की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे. इसकी चालीस प्रतिशत शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. फिल्म में राणा डग्गुबाती, प्रभाष, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, रमैया कृष्णन और सत्यराज मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि बाहुबली का प्रीक्वल बनाने की भी योजना है. हो सकता है कि यही फिल्म की तीसरी कड़ी हो.■

## रहमान को मिला हृदय नाथ मंगेशकर अवॉर्ड

**निर्माता सुभाष घई ने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के 78वें जन्मदिन(26 अक्टूबर) के अवसर पर रहमान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया. वह यह पुरस्कार पाने वाले पांचवें कलाकार हैं,**

बॉलीवुड के जाने-माने संगीतकार ए आर रहमान को इस साल के हृदयनाथ मंगेशकर अवॉर्ड से नवाजा गया है. जाने-माने निर्माता सुभाष घई ने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के 78वें जन्मदिन (26 अक्टूबर) के अवसर पर रहमान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया. वह यह पुरस्कार पाने वाले पांचवें कलाकार हैं. बॉलीवुड की महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जयंती के अवसर पर हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है. इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए रहमान ने कहा कि हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत सभी के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने यह भी कहा कि मंगेशकर परिवार कई पीढियों से संगीत की इस महान परंपरा को बनाए रखे है. यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अच्छे संगीतकारों व दूसरे निपुण अभिनेताओं को बतौर सम्मान दिया जाता है. पहला हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर को दिया गया था. इसके बाद आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री सुलोचना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस मौके पर हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा कि रहमान ने बेहतरीन संगीत का सृजन करके हमारे देश को गौरान्वित किया है.■

# मैथिली धारावाहिक मास्टर साहेब

साल 2002 में मैथिली को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद उसे सुदृढ़ और सशक्त बनाने का इस भाषा से जुड़े लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं. साहित्य लेखन के अलावा बहुत से नाटक, गीतों की रचना इस भाषा में हो रही है. इस भाषा में अब धारावाहिकों का भी निर्माण हो रहा है. 2 नबंबर से डीडी बिहार चैनल पर मैथिली भाषा में एक धारावाहिक मास्टर साहेब की शुरूआत हुई है, इसका प्रसारण सप्ताह में तीन दिन(सोम, मंगल, बुध) को रात्रि 9.00 से 9.30 के बीच हो रहा है. इस धारावाहिक में अभिराज झा, करण मिश्रा, शिखा चौधरी और सुरेश आनंद मुख्य भूमिका में हैं. धारावाहिक के निर्माता दिनेश कुमार सिंह है जबकि धारावाहिक की पटकथा संवाद और निर्देशन अभिराज झा ने किया है. यह एक कॉमेडी धारावाहिक है, जो दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक संदेश दे रहा है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# पौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

## बिहार-झारखंड

09 नवंबर–15 नवंबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

# उम्मीदों से लदी होगी नई सरकार

मौटे तौर पर लोगों की चिंता कानून-व्यवस्था को लेकर है. लोग मानते हैं कि नीतीश सरकार में इसमें सुधार आया था पर बाद के दिनों में इसमें लगातार गिरावट आती गई. एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि पुराने दिन लौट रहे हैं. इसलिए आमजनों के दिलों में यह नई सरकार से अपेक्षा है कि कोई भी सत्ता में आए पर वह यह सुनिश्चत जरूर करे कि सूबे में अमन-चैन और शांति रहे.

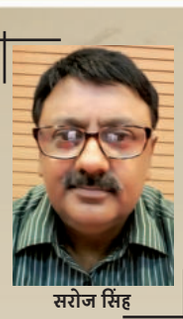

सरोज सिंह

जब आप यह खबर पढ़ रहे होंगे उस समय बिहार में नई सरकार बनने की कवायद अपने चरम पर होगी. लगभग महीने भर की ताबड़तोड़ रैलियों और जनसंपर्क के बाद चुनाव के नतीजों पर दुनिया भर की नजर थी. हर कोई अपना आकलन लेकर बहस का बाजार गर्म किए हुए था और हालात ये हो गए थे कि बिहार में एक नहीं बल्कि दो-दो सरकार बनने का दावा किया जा रहा था. मतलब एक सरकार एनडीए की बन रही थी और दूसरी महागठबंधन की. दोनों ही खेमों ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर रखा था कि आठ के बाद हमारी सरकार बनने वाली है. हैरान करने वाली बात यह रही कि दोनों ही खेमों का विश्वास सातवें आसमान पर था. भाजपा खेमा साफ कह रहा था कि बिहार में अपने बलबूते हम सरकार बना रहे हैं जबकि राजद वालों ने साफ कहा कि सरकार तो हमलोग ही बनाएंगे, लेकिन इन दोनों खेमों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो बार-बार यह कह रहे थे कि हो सकता है कि किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बहुमत न मिले. इन लोगों का कहना था कि ऐसे हालात पैदा हुए तो राज्यपाल की भूमिका काफी अहम हो जाएगी. पूर्व विधान पार्षद पीके सिन्हा का मानना है कि अगर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं.

राज्यपाल आमंत्रण के साथ इस दल को एक नीयत समय दे सकते हैं ताकि नई सरकार अपना बहुमत साबित कर सके. लेकिन इस तरह की संभावनाओं पर दोनों गठबंधनों को भरोसा नहीं है और सरकार बनाने का दावा वह लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच एक हकीकत यह है कि बिहार के लोगों ने सूबे में बनने वाली नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें बांध रखी है. दरअसल चुनावी भाषणों में नेताओं ने इतने सारे वादे लोगों से कर दिए कि जनता के मन यह ख्वाब पलना स्वाभाविक है कि नई सरकार निश्चित तौर पर अपने कहे पर सही उतरेगी. मौटे तौर पर लोगों की चिंता कानून व व्यवस्था को लेकर है. लोग मानते हैं कि नीतीश सरकार में इसमें सुधार आया था पर बाद के दिनों में इसमें लगातार गिरावट आती गई. एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि पुराने दिन लौट रहे हैं. इसलिए आमजनों के दिलों में यह नई सरकार से अपेक्षा है कि कोई भी सत्ता में आए पर वह यह सुनिश्चत जरूर करे कि सूबे में अमन-चैन और शांति रहे. आम जनता यह मानती है कि अगर यही एक काम कायदे से हो जाए तो हम अपना जीवन अपनी मेहनत से बेहतर बना सकते हैं. पटना के मोर्यलौक में चाउमीन की दुकान चलाने वाले जीवन मेहता कहते हैं कि कोई सरकार बने हमलोगों की जिंदगी बहुत बदलने वाली नहीं है, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि शांति से अपना कारोबार कर सकें. जीवन मेहता कहते हैं कि हमने कई सरकारों को देखा है. इस बार भी नेता लोग तरह-तरह का वायदा

**उत्तम का मानना है कि रोजगार देने वाली शिक्षा का भी बिहार में काफी स्कोप है. दुर्भाग्य से किसी भी सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया. वे कहते हैं कि नई सरकार को इस बारे में खास ध्यान देना चाहिए कि बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके. उत्तम बाबू कहते हैं कि बहुत राजनीति हो गई अब सब को मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. बिहार आगे बढ़ा तो सारा देश आगे बढ़ेगा. इसके बाद लोगों ने एक सुर से बिजली में सुधार की बात कही.**

करके गए हैं. देखिये क्या होता है पर हम तो यही चाहते हैं कि शांति से अपना धंधा चलता रहे बाकी भगवान सब ठीक करेगा. अमन-चैन बना रहे यह बात सभी चाहते हैं. इसके बाद अगर कोई उम्मीद या फिर नई सरकार के लिए चुनौती है तो वह यह है कि विकास की रुकी हुई गाड़ी को कैसे पटरी पर लाई जाय. बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन ठाकुर कहते हैं कि जो भी सरकार बने उसे सबसे पहले मूलभूत संरचना को दुरुस्त करना ही होगा. नवीन कहते हैं कि अभी तक इस दिशा में जो काम हुए हैं वह पर्याप्त नहीं कहे जा सकते हैं, इसलिए नई सरकार को चाहिए कि वह जितनी जल्दी हो सके संबंधित लोगों की एक बैठक बुलाकर सभी लोगों की राय सुनकर कोई समग्र नीति की घोषणा करें और इस पर तेजी से काम करे. नवीन की राय में अगर हमें सही मायनों में विकास करना है तो बिहार में कारोबार करने वाले लोगों को उचित माहौल के साथ ही साथ सभी जरूरी सुविधाएं देनी होंगी. बिहार का पैसा बिहार से बाहर जा रहा है. जाने-माने शिक्षाविद् उत्तम सिंह कहते हैं कि सरकार कोई भी बने मेरा उससे आग्रह है कि शिक्षा पर खास ध्यान दे. उत्तम कहते हैं कि शिक्षा ही समाज की बुनियाद है.

शिक्षित समाज ही विकसित समाज का निर्माण कर सकता है. उच्च शिक्षा के मामले में अभी बिहार में बहुत सारे काम करने बाकी हैं. नई सरकार से मेरा निवेदन है कि

*– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर*

गया एक नज़र

# हर किसी का जीत का दावा

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में पिछले तीन दशक में पूर्णतः हिंसा रहित शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न होने का हर कोई अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा है. मतदाता भी चुपचाप है और परिणाम के इतंजार में हैं. लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता गया जिले के दस सीटों पर अपने-अपने जीत का दावे कर रहे हैं. इस दावे के पीछे सभी के अपने-अपने तर्क है, और वोट बैंक का समीकरण के अलावा भी वोट मिलने की बातें है. 8 नवम्बर 2015 को ही स्पष्ट हो पायेगा कि एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के दावे में कितनी सच्चाई है और अपने वोट बैंक की सही जानकारी कितनी है या फिर राजनीतिक दावे ही है. जिले के भाजपा अध्यक्ष अनिल


अनिल स्वामी


अभय कुशवाहा

लोजपा के प्रदेश संगठन सचिव और अतरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अरविन्द कुमार सिंह अपनी जीत के प्रति सौ फीसद आश्वस्त होकर कहते हैं कि गया जिले की सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है. बिहार में एनडीए की सरकार बनना पूरी तरह से निश्चित है. गया जिले में जनता पूरी तरह से चुनाव में एनडीए के साथ थी.

स्वामी का दावा है कि सभी दस सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी. उनका कहना है कि गया जिले की जनता कथित जंगलराज का खामियाजा सबसे अधिक भुगत चुकी है. इसलिए जिले के सर्वांगिण विकास और शांति-अहिंसा तथा विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहां की जनता ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए जमकर मतदान किया है. सभी जाति व वर्ग के मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन कर बिहार में परिवर्तन की लहर को कसकर हवा दिया है. वहीं दूसरी ओर गया जिले के जदयू अध्यक्ष और टिकारी विधानसभा क्षेत्र से महगठबंधन के प्रत्याशी अभय कुशवाहा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए कहते है कि गया जिले की सभी सीटों पर महागठबंधन को लोगों का अपार समर्थन मिला है अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. परिणाम आयेगा तो सभी को पता चल जाएगा. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित-महादलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भाजपा की जुमलेबाजी को चुनाव में नकार दिया है. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है. लोजपा के प्रदेश संगठन सचिव और अतरी विधानसभा क्षेत्र से एनडलीए प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह ने अपनी जीत के प्रति सौ फीसदी आश्वस्त होकर कहते है कि गया जिले के सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है. बिहार में एनडीए की सरकार बनना पूरी तरह से निश्चित है. गया जिले में जनता पूरी तरह से चुनाव में एनडीए के साथ थी. राजद के गया जिला अध्यक्ष प्रो. राधेश्याम प्रसाद का दावा है कि जिले के सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. दलितों-पिछड़ो-अल्पसंख्यकों को बुलंद अवाज देने वाले लालू यादव की अगुवायी में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. जदयू के वरिष्ठ नेता लालजी प्रसाद का दावा है कि गया जिले के सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. हर नेताओं के अपने-अपने दावे है. लेकिन इन दावों में कितनी राजनीतिक समक्ष है, यह तो मतदाताओं के दिये गए मत के परिणाम ही बता देगें कि कौन नेता कितने पानी में हैं.■

डेंगू को हल्के में नहीं लें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.


डॉ.राणा एस.पी. सिंह
MBBS, MD (PMCH) DA, RCGP (London)

पटना के बुद्धा कॉलोनी से डॉ. वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. राणा एस.पी. सिंह से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि इस बार 275 डेंगू मरीजों का ईलाज किया। डेंगू की उत्पत्ती के बारें में उन्होंने बताया कि कहीं भी साफ पानी में इस मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। मसलन कूलर, छत पर रखा हुआ टायर फूलदान, गमला इत्यादि में भी जमा हुआ पानी में हो सकता है। जिसका उपाय ब्लीचिंग पाउडर या जला हुआ मोबिल डालना भी है। ये भ्रांति है कि यह मच्छर दिन में ही काटता है, आप खुद सोंचिए क्या मच्छर समय देख कर काटता है। इसलिए आप सुरक्षित रहने के लिए रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल, व दिन में फुलबांह के पैंट शर्ट का ज्यादा प्रयोग करें। डॉ. राणा ने इसके लक्षणों में तेज बुखार आना, सर्दी खांसी, टायफायड के साथ भी आ सकता है के अलावा, जी मचलाना या उल्टी की इच्छा, चेहरे पर लाल चकते का निकलना है स्थिति खराब होने पर पेशाब, पैखाना और नाक से खून का रिसाव भी इसके लक्षणों में शामिल है। लेकिन आप इसके प्राइमरी लक्षणों में सिर पकड़ना, और आंखों में दर्द को मुख्य लक्षण मान सकते हैं। इस समस्या का इलाज एन्टीबायोटिक टेबलेट नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अपना इलाज कुशल चिकित्सक से ही करायें। नीम हकीम के चक्कर में न पड़ें। यदि आप कोई टेबलेट ले रहे हैं तो पारासिटामोल ही लें कोई अन्य मिक्सड कम्पेजिशन का टेबलेट न लें। शुरूआती इलाज में पपीते के पते को धोकर बारीक टुकड़े को मिक्सी में पिस कर रस निकालकर तीन कप दिन में लें साथ ही एलोवेरा 20 एमएल दो बार तथा अनार का रस 6 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, परन्तु कुशल चिकित्सक से तुरंत सलाह अवश्य लें ■ - भारती

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

झारखंड

# चिराग तले अंधेरा

झारखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का स्रोत मुख्यतः लोहा, कोयला, बाक्साइट ,ग्रेफाइट, माइका, चूना पत्थर, यूरेनियम समेत कई खनिज संपदाओं पर आधारित है. खनिज संपदाओं की प्रचुरता के कारण यहां उद्योग धंधों का जाल चारों ओर फैला हुआ है. इतनी खनिज संपदाओं की प्रचुरता के बावजूद भी यहां आज बेरोजगारी चरम पर है. झारखंड से प्रतिदिन हजारों युवक युवतियां रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं. बेरोजगारी इस राज्य की गंभीर समस्या बन गई है. आए दिन झारखंड छोड़ दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हुए लोगों की भीड़ ट्रेनों में देखने को मिलती है.

दिवाकर तिवारी feedback@chauthiduniya.com

झारखंड अपनी स्थापना का 15वां वर्षगाठ मना रहा है. गठन के 15 वर्ष बाद भी राज्य का विकास नगण्य हुआ है. वर्तमान रघुवर सरकार के समक्ष कई चुनौतीयां मुंह बाऐं खड़ी है जिसमें मुख्यतः युवाओं को रोजगार, मजदूरों का पलायन, अपराध नियंत्रण,और नक्सल जैसे गंभीर कई मुद्दे है. जिसका समाधान यहां कि जनता जल्द से जल्द चाहती हैं. राज्य में खनिज सम्पदा का प्रचुर भंडार है. जिससे राज्य का समुचित विकास संभव है. फिर भी यह राज्य अन्य राज्यों के तुलना में गरीब और पिछड़ा हुआ है. जल, जंगल,जमीन से भरा पूरा यह राज्य आज अपनी ही पहचान को तरस रहा है. इस राज्य के भुगर्भ से निकलने वाले कोयला से कई राज्यों के बिजली तापघर चलते है और कितनों राज्य एवं देशों को रोशनी देते है. लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहावत झारखंड राज्य के साथ सटीक बैठती है.आजादी के 6 दशक पश्चात आज भी झारखंड के सैकड़ों गांव में बिजली लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है. झारखंड राज्य गठन के साथ ही राज्य के लोगों में यह उम्मीद जगी की अब उनका चौतरफा विकास हो जाएगा. लेकिन यह विडम्बना है कि 15 वर्षों में 9 मुख्यमंत्री बने और 4 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा. वर्तमान में झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है. इस सरकार के भी लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है, देखना यह है कि यह सरकार लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरती है. राज्य कि जनता को पीनें के लिए शुद्ध जल तक अभी तक सरकार मुहैया नहीं करा पाई है. जिन आदिवासीयों और आदिम जनजातियों के बेहतर भविष्य और विकास के लिए झारखंड अलग राज्य बना उनके ही रहनुमा उनको लूटने का कार्य कर रहे है.

झारखंड का आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का स्त्रोत मुख्यतः लोहा, कोयला, बाक्साइट ,ग्रेफाइट, माइका, चूना पत्थर, यूरेनियम समेत कई खनिज संपदाओं पर है. खनिज संपदाओं की प्रचुरता के कारण यहा उद्योग धंधे का जाल चारों ओर फैला हुआ है. इतने खनिज संपदाओं के प्रचुरता के बावजूद भी यहां आज बेरोजगारी चरम पर है. झारखंड से प्रतिदिन हजारों युवक युवतियां रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करते है. बेरोजगारी इस राज्य की गंभीर समस्या बन गई है. आय दिन झारखंड छोड़ दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हुए लोगों की भीड़ ट्रैनों में देखने को मिलती है. जबकि राज्य में उद्योग धंधे और खनिज की प्रचुरता है लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण यहां के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और लोग पलायन को ही अपना सुनहरा भविष्य मान रहे है. आखिर कब होगा झारखंड के लोगों के मूलभूत समस्याओं का निदान इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है. फिलवक्त झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार है जिससे लोगों में उम्मीद जगी है कि उनका कुछ भला होगा और यह सरकार कुछ जनोपयोगी कार्य करेगी, लेकिन वास्तविकता में सरकार कि मंशा क्या है यह लोगों को समझ से परे है.

## क्यों प्रसिद्ध रहा झारखण्ड

जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो इसके साथ दो और उतराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था. जहां आज विकास की गंगा बह रही है. झारखंड राज्य गठन के बाद ही घोटालों के लिए मशहूर रहा, उसी राज्य में पहली बार कोई निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए थे. यह इस राज्य कि दुर्दशा बयां करने के लिए काफी है कि इस राज्य के अधिकतर विधायक एवं पूर्व विधायक पर हार्स ट्रैडिंग, आय से अधिक संपत्ति एवं घोटालें का केस चल रहा है. जिसकी जांच सीबीआई, एवं अन्य एजेंसी के द्वारा की जा रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप साही, कमलेश सिंह समेत कई मंत्रीयों का नाम पर घोटाले का केस चल रहा है. झारखंड के लिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यहां जनता से अधिक नेता का विकास हुआ है. वन,खनिज एवं रत्न गर्भा से परिपूर्ण इस राज्य में जिस पार्टी की सरकार बनी या पद पर बैठने का अवसर मिला,सभी ने राज्य संपदा को खूब लूटा खसोटा. खूब बंदरबाट की और अपनी तिजोरी को भरा. राज्य की जनता और विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. जिसके कारण नवोदित राज्य सर्व सम्पन्न होकर भी विकास के पथ पर पिछड़ गया सत्ता पर बैठे लोग सिर्फ इसका दोहन करते रहे.

झारखंड राज्य जहां अपने गठन का 15 वी वर्षगांठ मना रहा है वहीं यहां के निवासी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य बना इसको अलग करवाने में कितने लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी, भले ही एक लंबे संघर्ष के उपरांत यहां की जनता को उनका राज्य मिल गया लेकिन उनका अस्तित्व एवं अस्मिता का संकट ज्यों का त्यों बरकरार है.

झारखंड की पहचान वहां के प्राकृतिक संपदाओं से रही है. लेकिन राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह राज्य खूब प्रसिद्ध हुआ. इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर किया गया. बिहार विभाजन के बाद जब झारखंड एक नया राज्य बना तब यहां कि जनता ने दीपावली मनाया था. उन्हें यह आशा थी, कि अब उनका विकास होगा. एकीकृत बिहार के समय उन इलाकों का समुचित विकास नहीं हुआ था और यह इलाका बहुत पिछड़ा था. राज्य अलग होने के बावजूद भी राज्य के लोगों का विकास तो नहीं हुआ लेकिन राज्यों के नेताओं का भरपूर विकास हुआ. वैसे झारखंड राज्य अपनी स्थापना का 15 वी वर्षगांठ मना रहा है लेकिन यह देखना है कि कितने सालों बाद यहां कि जनता झारखंड अलग होने का सच्ची सालगिरह मनाती है.■

feedback@chauthiduniya.com









झारखंड की पहचान वहां की प्राकृतिक संपदाओं से रही है. लेकिन राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह राज्य खूब प्रसिद्ध हुआ. इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर दिया गया. बिहार विभाजन के बाद जब झारखंड एक नया राज्य बना तब यहां कि जनता ने दीपावली मनाया था. उन्हें यह आशा थी कि अब उनका विकास होगा. एकीकृत बिहार के समय उन इलाकों का समुचित विकास नहीं हुआ था और यह इलाका बहुत पिछड़ा था. राज्य अलग होने के बावजूद भी राज्य के लोगों का विकास तो नहीं हुआ लेकिन राज्यों के नेताओं का भरपूर विकास हुआ.

पृष्ठ 17 का शेष

# उम्मीदों से लदी होगी नई सरकार



बिहार के बच्चों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाय. उत्तम बाबू का मानना है कि रोजगार देने वाली शिक्षा का भी बिहार में काफी स्कोप है. दुर्भाग्य से किसी भी सरकार ने इस दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया. वे कहते हैं कि नई सरकार को इस बारे में खास ध्यान देना चाहिए कि बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके. उत्तम बाबू कहते हैं कि बहुत राजनीति हो गई अब सब को मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. बिहार आगे बढ़ा तो सारा देश आगे बढ़ेगा. इसके बाद लोगों ने एक सुर से बिजली में सुधार की बात कही. हालांकि लोग मानते हैं कि पहले की तुलना में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है पर इसे काफी नहीं माना जा सकता है. अभी बहुत से ऐसी जगहें जहां बिजली के तार पहुंचने अभी बाकी हैं. साथ ही बिजली लोगों को अधिक से अधिक मुहैया, इस बात की जिम्मेदारी सरकार को निभानी होगी. नीतीश सरकार के आलोचक और पेशे से वकील अमरेश तिवारी कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं जब लोग कहते हैं कि बिजली की स्थिति सुधरी है. आप बिहार के किसी भी शहर में चले जाइये जनरेटर का शोर आपको ढंग से बात नहीं करने देगा. इंवर्टर की बिक्री में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. सुनने में आया है कि बिजली में सुधार का आया पैसा भी उपयोग में नहीं लाया जा सका. खैर अब मैं पुरानी बात दोहराना नहीं चाहता बस इतना चाहता हूं कि सरकार किसी की भी बने बिजली पर दूरगामी सोच के साथ काम शुरू करे. हमारा अपना उत्पादन हो और हम दूसरे के भरोसे न रहे. किसानों को कम से कम सिंचाई के लिए आठ घंटा बिजली मिले इसकी भी व्यवस्था नई सरकार को करनी चाहिए. बी कॉम की पढ़ाई कर रहे दीपक गुप्ता कहते हैं कि नई सरकार को रोजगार के नए अवसर बढ़ाने का काम तेजी से करना चाहिए. युवाओं को रोजगार देना जरूरी है नहीं तो फिर किसी भी विकास का कोई मतलब नहीं है. देखा जाए तो साफ है कि सूबे में बनने वाली नई सरकार से राज्य के लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं. देखना है कि जनता की अपेक्षाओं पर नई सरकार कितनी खरी उतरती है.■

feedback@chauthiduniya.com



# दोहरी चुनौती से जूझती कामकाजी महिलाएं

महिलाओं को यह समझना चाहिए कि बदलते परिदृश्य और आधुनिक जीवनशैली की एक आवश्यकता है कि वह घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ आफिस की जिम्मेदारी भी संभालें. अक्सर यह देखा जाता है कि अगर कोई महिला कार्यालय के किसी सहयोगी से परामर्श लेती है, किसी बहस में गर्मजोशी से भाग लेती है तो पुरुष उस महिला के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं. उन्हें यह भ्रांति होने लगती है कि वह महिला उनमें रूचि ले रही है. अतः वह इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं. कभी-कभी वह अनुचित प्रयास भी करते हैं.

राधिका feedback@chauthiduniya.com

तेजी से बदले आर्थिक समीकरणों ने नारी को दहलीज के बाहर कदम रखने को प्रेरित किया और घर के हर व्यवहार को चुस्त-दुरुस्त रखते हुए नारी ने बाहरी दुनिया के कार्य व्यवहार जमाने में भी उतनी ही दक्षता का परिचय दिया. समाज में अब एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है. इसमें और चीजों के साथ ही महिलाओं की दशा भी सुधरी है. आज की महिला हर क्षेत्र में पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही है और सफलता के नित नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है. लेकिन संयोगवश सामाजिक विकास के क्षेत्र में हुआ बदलाव पुरुषों की मानसिकता को नहीं बदल पाया है. हकीकत में पुरुष मानसिक स्तर पर इस बदलाव को सहज रूप में स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं. जिससे कामकाजी महिलाओं की आफिसों में मुश्किलें बढ़ रही हैं.

महिलाओं को यह समझना चाहिए कि बदलते परिदृश्य और आधुनिक जीवनशैली की एक आवश्यकता है कि वह घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ आफिस की जिम्मेदारी भी संभालें. अक्सर यह देखा जाता है कि अगर कोई महिला कार्यालय के किसी सहयोगी से परामर्श लेती है, किसी बहस में गर्मजोशी से भाग लेती है तो पुरुष उस महिला के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं. उन्हें यह भ्रांति होने लगती है कि वह महिला उनमें रूचि ले रही है. अतः वह इसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं. कभी-कभी वह अनुचित प्रयास भी करते हैं. ऐसे में महिला यदि शिकायत भी करे, तो गलत उसे ही ठहराया जाता है. लेकिन ऐसी किसी भी अवस्था से महिलाओं को पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए. इस बारे में हमने कुछ कामकाजी महिलाओं की राय भी ली.

इस बारे में अनामिका सिंह, जिनका अपना हॉस्पीटल है, का कहना है कि घर और बाहर दोनों जगह संभालना आसान नहीं है. इन सारी चीजों को संभालने के लिए धैर्य रखना बहुत ही जरूरी होता है. एक कामकाजी महिला से उसके ससुराल वालों को ज्यादा अपेक्षा होती है. इसके अलावा बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बरकरार रखना भी कामकाजी महिलाओं के लिए चिंता का विषय बना रहता है. जहां तक बात लड़कियों के एक्स्प्लॉयटेशन की करें तो ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है. ऐसे में लड़कियों को चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें. किसी को भी बिना वजह स्पेस न दें. क्योंकि इसी जगह से लड़कियों के लिए समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आज लड़कियां जूझती रहती हैं.

इस विषय में पल्लवी लाला, जो कि पेशे से लॉयर हैं, का कहना है कि महिला अगर कामकाजी हो तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही जुड़ जाती हैं. ऑफिस तो देखना ही होता है साथ-साथ घर के भी सारे काम करने होते हैं. और ऐसे में मजबूरन हमें दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है. इतना ही नहीं कामकाजी होने की वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है. कम उम्र में ही ज्यादातर कामकाजी महिलाओं में बीमारियां बढ़ने के बारे में डॉ हीमा चरण का कहना है कि महानगरीय जीवन का दबाव, नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाने की मजबूरी और शादी के बाद रहन-सहन में आने वाला बदलाव ही इसके लिए जिम्मेदार है. महानगरों में खासकर युवा वर्ग की ज्यादातर महिलाएं नौकरीपेशा हैं. दफ्तर के दबाव के साथ ही उनको घर-परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है. यह दोहरा तनाव कम उम्र में ही डायबिटीज और थायरायड जैसी बीमारियों को न्योता देता है. इसके अलावा महानगरीय जीवन में रोजमर्रा का तनाव ही इसकी प्रमुख वजह है. महिलाओं को दफ्तर और घर संभालने के लिए दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है. इससे तनाव बढ़ता है और बीमारियां पैदा होती हैं. नौकरी करने और घर संभालने वाली ज्यादातर महिलाएं इन दोनों बीमारियों के अलावा मानसिक अवसाद, कमर दर्द, मोटापे और दिल की बीमारियों से जूझ रही हैं. शादी भी इस समस्या की एक प्रमुख वजह है. शादी से पहले तक तो कामकाजी युवतियों को घर संभालने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता. घर पर उनकी मां या दूसरे लोग बाकी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं. दूसरे शहरों में हॉस्टल में रहने की वजह से घर संभालने का दबाव कम रहता है. लेकिन शादी होते ही उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है. उनको अपने जीवन में रहन-सहन संबंधी बदलाव करने पड़ते हैं.

कामकाजी महिलाओं की समस्या पर जया मिश्रा, जो कि एक सफल महिला नेता हैं, उनका कहना है कि हम एक दोहरी जिंदगी जीते हैं. और इसे संभाल पाना बहुत हीं मुशकिल होता है. ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार का सपोर्ट. कामकाजी महिला को हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए. जब भी महिला अपने घर की दहलीज से बाहर निकल कर काम करती है तो उसे अपने व्यक्तित्व में गरिमा रखनी चाहिए. जया आगे कहती हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन को किसी मजबूरी वश ऐसा करना पड़ जाता है जो वो नहीं करना चाहती. ऐसे में गलती उस लड़की की नहीं बल्कि उस इंसान की होती है, जो उस लड़की के मजबूरी का फायदा उठाता है. साथ ही दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मर्यादा की सीमा को न लांघें और न ही ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे दूसरा व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाए.■



कामकाजी महिलाओं की समस्या पर जया मिश्रा, जो कि एक सफल महिला नेता हैं, उनका कहना है कि हम एक दोहरी जिंदगी जीते हैं. और इसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार का सपोर्ट. कामकाजी महिला को हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए. जब भी महिला अपने घर की दहलीज से बाहर निकल कर काम करती है तो उसे अपने व्यक्तित्व में गरिमा रखनी चाहिए.



बेगूसराय

# कई मायनों में अनूठा है बेगूसराय

बेगूसराय में सर्वप्रथम घटित होने वाली इन दिलचस्प घटनाओं के बारे में पहली घटना 1957 की है. अवसर था बिहार विधानसभा के चुनाव का. उस समय बेगूसराय उत्तर एवं बेगूसराय दक्षिण विधानसभा सीट हुआ करती थीं. बेगूसराय दक्षिण सीट पर कांग्रेस ने प्रसिद्ध नेता सरयुग प्रसाद सिंह को एवं भाकपा ने ख्याति प्राप्त नेता चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बना कर चुनाव मैदान में उतारा था. इस सीट पर कांग्रेस एवं भाकपा दोनों दलों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी.




सुरेश चौहान feedback@chauthiduniya.com

जिस बिहार की धरती ने देश को पहला गणतंत्र दिया, उसी बिहार की धरती पर देश में सर्वप्रथम बूथ केप्चरिंग की घटना घटी. लिच्छिवी ने गणतंत्र दिया तो बेगूसराय ने बूथ केप्चरिंग की घटना को अंजाम दिया. बेगूसराय में न सिर्फ देश का पहला बूथ केप्चरिंग कांड हुआ बल्कि आजाद भारत का पहला जेल ब्रेक कांड भी बेगूसराय में ही हुआ. आजादी के बाद प्रथम बार बेगूसराय में ही जमींदार की 250 एकड़ जमीन पर भूमिहीनों ने जबरन कर लिया. उतना ही नहीं थोक भाव में अवैध बम एवं गोला बारूद निर्माण का पहला केंद्र भी बेगूसराय ही बना.

दूसरी घटना 1971 की है, बेगूसराय के चैरिटी ट्रस्ट नावकोठी के पास हजारों एकड़ जमीन थी. जबकि उसी क्षेत्र के हजारों परिवारों के पास झोपड़ी खड़ी करने के लिए भी भूमि नहीं थी. शिक्षक नेता गणेश प्रसाद सिंह एवं भाकपा के वरिष्ठ नेता ललन प्रसाद सिंह कहते हैं कि 1971 तक बेगूसराय में भाकपा जन आंदोलन खड़ा कर अपना पैर जमा चुकी थी. गरीबों, मजदूरों एवं भूमिहीनों के हक की लड़ाई लड़ते हुए वह इस वर्ग का मसीहा बन चुकी थी. भाकपा की योजनानुसार क्षेत्र के रजाकपुर सहित पड़ोस के अन्य गांवो के हजारों भूमिहीन, गरीब, मजदूरों ने चैरिटी ट्रस्ट की 250 एकड़ भूखंड पर धावा बोल दिया और उसपर भाकपा का लालझंडा एवं बैनर गाड़कर जबरन कब्जा कर लिया शायद आजाद भारत की यह पहली घटना थी.


चितरंजन प्रसाद सिंह | ललन प्रसाद सिंह | राजेंद्र शर्मा | सुशील मिश्र | सुशील कुमार सिंह

आइए जाने बेगूसराय में सर्वप्रथम घटित होने वाले इन दिलचस्प घटनाओं के बारे में पहली घटना 1957 की है, अवसर था बिहार विधानसभा के चुनाव का इस समय बेगूसराय उत्तर एवं बेगूसराय दक्षिण विधानसभा सीट हुआ करता था. बेगूसराय दक्षिण सीट पर कांग्रेस ने नामचीन नेता सरयुग प्रसाद सिंह को एवं भाकपा ने ख्याति प्राप्त नेता चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बना कर चुनाव मैदान में उतारा था. इस सीट पर कांग्रेस एवं भाकपा दोनों दलों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी. जिले के बुजुर्ग समाजवादी एवं हम पार्टी के नेता चितरंजन प्रसाद सिंह कहते हैं कि दोनों दल किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहते थे. मतदान चल रहा था, पर यह क्या? कुछ दबंग लोगों का एक झुंड अवैध बम-बंदूक से लैश मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही रामपुर कचहरी मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और पीठासीन पदाधिकारी को धमका कर बूथ केप्चर कर मतपत्रा एक प्रत्याशी के मतपेटी में डाल देते हैं. दबंगों का यह झुंड इतने से ही संतुष्ट नहीं होता है और मटिहानी तथा नयागांव थाना क्षेत्रा के लगभग 40 मतदान केंद्रों पर पहुंच कर बूथ केप्चर कर अपने प्रत्याशी के मतपेटी में मतपत्रा डाल देता है. इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सरयुग प्रसाद सिंह विजयी हुए और तत्कालीन सरकार में बिना विभाग के मंत्री बनाए गए. जबकि भाकपा के कद्दावर नेता चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह द्वितीय स्थान पर रहे,और यहीं से प्रारम्भ होता है मटिहानी व नयागांव थाना क्षेत्रा के कुछ गांवो में अवैध बम व गोला-बारूद के निर्माण की कहानी. कांग्रेसी नेता सुशील मिश्र बताते हैं कि राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता, अपराधियों के गुटो द्वारा वर्चस्व स्थापित करने की ललक एवं गांजा तस्करों द्वारा अवैध बम एवं गोले-बारूद की मांग काफी बढ़ने लगी और क्षेत्रा में इसका निर्माण कुटीर उद्योग का रूप ले लिया गया. बन्दूक फैक्ट्री मुंगेर के सेवानिवृत कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित बम एवं हथियारों की मांग बिहार के पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल के अपराधियों द्वारा की जाने लगी.

कांग्रेसी नेता सुशील मिश्र बताते हैं कि राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंद्विता, अपराधियों के गुटों द्वारा वर्चस्व स्थापित करने की ललक एवं गांजा तस्करों द्वारा अवैध बम एवं गोले-बारूद की मांग काफी बढ़ने लगी और क्षेत्र में इसका निर्माण कुटीर उद्योग का रूप ले लिया गया. बन्दूक फैक्ट्री मुंगेर के सेवानिवृत कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित बम एवं हथियारों की मांग बिहार के पड़ोसी राज्यों एवं नेपाल के अपराधियों द्वारा की जाने लगी.

तीसरी घटना 1986 की जेलब्रेक कांड की है. भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र शर्मा एवं सुनिल कुमार सिंह बताते हैं कि बेगूसराय जेल में दो खूंखार अपराधी ग्रुप के सरगना बंद थे. एक गुट का सरगना अपने प्रतिद्वंदी गुट के सरगना की हत्या जेल में ही करने की योजना बनाई थी. जेल के अन्दर दही में रखकर पिस्तौल एवं गोली सरगना को पहुंचाया गया था. योजना के अनुसार कुछ अनजान अपराधी दूसरे गुट के सरगना से मिलने जेल गेट पर पहुंचा, गार्ड जेल के अन्दर का गेट खोलकर बाहरी गेट के पास उसे लाया अजनबी को देखकर वह उससे मिले बिना वापस लौटने लगा, इसी क्रम में घात लगाये पहले गुट का सरगना ने अपने प्रतिद्वंदी को गोली मारकर हत्या कर दी और गार्ड को भी गोली मारकर मुख्य गेट की चाभी से गेट खोलकर फरार हो गया. गेट खुला देख कुछ अन्य दुर्दान्त अपराधी भी भाग निकले. जेल से कुछ दूरी पर खड़ी जीप पर सवार होकर फरार अपराधी सरगना एवं अजनबी अपराधी भाग निकले. घायल गार्ड की मृत्यु इलाज के दौरान हो गयी.■

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेंडस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

# अब सबकी अटकी हैं चुनाव परिणाम पर निगाहें

**2015 के विधानसभा चुनाव को लेकर संपन्न तमाम चुनावी सभाओं में तरह-तरह से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास नेताओं की ओर से किया गया. मगर दो प्रमुख राजनीतिक दल की चर्चा जोरों पर है. कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल के निशाने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में रहें, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को स्वार्थबंधन की संज्ञा देकर बिहार में विकास के लिए जज्बे वाली सरकार बनाने की अपील लोगों से की. उधर तीसरे मोर्चे ने महागठबंधन को विश्वासघाती तो एनडीए को ठगेरा पार्टी कह कर वोट अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास किया हैं. जबकि कुछ स्थानों पर निर्दलीयों ने अपने पक्ष में मतदान की गुहार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ीं.**

वाल्मीकि कुमार

विधानसभा चुनाव को लेकर जारी शोर पर अब विराम लग गया है. चुनावी सभाओं से गुलज़ार रहने वाला मैदान में अब फिर से विरानी छाने लगी है. न मूंगफली का खोंमचा और न ही नेताओं का काफिला मैदानों में नजर आ रहा हैं. चुनावी नारों से गूंज रहा वातावरण में अब संनाटा पसरा है. जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पार्टी कार्यकर्ता भी फिलहाल विरामावस्था में नजर आने लगे है. परंतु इन सब के बीच चुनाव परिणाम को लेकर आंकडों की बाजीगरी जोरो पर हैं. कोई महागठबंधन की सरकार बनाने में लगा है, तो कोई बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत की बात कर रहा है. कोई तीसरा मोर्चा तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी को चुनावी गणित में गड़बड़ी करने की बात भी कर रहा है. लेकिन अब तक कोई ताल ठोक कर यह कहने का साहस नहीं जुटा रहा है कि अबकी बार किस सीट का ताज किसके सिर पर चढ़ने वाला है. जाति –पार्टी, अगड़ा–पिछड़ा से लेकर विकास और विनाश तक का ढ़ोल पिटने वालों की जुबाने भी खामोश है. खेत का मेड से कंधा पर कुदाल लेकर चलने वाला किसान और दैनिक मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करने वाला मजदूर अब चुनावी दुनिया से बाहर आ चुका है. इस तबका को अब भी पूरा यकीन है कि न खेत को पानी और न समय पर खाद, बीज मिलने वाला है. बेरोजगार बेटा को परदेश नौकरी करना है और बिमारी की हालत में घर की जमा पूंजी बेच कर इलाज कराने की विवशता भी जान छोड़ने नहीं जा रही है. बेटी की विदाई से लेकर पढ़ाई तक का खर्च पूर्ववत ढ़ोना है. जब चुनावी घोषणा की चर्चा होती है, तब उनका तेवर देखने लायक नजर आ रहा है. नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ लोग कहते है कि सरकार चाहे किसी की भी बने अपने भाग्य के भरोसे ही रहना है. कांग्रेस का 40 साल, राजद का 15 साल और एनडीए का 10 साल जब गरीबों की किस्मत नहीं बदल सका तो अब पैसों के बूते चुनाव लड़ने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है. कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है, कि अब गरीबों को कोई देखने वाला नहीं हैं. मंच से भाषण अच्छा लगा जिसे जी में आया मतदान कर दिया. मगर समस्या निदान की उम्मीद न किया है और न करने में ही भलाई है. तकरीबन यहीं0सोच अधिकांश लोगों की चुनाव को लेकर वर्तमान में चर्चा का केंद्र बना है.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

नाम नहीं छापने की शर्त पर कुछ लोग कहते है कि सरकार चाहे किसी की भी बने अपने भाग्य के भरोसे ही रहना है. कांग्रेस का 40 साल, राजद का 15 साल और एनडीए का 10 साल जब गरीबों की किस्मत नहीं बदल सका तो अब पैसों के बूते चुनाव लड़ने वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है. कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार की जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है, कि अब गरीबों को कोई देखने वाला नहीं हैं. मंच से भाषण अच्छा लगा जिसे जी में आया मतदान कर दिया. मगर समस्या निदान की उम्मीद न किया है और न करने में ही भलाई है. तकरीबन यही सोच अधिकांश लोगों की है.

सीतामढ़ी के 8 और शिवहर के 1 विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर तकरीबन दो दर्जन राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं की चुनावी सभा हुई हैं. उनमें एनडीए की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद हीरा माझी, राजीव प्रताप रूढी, मनोज तिवारी, रालोसपा से केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रेमचंद्र मिश्र, राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, सांसद सह सिनेमा कलाकार नगमा, राजबब्बर, राजद के लालू प्रसाद, डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह, मीसा भारती, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री रघुनाथ झा और जन अधिकार पार्टी की ओर से सांसद पप्पू यादव समेत अन्य शामिल हैं. उन तमाम नेताओं ने अपने–अपने गठबंधन व पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ा हैं. कमोवेश तमाम नेताओं के चुनावी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ भी रही हैं. तालिया भी बजी और जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया. मगर सबकुछ के बाद भी वोट का बटन किसके पक्ष में दबा इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है.

2015 के विधानसभा चुनाव को लेकर संपन्न तमाम चुनावी सभाओं में तरह–तरह से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास नेताओं की ओर से किया गया हैं. मगर दो प्रमुख राजनीतिक दल की चर्चा जोरों पर हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल के निशाने पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में रहें, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को स्वार्थबंधन की संज्ञा देकर बिहार में विकास के लिए जज्बा वाली सरकार बनाने की अपील लोगों से की. उधर तीसरा मोर्चा ने महागठबंधन को विश्वासघाती तो एनडीए को ठगेरा पार्टी कह कर वोट अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास किया हैं. जबकि कुछ स्थानों पर निर्दलीय ने खुद को चुनावी दल से अलग होने की बात कहते हुए अपने पक्ष में मतदान की गुहार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं. अब देखना हैं कि सीतामढ़ी व शिवहर क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधित्व किसे सौंपने का मन बनाया हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

**चर्चा हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव होता है तो एनडीए व महागठबंधन ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता है. कारण कि एक ओर यादव वोटों पर पकड़ रखने वाला पूर्व विधायक मजबूती से डटा रहा, तो दूसरी ओर भूमिहार बिरादरी के माधव के समर्थन में भी उनकी पत्नी जान्हवी की अगुवाई में जमात ने चुनावी कसरत में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं.**

# कई सीटों पर बदल सकता है चुनावी समीकरण

वाल्मीकि कुमार

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव की तिथि निर्धारित होने के साथ ही सीतामढ़ी जिले में टिकट के दावेदारों के बीच उफान शुरू हुआ. जब पार्टी नेताओं ने टिकट का वितरण शुरू किया तब कई सीटों पर सेंबल को लेकर तर्कवितर्क का दौर शुरू हुआ. चर्चा है कि नामांकन प्रक्रिया का श्री गणेश होने के साथ ही दलगत नेताओं में विदेश का वीजा–ोपण शुरू होने लगा. कुछ ने खुलकर बागी तेवर अख्तियार कर लिया तो कुछ ने पार्टी नेताओं द्वारा थोपे गये प्रत्याशी को चुनाव मैदान में सबक सिखाने की ठानी. वह समय भी आया जब नाम वापसी के बाद जिले के कुल 8 विधानसभा सीटों के लिए तकरीबन सवा सौ से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे रहे हैं. जब चुनाव प्रचार अभियान गति पकड़ना शुरू किया तब बेटिकट कुछ पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अपना चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी में लग गये.

चल रही चर्चाओं पर यकीन करे तो सीतामढ़ी जिले के 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा सीटों पर बतौर बागी प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी हैं. उनमें कई की चुनावी स्थिति संतोषजनक भी होना बताया जाता है. 23– रीगा विधानसभा सीट की अगर चर्चा करें तो इस क्षेत्र से डेढ़ दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जिनमें मुख्य रूप से एनडीए से भाजपा के मोतीलाल प्रसाद का सीधा मुकाबला महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना से है. महागठबंधन के वोट बैंक का अल्पसंख्यक मत में बिखराव की संभावना सपा प्रत्याशी ताजुद्दीन हैदर खां से होने की बात कही जा रही हैं. परंतु लगातार क्षेत्र में प्रयासरत टुन्ना को अबकी बार व्यापक समर्थन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. 24 – बथनाहा विधानसभा सीट से एक दर्जन प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. मगर इस सीट पर महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र राम का मुकाबला एनडीए के भाजपा प्रत्याशी दिनकर राम से होना हैं. इसके अलावा 25 – परिहार विधानसभा सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हाथ–पांव मार रहे हैं. इनमें महागठबंधन से राजद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहें प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे का मुकाबला एनडीए की भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी से होने की बात कही जा रही हैं. मगर इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी का खेल बिगाड़ने के लिए उनके स्वजातीय जन अधिकार पार्टी की प्रत्याशी सरिता यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी हैं. वहीं महागठबंधन के अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव की दिशा में कांग्रेस का बागी सपा प्रत्याशी मो. शम्स शाहनवाज अंतिम पल तक क्षेत्र में जमे रहे है. 26– सुरसंड़ विधानसभा सीट से कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में कसरत करते रहें हैं. उनमें एनडीए से हम की टिकट पर शाहिद अली खान तो महागठबंधन से राजद की टिकट पर सैयद अबुदोजाना दो–दो हाथ करते रहे हैं. जबकि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व राजद विधायक जयनंदन प्रसाद यादव व जेल की सलाखों में कैद अमित कुमार उर्फ माधव चौधरी ने भी भरपूर चुनावी कसरत किया है. चर्चा हैं कि अगर अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव होता है तो एनडीए व महागठबंधन ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता हैं. कारण कि एक ओर यादव वोटों पर पकड़ रखने वाला पूर्व विधायक मजबूती से डटा रहा, तो दूसरी ओर भूमिहार बिरादरी के माधव के समर्थन में भी उनकी पत्नी जान्हवी की अगुवाई में जमात ने चुनावी कसरत में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं. 27 – बाजपट्टी विधानसभा सीट से सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं. जिसमें एनडीए से रालोसपा की ओर से नया चेहरा रेखा कुमारी गुप्ता, महागठबंधन से जदयू की टिकट पर डॉ. रंजूगीता तो रालोसपा के बागी रविन्द्र कुमार शाही के बीच त्रिकोणात्मक चुनावी संघर्ष की चर्चा है. 28 – सीतामढ़ी विधानसभा सीट से कुल 15 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. जिसमें बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रहे भाजपा के सुनील कुमार पिंटू से मुकाबला के लिए महागठबंधन ने राजद की टिकट पर सुनील कुमार कुशवाहा को उतारा है. इस सीट से लोजपा की पूर्व विधायक नगीना देवी बतौर बागी वैश्य समर्थित प्रत्याशी के रूप में एनडीए के लिए चुनौती बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. वहीं महागठबंधन के लिए अल्पसंख्यक मतों का बिखराव निर्दलीय प्रत्याशी शाहीन प्रवीन ने भी किया है. 29 – रुन्नीसैदपुर सीट से 14 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने का काम किया. जिसमें एनडीए से रालोसपा की टिकट पर पंकज कुमार मिश्रा तो महागठबंधन से राजद की टिकट पर मंगीता देवी ने वोट बटोरने का प्रयास किया है. इस सीट से तीसरा मोर्चा की टिकट पर विधायक गुड्डी देवी ने बागी तेवर में अपना भाग्य आजमाया है. स्वजातीय के अलावा अन्य में पैठ की बदौलत चर्चा है कि चुनावी समीकरण की दिशा बदलने में बहुत हद तक कामयाब रही है. जबकि राजद प्रत्याशी को अपने स्वजातीय राजद के बागी लालबाबू यादव की सक्रियता परेशानी का सामना कराया है. 30– बेलसंड विधानसभा सीट से 18 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया हैं.

इस सीट से महागठबंधन की ओर से जदयू की टिकट पर सुनीता सिंह चौहान तो एनडीए की ओर से लोजपा की टिकट पर नसीर अहमद ने चुनावी कसरत की है. मगर वैश्य बिरादरी के भाजपा के बागी वैद्यनाथ प्रसाद का बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में आना दोनों ही गठबंधन के लिए घातक बताया जाता है. कुल मिलाकर अगर देखा जाये तो सीतामढ़ी में महागठबंधन और एनडीए कई सीटों पर दुविधा की स्थिति में नजर आ रही है. वैसे मतदान तक चुप्पी साधने वाले मतदाताओं की मंशा से पर्दा मतगणना के बाद ही उठ पायेगा. चल रही चुनावी चर्चा पर अगर यकीन करें तो महागठबंधन व एनडीए को कई सीटों पर टिकट बंटवारे में मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. फिलहाल मतगणना तक इन चर्चाओं पर कुछ कहना उचित नहीं होगा.■

गुड्डी देवी

गायत्री देवी

डॉ. रंजूगीता

बीएन प्रसाद

मोतीलाल प्रसाद

माधव चौधरी

डॉ. रामचंद्र पूर्वे

अमित कुमार टुन्ना

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

09 नवंबर–15 नवंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


## उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

## मुलायम के शपथ पत्र में पकड़ा गया झूठ! चुनाव आयोग ने पल्ला झाड़ा

# सरकार ने ग़लत बयाना ले लिया

***सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनकी पुत्रवधू सांसद डिम्पल यादव को भी एक पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामों में कथित विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है.***

प्रभात रंजन दीन

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देकर फंसे मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र में गलत सूचना देने के प्रकरण में भी फंसते दिख रहे हैं. उनकी पुत्रवधू डिम्पल यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ते समय जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव से पांच लाख रुपये ऋण लेने की बात कही है, जबकि मुलायम के शपथ पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है. इन दोनों शपथ पत्रों में से कोई एक झूठा है. एक ही परिवार के दो विरोधाभासी शपथ पत्रों का यह प्रकरण अदालत पहुंचने की दहलीज पर है. चुनाव आयोग ने इस मसले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है और इसे अदालत ले जाने की सलाह दी है. इस प्रकरण को चुनाव आयोग तक पहुंचाने वाली हैं डॉ. नूतन ठाकुर, जो निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी हैं. डॉ. ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कन्नी काट लेने के बाद अब अदालत का दरवाजा खटखटाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है.

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उनकी पुत्रवधू सांसद डिम्पल यादव को भी एक पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामों में कथित विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया है. डॉ. नूतन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल शपथपत्र में मुलायम ने कहा है कि उन्होंने किसी निजी व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया है. जबकि डिम्पल यादव ने दो अप्रैल 2014 को दाखिल अपने शपथपत्र के पृष्ठ 16 पर उल्लेख किया है कि मुलायम सिंह ने उन्हें पांच लाख रुपये ऋण दिया है और उनके पति अखिलेश यादव ने भी उन्हें तीन लाख रुपये का ऋण दिया है. डॉ. ठाकुर ने इसे विरोधाभासी करार देते हुए मुलायम से अनुरोध किया है कि वे इस बारे में चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण दें.

उधर, चुनाव आयोग ने इस प्रकरण से पल्ला झाड़ते हुए डॉ. नूतन ठाकुर को सलाह दी है कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनकी पुत्रवधू डिम्पल यादव द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में भरे गए शपथपत्र में एक-दूसरे से लिए लोन की सूचना में विरोधाभास के सम्बन्ध में वे सक्षम न्यायालय में जा कर शिकायत दायर करें. आयोग द्वारा भेजे पत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33-ए के तहत भरे जाने वाले फॉर्म 26 में कोई भी असत्य सूचना इस अधनियम की धारा 125-ए में दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 6 माह तक हो सकती है. आयोग ने कहा मुक़दमा रिटर्निंग अफसर द्वारा ही लिखवाया जा सकता था, पर 26 अप्रैल 2014 के पत्र द्वारा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय में यह मुक़दमा दर्ज करा सकता है, लिहाजा, डॉ. ठाकुर भी स्वयं सक्षम न्यायालय में शिकायत कर सकती हैं.

डॉ. ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए 22 अप्रैल 2014 को दाखिल अपने शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 14, क्रम 8 (i) पर अन्य व्यक्तियों को दिए ऋण शीर्षक पर शून्य अंकित किया है, जबकि डिम्पल यादव ने 02 अप्रैल 2014 को कन्नौज लोकसभा के लिए दाखिल शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 16 पर अन्य लोगों से प्राप्त ऋण में मुलायम सिंह द्वारा 5 लाख तथा अखिलेश द्वारा 3 लाख रुपये ऋण लेने का उल्लेख किया है. इन दोनों शपथ पत्रों में से कोई एक शपथ पत्र झूठा है. डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में सीधे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आयोग ने उल्टा मुझे ही कोर्ट जाने की सलाह दे दी है. ऐसा करके आयोग ने अपने औचित्य पर खुद ही सवाल खड़ा कर दिया है. ■

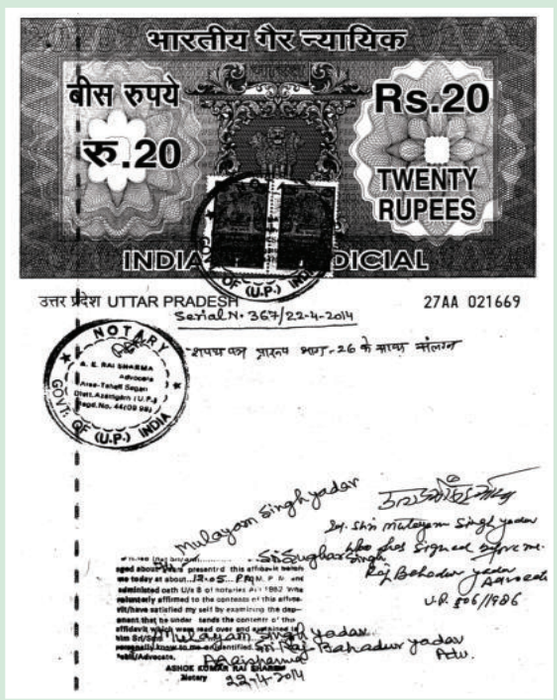

## फंसाने के बजाय खुद ही फंस गया विजिलेंस

मुलायम सिंह धमकी प्रकरण में एफआईआर से बौखलाई समाजवादी पार्टी सरकार आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को सतर्कता जांच के घेरे में लेने की कोशिश में खुद ही फंसती जा रही है. आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज करने वाले सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारी अब भागते फिर रहे हैं. अमिताभ ठाकुर की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले को कानूनी तौर पर साबित करने में सतर्कता (विजिलेंस) अधिष्ठान को अब दिक्कतें समझ में आने लगी हैं. अमिताभ के खिलाफ चल रही सतर्कता जांच पर अदालत की निगाह है. अदालत के संज्ञान में है कि सतर्कता जांच में सामने आई कथित आय से अधिक सम्पत्ति के ब्यौरे अमिताभ ठाकुर को ही नहीं दिए जा रहे हैं. इस जांच के प्रारंभ से ही ठाकुर लगातार यह कहते रहे हैं कि विजिलेंस इस मामले में राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और उन्हें आज तक यह नहीं बताया गया है कि एफआईआर में उनकी परिसम्पत्ति कैसे और किस आधार पर आंकी गई है. सतर्कता जांच की प्रक्रिया के तहत 28 अक्टूबर को अमिताभ ठाकुर को अनुसंधान अधिकारी दद्दन चौबे ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था. लेकिन अनुसंधान अधिकारी खुद ही दफ्तर से गायब हो गया. अमिताभ से उनके बच्चों और पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की शिक्षा पर हुआ व्यय, उनके और उनके परिवार वालों की चल और अचल सम्पत्ति, बैंक लॉकर आदि का विवरण, नेशनल आरटीआई फोरम, पीपुल्स फोरम, पीके ओएमजी ट्रस्ट आदि से जुड़े अभिलेख की सूचना मांगी गई थी. सारी सूचनाएं लेकर विजिलेंस कार्यालय पहुंचे अमिताभ ठाकुर को अनुसंधान अधिकारी नदारद मिले. अमिताभ ठाकुर ने इस तरह बुला कर अनुसंधान अधिकारी के गायब होने पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है. सतर्कता जांच के दावपेंच के बीच ही अमिताभ ठाकुर ने राज्य के सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस अफसरों समेत अन्य संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सम्पत्ति का विवरण लेकर सरकार को उसकी समीक्षा करने को कहा है. ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह आग्रह किया है कि इस बारे में अदालत सरकार को जरूरी निर्देश दे. अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में अखिल भारतीय सेवा तथा राज्य कर्मियों की आचरण नियमावली के सम्पत्ति विवरण देने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने लगातार अपना सम्पत्ति विवरण दिया फिर भी अकेले उन्हें चुन कर उनकी सम्पत्ति विवरण का विश्लेषण किया गया और सतर्कता जांच बिठा दी गई. अन्य अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता. सतर्कता अधिष्ठान ने अकेले उनसे उनके विदेश भ्रमण, हवाई यात्रा, कुत्तों, घरेलू नौकर, मोबाइल नंबर आदि का विवरण मांगा. जबकि राज्य सरकार को सभी राज्य कर्मियों के सम्बन्ध में ऐसा करना चाहिए. इसके लिए अदालत के निर्देश की आवश्यकता है.

इसके पहले अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र लिख कर उनसे उत्तर प्रदेश के सभी लोक सेवकों से उनके द्वारा पाले गए कुत्तों और पशुओं की नस्ल, उनके और परिवार द्वारा की गई विदेश यात्राएं और अन्य हवाई यात्राओं के विवरण और उस पर हुए व्यय और उनके और उनके परिवार द्वारा विभिन्न आलीशान क्लबों की सदस्यता लिए जाने का विवरण मांगने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग ने उनसे उनके 1992 में सेवा में आने से लेकर 13 जुलाई 2015 तक की अवधि में इन सूचनाओं के अलावा उनके तथा उनके परिवार द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा, प्रयोग में लाए गए वाहन के रखरखाव और मोबाइल नंबर और घरेलू नौकर तक के विवरण मांगे हैं. अमिताभ ने कहा कि उनके परिवार ने कभी कुत्ता नहीं पाला और न ही वे किसी क्लब के सदस्य हैं. उनके एक बार इंग्लैंड ट्रेनिंग और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के यूएस एम्बेसी से अमेरिका टूर पर जाने के अलावा वे लोग कभी विदेश नहीं गए और उन्होंने हवाई यात्रा भी यदा-कदा ही की है. लेकिन वे तमाम अफसरों को जानते हैं, जिनके इन मामलों में अच्छे-खासे खर्चे हैं. ■

## कई बड़े दल अमिताभ के सम्पर्क में

आईपीएस अफसर रहते हुए जन-सरोकारों से सीधे जुड़े रहने और समाजवादी सरकार के खिलाफ खुली बगावत करने के कारण सुर्खियों में आए अमिताभ ठाकुर को राजनीति के मैदान में उतरने के प्रस्ताव और सुझाव आ रहे हैं. हालांकि इस बारे में पूछने पर अमिताभ ठाकुर कुछ स्पष्ट नहीं कहते. कई पार्टियां अमिताभ के सम्पर्क में हैं, लेकिन अमिताभ इसका खुलासा करने के बजाय इतना ही कहते हैं कि समाज के लिए लड़ना उनकी फितरत में है और वे इसे जारी रखेंगे. नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश (वीआरएस) लेने की बात पर अमिताभ ने कहा कि वे नौकरी से मुक्त होकर सामाजिक सेवा करने के बारे में अर्से से सोच रहे थे, लेकिन अब चूंकि सरकार ने जांच शुरू कर दी है, तो इसे वे निपटा कर ही छोड़ेंगे. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की फोन पर मिली धमकी को कानून के दायरे में लाने के कारण उनके खिलाफ सरकार द्वारा मोर्चा खोलने और एकतरफा कार्रवाई करने के कारण अमिताभ खिन्न हैं और नौकरी छोड़ कर सामाजिक स्तर पर पूर्णकालिक रूप से सक्रिय होने की प्रतिबद्धता जताते हैं. अमिताभ कहते हैं, मेरा वोट की राजनीति का मन तो कतई नहीं करता, क्योंकि वोट मांगने और उसके लिए सब्जबाग दिखाने, लोगों को ठगने और तमाम चोंचले अपनाने में मेरी रुचि नहीं है, पर जल्द ही सरकारी सेवा से मुक्ति पाकर राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर कुछ करूंगा. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनका पहला मुद्दा है शासन (गवर्नेंस) में पारदर्शिता और जवाबदेही. बिना इसके जनता का भला होने वाला नहीं है. ■

## बाग़ी आईएएस भी उतर रहे सियासत के मैदान में

सपा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी राजनीति के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है. सूर्य प्रताप सिंह ने पिछले दिनों राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन 28 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित युवा संकल्प सभा में सिंह ने घोषणा की कि वे अभी 'उत्तर प्रदेश बचाओ-उत्तर प्रदेश बनाओ' अभियान को गति देने का काम करेंगे, सक्रिय राजनीति के मैदान में उतरने के बारे में वे बाद में निर्णय लेंगे. पिछले कई महीनों से तैनाती के लिए प्रतीक्षा कर रहे 1982 बैच के आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने पिछले कुछ अर्से से नेताओं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वे सार्वजनिक स्थलों और रेस्टोरेंट में युवकों से मिल रहे हैं. नकल विरोधी अभियान चला कर चर्चा में आने वाले सिंह ने जन-अभियान चला रखा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने के कारण सिंह राज्य सरकार के निशाने पर आ गए. उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख सचिव बनने के बाद शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया. इसके बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल रोको अभियान चलाया. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के खिलाफ अभियान चला कर हाईकोर्ट के जरिए उन्हें बर्खास्त कराने का श्रेय भी सिंह को ही जाता है. उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि वे इलाहाबाद के कमिश्नर होते, तो अनिल यादव जेल में होते. राज्य सरकार के खिलाफ अध्यापकों के धरना-प्रदर्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और किसानों की बदहाली के प्रति लापरवाही पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार को खुलेआम लताड़ा था. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

## एक दिन में 35 लाख रुपये की 'सफाई' करता लखनऊ नगर निगम

# कूड़े के ढेर में सफाई का दावा

गणेशजी वर्मा

एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ के अस्पताल संक्रामक रोगों के मरीज से भरे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ नगर निगम सफाई के नाम पर प्रतिदिन 35 से 40 लाख रुपये खर्च कर रहा है. यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन नगर निगम का बजट यह हकीकत खुद ही बयां कर रहा है. यदि कहा जाए कि लखनऊ नगर निगम गंदगी की नहीं रुपये की सफाई कर रहा है, तो गलत नहीं होगा. हैरत तो इस बात पर है कि नगर निगम के मेयर भाजपा के हैं, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री सफाई अभियान को लेकर लगातार अभियान चलाने की बात करते हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सफाई अभियान को लेकर सजग दिखने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सफाई के दावे आपको कूड़े के अम्बार में दिखाई दे जाएंगे.

नवाबों का शहर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन वर्तमान समय का सच कुछ और है. लखनऊ का हृदय कहा जाने वाला हजरतगंज और पॉश इलाकों में गिना जाने वाला गोमतीनगर, महानगर, अलीगंज, इंदिरानगर समेत कई क्षेत्रों में गंदगी की भरमार है. पॉश कालोनियों में सफाई का आलम यह है, तो उन क्षेत्रों का क्या हाल होगा जहां आम और गरीब लोग रहते होंगे. आम आदमी से लेकर समृद्ध वर्ग सभी नगर निगम को टैक्स देते हैं, फिर भी गंदगी की भरमार है. नगर निगम इस गंदगी को साफ करने के लिए प्रतिदिन लगभग 35 लाख रुपये खर्च करता है. इस खर्च में गाड़ी का ईंधन, पानी का छिड़काव, नालों की सफाई, कर्मचारियों का वेतन वगैरह शामिल है. सफाई के लिए एक अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक 9500.08 लाख रुपये खर्च कर दिये गए.



नगर निगम विभाग कथित तौर पर प्रतिदिन सुबह नौ बजे से लेकर छह बजे तक सफाई अभियान में लगा रहता है. हर पड़ाव पर नगर निगम की गाड़ियों की समय-सीमा भी निर्धारित होती है. लेकिन बिना समय के पहुंचने वाली इन गाड़ियों में सवार कर्मचारी जैसे-तैसे पड़ाव घर से कूड़ा उठाकर चले जाते हैं. कई जगहों की हालत यह है कि कई दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे बदबू की वजह से राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता है. जब स्थानीय लोग लगातार शिकायत करते हैं, तभी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंचती है.

ऐसी हालत में नगर निगम के खर्च पर हैरान होना स्वाभाविक है. सफाई के काम में लगी गाड़ियों के पेट्रोल व डीजल पर विभाग करीब 6 लाख रुपये रोज खर्च करता है. हालांकि वर्ष 2013-14 में इसका लक्ष्य लगभग प्रतिदिन सात लाख रुपये था, लेकिन वर्ष 2014-15 में इसे घटाकर लगभग छह लाख रुपये कर दिया गया. इतने पैसे खर्च करने के बावजूद शहर में जगह-जगह पर गंदगी क्यों दिखती है, इस सवाल का जवाब निगम के पास नहीं है. जबकि नगर निगम का दावा यह भी है कि सुबह छह बजे से लेकर शाम पांच बजे तक नगर निगम सफाई अभियान में लगा रहता है. डोर टू डोर सफाई के तहत विभाग पूरे दिन सफाई अभियान में जुटा रहता है. पूरे दिन की मेहनत के बाद भी राजधानी में गंदगी का अम्बार क्यों है, इसका जवाब निगम के अधिकारी नहीं दे पाते. लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा कहते हैं कि नगर निगम अपने क्षेत्र में सफाई करता है. कूड़े हर जगह से उठाएं जाते हैं. शिकायत मिलने पर कर्मचारियों को डांट-फटकार भी लगाई जाती है, तो इसी अंदाज में नगर आयुक्त उदयराज सिंह कहते हैं कि सफाई को लेकर नगर निगम चौकन्ना है. कर्मचारी और अधिकारी भी सफाई अभियान पर गंभीर रहते हैं. शहर में सफाई रहती है और सफाई पर ही बजट खर्च किया जाता है. ■

### क्यों संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाता है लखनऊ?

लखनऊ की सफाई के लिए नगर निगम ने 43 लाख रुपये प्रतिदिन के खर्च का प्रावधान रखा है. निगम सफाई का दावा भी करता रहता है. लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि जब राजधानी की सफाई यथोचित रहती है, तो फिर शहर हर बार संक्रामक रोगों की चपेट में क्यों आ जाता है? स्मार्ट सिटी हो जाने पर सफाई का प्रतिदिन का बजट 60 लाख रुपये हो जाएगा. फिर कितनी तेजी से रुपये की सफाई होगी.

feedback@chauthiduniya.com

## गिरफ्तार आतंकी का खुलासा: नेपाल के रास्ते आतंक फैलाने में आईएसआई फिर सक्रिय

# भारत में स्लीपर सेल को जगा रहे आतंकी



शत्रुंजय सिंह रैकवार

भारत-नेपाल के सोनौली सीमा पर गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक डॉ. जावेद कमाल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. जावेद ने कई बार सुरक्षा एजेंसियों को भ्रमित करने का प्रयास किया. अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वह आईएसआई का एजेंट है. कई बार नाम बदल कर वह पहले भी नेपाल की यात्रा कर चुका है. खुद को डॉ. जावेद कमाल बताने वाले आतंकी ने सुरक्षा एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं. इस आधार पर बैंकॉक, थाइलैंड और काठमांडू के आतंकी लिंक तलाशने में जांच एजेंसियां लग गई हैं. उसके पास मिले भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेज की भी जांच की जा रही है. एसटीएफ के अधिकारियों को पूछताछ में उसने अपना नाम डॉ. जावेद कमाल निवासी, पीएलओ चक्र नंबर 76 फैसलाबाद, पाकिस्तान बताया. उसने बताया कि पाक में पीएचडी करने के बाद वह बैंकॉक चला गया था. वहां से भारत की नागरिकता बनवाई और काठमांडू पहुंचकर सीधे सोनौली पहुंच गया. यहां से उसे वाराणसी जाना था. पाकिस्तानी नागरिक जावेद कमाल वाराणसी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिसे सरहद पर एसएसबी के जवानों ने दबोच लिया.

23 अक्टूबर को गिरफ्तार जावेद ने बताया कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी यहां पहले से मौजूद स्लीपर सेल को सक्रिय करने का काम कर रही है. जावेद को काशी और अन्य जिलों में मौजूद स्लीपर सेल को सक्रिय करने का काम सौंपा गया था. इस काम में जावेद के कुछ साथी यूपी के अन्य जिलों में भी पहुंच चुके हैं. गोरखपुर रेंज के डीआईजी आरके चतुर्वेदी ने बताया कि जावेद के संबंध आईएसआई से हैं या नहीं, इस बात के संकेत जरूर मिले हैं. जावेद की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) के बड़े अधिकारी सीमा क्षेत्र में उसका संपर्क सूत्र तलाशने में जुट गए. दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की टीम भी महराजगंज पहुंच गई. नेपाल के उन होटलों को भी खंगाला जाने लगा, जहां वह ठहरा था. जांच के बाद पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि जावेद अपनी पहचान और भारत आने का उद्देश्य छिपा रहा है. खुद को एग्रीकल्चर से पीएचडी बताने वाला पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला डॉ. जावेद कमाल बैंकॉक सहित 20 देशों की यात्रा कर चुका है. उसे बखूबी पता है कि बिना वीजा देश में प्रवेश करने पर हिरासत में ले लिया जाएगा. फिर भी वह गोपनीय ढंग से प्रवेश क्यों कर रहा था, यह सवाल सामने है. आमतौर पर सोनौली से भारत में प्रवेश करने वालों की कोई जांच भी नहीं होती है, लेकिन जावेद के हुलिये और कदकाठी को देखकर जब एसएसबी ने उससे पूछताछ की, तो उसने पहले खुद को नेपाल का निवासी बताकर मामले को टरकाने की कोशिश की. वहीं, जब उसकी घबराहट को देखकर उसे एसएसबी चौकी पर लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपने पिता का नाम नवाब कमाल और खुद को पीएलओ 76, फैसलाबाद, पाकिस्तान का रहने वाला बताया. जावेद कमाल के खतरनाक मंसूबे परत-दर-परत खुलते चले गए. वह 1996 से ही आईएसआई से जुड़कर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है. जावेद के साथ पांच लोग भी थे. संभावना जताई जा रही है कि इसमें से कुछ लोग पहले ही दशहरा और मोहर्रम का लाभ उठाकर भारत में प्रवेश कर चुके हैं. नेपाल के तराई इलाके में सिमी, आईएम, हूजी और आईएसआई ने लंबे अर्से से ट्रांजिट प्वाइंट बना रखे हैं. इससे पहले भी तमाम आतंकी यहां से घुसपैठ करते रहे हैं. ये इलाका टॉप 20 में शामिल आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आया था. आईएम का सरगना यासीन भटकल भी यहीं से पकड़ा गया था. वहीं, पंजाब का दुर्दांत आतंकी सुखविंदर सिंह भी यहीं से दबोचा जा चुका है.

जावेद कमाल भारत में कुछ दिन टिकने की कोशिश में था. वह फेसबुक पर बड़ी संख्या में भारतीय दोस्त बना रहा था. जावेद ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि उसने सूर्यमुखी पर शोध किया है, लेकिन खुद को एग्रो में पीएचडी बताने वाला जावेद पूछताछ में सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम नहीं बता पाया. साथ ही हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी बात नहीं कर सका. इससे उस पर शक और गहरा गया. नेपाल से भारत में पाकिस्तानी नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, इसके बावजूद बिना वीजा के वह भारत में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था? सवाल यह भी है कि बिना डेबिट कार्ड और मोबाइल के वह कैसे सफर तय करता रहा, जबकि बैंकॉक में ही वह 35 दिन फाइव स्टार और थ्री स्टार होटलों में रुका और इस दौरान लाखों रुपये खर्च हुए? बेरोजगार होने के बाद भी उसे कहां से और कौन रुपये देता रहा? उसके पास से बरामद हुई 40 हजार थाई मुद्रा के बारे में वह जवाब क्यों नहीं दे सका? ■

### कमज़ोर नेपाल आईएसआई का मज़बूत ठिकाना

सिद्धार्थनगर जिले की बढ़नी सीमा पर भाग सिंह और अजमेर सिंह नाम के आतंकी पकड़े गए थे. वर्ष 1993 में सोनौली सीमा पर मुंबई बम कांड का दोषी याकूब मेमन भी धरा गया था. आतंकी जब्बार भी इसी रास्ते से होकर लखनऊ पहुंचा था. गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद की कचहरियों में विस्फोट करने वाला संजरपुर निवासी सलमान उर्फ छोटू भी यहीं से गिरफ्तार हुआ था. बहरहाल, नेपाल में बदले राजनीतिक समीकरण का लाभ उठा कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर भारत में आतंक फैलाने की साजिशें शुरू कर दी हैं. नेपाल को इसका जरिया बनाने की कोशिशें चल रही हैं. काठमांडू में बैठे पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी आईएसआई की भरपूर मदद कर रहे हैं. पहले भी काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के राजनीतिक सचिव रहे हामिद गुल व तृतीय सचिव इम्तियाज खां के ऊपर आईएसआई का सहयोग करने के आरोप लग चुके हैं. बीते 23 अक्टूबर को जनपद महराजगंज सोनौली सीमा से गिरफ्तार जावेद कमाल के मिशन-नेपाल की कड़ियां खुलने लगी हैं. उसका इरादा सोनौली बॉर्डर से गोरखपुर पहुंच कर वाराणसी में धमाके को अंजाम देने का था. इस खुलासे के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ आतंकवादियों की हिट-लिस्ट में हैं. सोनौली से भारत के शहरों में जाने के लिए गोरखपुर रेल मार्ग व सड़क मार्ग को ही चुना जाता है. गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने कहा कि जिले में पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व संदिग्ध मार्गों पर गहन चेकिंग शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आतंकवादियों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

उलेखनीय है कि वर्ष 2005 में सऊदी अरब और 2013 में तुर्की की यात्रा कर चुके जावेद की योजना थाईलैंड से काठमांडू पहुंच कर वाराणसी जाने की थी. उसने वाराणसी के चप्पे-चप्पे की स्टडी की थी और काशी विश्वनाथ मंदिर व संकटमोचन के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में भी सारे मालुमात हासिल कर लिए थे. बीएचयू से कौन प्रोफेसर कब विदेश गया और उसने किस विषय के कांफ्रेंस में हिस्सा लिया, यह सब जानकारी जावेद के पास थी. पूछताछ में जावेद ने पैसे की तंगी के कारण थाईलैंड में मोबाइल फोन बेचने की बात कही. लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे उसके मोबाइल और लैपटॉप कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. उसने मोबाइल बेचा नहीं था, बल्कि उसने अपना मोबाइल और लैपटॉप सीमा पार करते समय अपने सहयोगियों के पास छोड़ दिया था. जावेद के सहयोगियों के तार सीधे आजमगढ़ से जुड़े बताए जा रहे हैं. वह वाराणसी जाते वक्त आजमगढ़ में ही रुकने वाला था.

अब तक की जांच में उसके स्थानीय मददगार भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं. इनमें एक सोनौली कस्बे और दो नेपाल के बेलहिया के रहने वाले हैं. इसके पूर्व बीते साल नेपाल के एक लाख का ईनामी आतंकी रियाज फकीर के नौतनवां में ही शरण लेने की बात खुली है. सोनौली में पकड़े गए आतंकी जावेद का मोबाइल और लैपटॉप स्थानीय लोगों के पास है. जांच एजेंसियां इन तीनों की तालाश में जुटी हैं. सोनौली बॉर्डर व महराजगंज और गोरखपुर में मात्र दस साल में कई ऐसे नवधनाढ्य पनपे हैं, जो अरबपति हैं. इनके पास अकूत धन कहां से आया, यह गंभीर जांच का विषय है.

आतंकियों की हिट लिस्ट में शुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मामला जुड़ने के कारण दिल्ली से वाराणसी तक की सुरक्षा एजेंसियां सोनौली पहुंच गईं. पहले तो पाकिस्तान के फैसलाबाद युनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने का दावा करने वाला जावेद हर कीमत पर वाराणसी पहुंचना चाहता था, पर सुरक्षा के लिहाज से उसने जिस रास्ते से भारत में प्रवेश को महफूज माना वहीं गिरफ्तार हो गया. प्रदेश में पिछले दिनों हुए बम धमाकों से जुड़े आतंकियो के बारे में भी उसने कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं. भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ अर्से में हुई कुछ खूंखार आतंकियों की गिरफ्तारी और खुफिया एंजेसियों की रिपोर्टों से यह साबित हुआ है कि भारत में आतंकवाद का कहर बरपाने वाले आतंकियों की बड़ी जमात नेपाल से भारत में प्रवेश कर रही है. स्थानीय और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत-नेपाल की 17 सौ किलोमीटर लंबी खुली सीमा का लाभ उठाकर अपराधी-आतंकवादी तत्व भारत में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले एक दशक में केवल महराजगंज व सिद्धार्थनगर सीमा पर हुई कई आतंकियों की गिरफ्तारी से इसकी पुष्टि भी होती है. आतंकवाद के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पहली बार तब सुर्खियों में आया था, जब वर्ष 1991 में महराजगंज के सोनौली चेक पोस्ट पर पंजाब का दुर्दांत आतंकी सुखविंदर सिंह दबोचा गया था. इसके बाद वर्ष 1993 में सोनौली बार्डर से ही मुम्बई बम कांड का खलनायक याकूब मेनन भी पकड़ा गया था. 2002 में पाकिस्तान निवासी साजिया बेगम मलिक को एक लाख डॉलर के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को पुछताछ के दौरान उसने बताया था कि यह पैसा हमें काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास से मिला था. यह पैसा हमें हुरियत कांफ्रेंस के एक नेता के द्वारा जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष यासीन मलिक को देने के लिए दिया गया था. उसने बताया था कि भविष्य में आईएसआई द्वारा भारतीय सीमा को टारगेट बनाकर तबाही फैलाने की योजना है. पिछले साल महराजगंज के ठूठीबारी थाना इलाके में नौ माओवादी एक कार्बाइन, हैंड ग्रेनेड व पिस्टल के साथ घुस आए थे, पर ऐन मौके पर पकड़े गए थे. वर्ष 1994 में ही काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के राजनीतिक सचिव हामिद गुल व तृतीय सचिव इम्तियाज खान पर आईएसआई की सरपरस्ती में भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के कारण उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था.



## उत्तर प्रदेश बचाओ-उत्तर प्रदेश बनाओ अभियान के जरिए एकजुट हो रहे छोटे दल

# राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की जद्दोजहद

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन दो साल और है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक सक्रियता सतह पर दिखने लगी है. बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करने के इरादे से तमाम छोटे-छोटे दल एक साथ आने और अपनी ताकत बटोरने के अभियान में जुट गए हैं. छोटे-छोटे राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने की पहल करते हुए ही यूपी में उत्तर प्रदेश बचाओ-उत्तर प्रदेश बनाओ अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान के जरिए तमाम छोटे दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास हो रहा है. इसी अभियान के तहत पिछले 28 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में युवा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई छोटे दलों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शरीक हुए. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के नेता दिनकर कपूर आयोजन की कामयाबी को नए विकल्प के लिए इकट्ठा हो रही जन-शक्ति का ठोस संकेत मानते हैं.

युवा संकल्प सभा में मौजूद लोगों ने सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने, प्रदेश में परिवारवाद-वंशवाद समाप्त करने और साम्प्रदायिक विद्वेष की राजनीति के विरोध में खड़े होने का संकल्प लिया. सभा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दों पर प्रदेशव्यापी अभियान तेज करने का फैसला लिया गया. सभा में शरीक राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार, महिला विरोधी हिंसा और जातीय भेदभाव के विरोध में प्रस्ताव ग्रहण करते हुए उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सीबीआई के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना की और भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने के लिए जुझारू आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया.

सभा में सरकारी नौकरियों में खाली लाखों पदों को बिना किसी देरी के भरे जाने और चयनप्रक्रिया को शुल्क-मुक्त, पारदर्शी व विधि सम्मत बनाने की मांग करते हुए नियुक्ति आयोग-समितियों में अयोग्य, आपराधिक कृत्य में लिप्त लोगों को नियुक्त करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने वाली समाजवादी सरकार की कड़ी निंदा की गई. सभा ने वित्तीय अनुशासन के नाम पर शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, अप्रेंटिस आदि मदों में हो रही भारी कटौती पर अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और उच्चतर प्रौद्योगिकी तथा शोध संस्थानों को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की तर्ज पर ढालने की नीति को नामंजूर करते हुए शिक्षा को सबको समान रुप से देने, सार्थक ज्ञान और चेतना विकसित करने के साधन के रूप में अपनाने की मांग की. तेजी से बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और वायदा कारोबार और जमाखोरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई. प्रदेश में चौपट हो रही खेती-किसानी पर चिंता व्यक्त करते हुए नोट किया गया कि खेती ही अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा है और खेती-किसानी, कृषि आधारित उद्योग, छोटे-मझोले उद्योग तथा दस्तकारी क्षेत्र के विकास से ही रोजगार सृजन और देश का वास्तविक विकास हो सकता है. संकल्प सभा में किसानों और आम नागरिकों की कीमत पर कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही छूट को समाप्त करने और कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जनहित के मदों पर बजट में पर्याप्त धन आवंटित करने की मांग की गई.




संकल्प सभा में वरिष्ठ आईएएस डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. चारों तरफ आशंका, भय, जुल्म और अराजकता का माहौल व्याप्त है. महिलाओं के साथ गैंगरेप और उनकी हत्या, बेकारी की आग में झुलस रहे नौजवानों की आत्महत्या, किसानों व गरीबों की मौत तथा पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या आम बात हो गई है. प्रदेश में दंगा-फसाद की घटनाओं का चेहरा बेहद डरावना होता जा रहा है. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है, विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी सरकार को कतई पसंद नहीं है. उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में गजब हालत है, यहां शिक्षक प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक विवादित लोग बनाए गए, जिन्हें उच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया. यहां सर्वोच्च न्यायालय तक को यह कहना पड़ता है कि अगर किसी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीबीआई जांच चल रही है, तो सरकार इतनी परेशान क्यों है? बाद में पता चलता है कि एक परिवार, जिसने पूरे प्रदेश पर कब्जा कर रखा है, भ्रष्टाचारी की कम्पनी में शेयर होल्डर है.

किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश सूखे से सबसे अधिक प्रभावित है. अभी भी उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करके राहत कार्य शुरू करने की कौन कहे, सरकार ने एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने की अपनी घोषणा पर भी अमल नहीं किया. किसान जो पैदा कर रहा है, उसे खरीदने और यदि खरीद भी ले तो कोई पैसा भुगतान करने वाला नहीं है.

बुलेट राजा' फिल्म के पटकथा लेखक और प्रगतिशील बुद्धिजीवी अमरेश मिश्रा ने आजादी की पहली लड़ाई 1857 का जिक्र करते हुए कहा कि आज फिर अवध से लेकर पूरे प्रदेश में जनता के हक में आंदोलन की जरूरत है. पूर्व सांसद व वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि प्रदेश में न तो पूंजी बन रही है, न बाहर से आ रही है. हां, विज्ञापन पर खूब पैसा खर्च हो रहा है. लखनऊ से लेकर मुंबई तक बड़े-बड़े होटलों में इन्वेस्टर कनक्लेव बुलाए जा रहे हैं. अलीगढ़ का ताला, मेरठ की कैंची, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ी, बनारस की साड़ी, भदोही का कालीन, मिर्जापुर का खिलौना जैसे उद्योग बर्बाद हो गए हैं.

आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी ने कहा कि बेकारी का आलम यह है कि सचिवालय में निकली चपरासी की 368 नियुक्तियों के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए, जिसमें पीएचडी, बीटेक, एमटेक से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों लोग हैं. मानकों के अनुसार नियुक्ति न होने की वजह से उच्च न्यायालय ने एक ही झटके में एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी अवैध घोषित कर दी. सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील ने इस बात पर गहरा क्षोभ जताया कि पिछले बीस साल में प्रदेश में जो भी पब्लिक सम्पत्ति, सीमेन्ट, कताई, चीनी जैसी मिलें थी, उन्हें कमीशनखोरी में निजी लोगों के हवाले कर दिया गया. पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि प्रदेश को एक नए विकल्प और बदलाव की जरूरत है, जिसे नौजवानों को पूरा करना होगा. पूर्व डीआरएम रेलवे आसमा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए किसानी के विकास की जरूरत है. सभा में प्रदेशभर से आए नौजवानों का स्वागत तारिक सिद्दीकी ने किया. सभा की अध्यक्षता पूर्व सांसद इलियास आजमी ने की और संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

# वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तिवारी का अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ धरना

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में कुमाऊ मंडल के सबसे बड़े सुशाली तिवारी अस्पताल की बदहाली से नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी पुत्र रोहित शेखर सहित धरने पर बैठे थे. इससे पहले उन्होंने अस्पताल पहुंचकर अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरने की चेतावनी थी. एनडी तिवारी के धरने को लेकर राजनीति के जानकारों का मानना है कि तिवारी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पुत्र मोह में अपनी पार्टी की सरकार पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं. सपा एनडी तिवारी के जैविक पुत्र रोहित शेखर तिवारी के कंधे पर चढ़कर उत्तराखंड में अपना पांव पसारना चाहती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने खिलाफ कांग्रिसयों के धरना प्रदर्शन का जवाब उन्हीं के दिग्गज के माध्यम से दिला कर राहुल-सोनिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया. जब प्रदेश की रावत सरकार अच्छे कामों का ढिंढोरा पीट रही थी, उसी समय तिवारी अपने मुंह पर काली पट्टी बांध कर धरने पर बैठे थे. हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर पूर्व सीएम एनडी तिवारी मुंह पर पट्टी बांध मौन व्रत पर बैठ गए. अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं से नाराज होकर उनकी पत्नी उज्जवला और पुत्र रोहित शेखर भी उनके साथ धरने पर बैठे थे. उल्लेखनीय है कि उक्त अस्पताल उनकी पहली पत्नी डॉ. सुशीला तिवारी के नाम से खोला गया है, वित्तमंत्री डॉ. इंद्रा हृदयेश और श्रम मंत्री दुर्गापाल पूर्व मुख्यमंत्री को मनाने पहुंचे, उनकी सारी कोशिश नाकाम रही वह नहीं माने. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी मंगलवार की शाम पांच बजे सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे थे. उनके बेटे रोहित ने एसटीएच के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत और एमएस डॉ. एके पांडेय से स्टाफ की जानकारी ली थी.

अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की कमी पर पूर्व सीएम ने नाराजगी जताई थी. अस्पताल में डॉक्टरों के साथ लगभग दो सौ नर्सें भी कम हैं. डॉक्टरों की कमी के कारण एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई में भी व्यवधान हो रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्डिक फिजीशियन, कार्डिक सर्जन, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जैसी सुविधाएं न होने पर आश्चर्य जताया था. तिवारी जी ने जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर जिस तरह हरीश-सरकार को आइना दिखाया उससे पूरी सरकार सकते में है. राजनीति में हरीश रावत के धुर विरोधी रहे तिवारी दस जनपथ से गहरे रिस्ते के कारण सदैव हरीश पर भारी पड़ते रहे हैं. तिवारी के इस मौन व्रत ने एक बार फिर से इतिहास को दोहराया है. 2003 में तिवारी सरकार के खिलाफ खुद पीसीसी प्रमुख के नाते हरीश रावत ने विस के बाहर धरना दिया था. अब तिवारी हरीश सरकार के खिलाफ मौन व्रत पर रहे. एनडी तिवारी का यह मौन कई संदर्भ में देखा जाने लगा है. तिवारी अपनी पत्नी उज्जवला, पुत्र रोहित शेखर तथा कुछ खास लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज के ठीक गेट के बाहर मौन व्रत पर बैठ गए. जानकार मान रहे हैं कि बुजुर्ग एनडी की सरकार नहीं सुन रही है. इससे आहत एनडी तिवारी ने एक बार फिर से अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है. इसका असर हल्द्वानी से लेकर दून तथा दिल्ली तक होना तय है. बताया जा रहा है कि तिवारी अपने कार्यकाल की कुछ योजनाओं की स्थिति को लेकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही आहत हैं. इसमें एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी शामिल है. उनके परिवार द्वारा हरीश सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाता रहा है, तिवारी जी का मन अब कांग्रेस से खिन्न हो कर डोल रहा है, जिसे हवा देने में सपा सुप्रिमों की भूमिका चिन्हित की जा रही है. कांग्रेस ने इस घटना से सबक लेकर समय रहते चेता नहीं, तो तिवारी कांग्रेस के मिशन 2017 में कांग्रेस के गले की फांस बन सकते हैं.

विकास पुरुष कह जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के मौन व्रत को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंभीरता से लिया है. तिवारी ने जो चिंता व्यक्त की है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है. इस मामले में हरीश रावत ने कहा है कि जो मुद्दे एनडी तिवारी ने उठाए हैं, उन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षामंत्री की संयुक्त प्रेस वार्ता की जानी थी, मगर थत्यूड़, टिहरी में देर शाम तक सीएम के कार्यक्रम होने के कारण प्रेस वार्ता चिकित्सा शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा की गई. कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी द्वारा दस साल पुरानी एमआरआई व सीटीस्कैन मशीनों को बदलने की बात की गई है. इस पर सीएम, कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश व उनके द्वारा विचार विमर्श के बाद उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में बदलने की सहमति व्यक्त की गई. उसके साथ



अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की कमी पर पूर्व सीएम ने नाराजगी जताई थी. अस्पताल में डॉक्टरों के साथ लगभग दो सौ नर्सें भी कम हैं. डॉक्टरों की कमी के कारण एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई में भी व्यवधान हो रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्डिक फिजीशियन, कार्डिक सर्जन, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जैसी सुविधाएं न होने पर आश्चर्य जताया था. तिवारी ने जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर जिस तरह हरीश सरकार को आइना दिखाया उससे पूरी सरकार सकते में है.

ही हृदय रोग विभाग के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आया है, जिस पर कार्य शुरू कर दिया गया है. ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से 125 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, किन्तु ट्रॉमा सेंटर की स्थापना जहां होनी है वह वन भूमि के अंतर्गत है. वन भूमि संबंधी मामले के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. वन भूमि संबंधी मामले के निस्तारण के बाद इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही डॉक्टरों की कमी की समस्याओं के बारे में बताया कि वर्तमान में 275 डॉक्टरों के पद सृजित हैं, जिनमें से 240 डॉक्टर कार्य कर रहे हैं. शेष 35 डॉक्टरों के पदों को दो-तीन माह में वॉक इन-इंटरव्यू के माध्यम से भर दिया जाएगा. टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि एमसीआई के मानक के हिसाब से टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ के 1,005 पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में 1400 टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि शेष टीचिंग व नान टीचिंग स्टाफ को हटाया नहीं जाएगा. इसके लिए संशोधन ढांचे के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेज दी गई है. स्टाफ नर्स की कमी के बारे में हरक सिंह ने कहा कि वहां पर 250 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं, मगर 75 स्टाफ नर्सों की अतिरिक्त आवश्यकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# योग संस्कृति में विश्व मानवता को पोषित करने की पूरी ताक़त : क़ादर ख़ान

चौथी दुनिया ब्यूरो

पतंजलि योगपीठ में योगासनों का स्वास्थ्य हेतु ज्ञान लेकर सिनेमा जगत के जाने-माने कलाकार कादर खान 27 अक्टूबर को मुंबई रवाना हो गए. योगपीठ से जाते समय कादर खान भावुक थे. उन्होंने कहा कि योगपीठ परिवार ने जिस तरह का आदर सम्मान दिया, उससे हम बहुत खुश हैं और पूरी दुनिया के लिए मेरा संदेश यह है कि हमारे योग संस्कृति में विश्व मानवता को पोषित करने की पूरी ताकत है, जिसकी दिव्यता से ही मानव अपने को स्वस्थ महसूस करने लगता है. उन्होंने आचार्य बालकृष्ण एवं योगगुरु बाबा रामदेव को मानवतावादी महान व्यक्ति बताया. कादर खान ने योगपीठ के सभी विद्यार्थियों और सेवियों को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यहां मानवतावादी लोग हैं, जो हमें इतने कम समय में ही इस पीठ से पूरी तरह जोड़ दिया है, जिसका फल है कि हमारा मन इस पीठ से पूरी तरह जुड़ा रहेगा. हम आगे भी इस पवित्र पीठ में आते रहेंगे. खान को जब योगपीठ लाया गया था, तो पूरी गर्मजोशी से पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने उनका स्वागत किया था. उनकी वापसी पर आचार्य जी भावुक एवं प्रसन्न थे, आचार्य जी ने खान साहब के सहजता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जिन्दादिली सराहनीय है. खान की सेवा में लगे योग आचार्य भी उनसे काफी प्रभावित रहे. ■



योगपीठ से जाते समय कादर खान भावुर थे. उन्होंने कहा कि योगपीठ परिवार ने जिस तरह का आदर सम्मान किया, उससे हम बहुत खुश हैं और पूरी दुनिया के लिए मेरा संदेश यह है कि हमारे योग संस्कृति में विश्व मानवता को पोषित करने की पूरी ताकत है, जिसकी दिव्यता से ही मानव अपने को स्वस्थ महसूस करने लगता है. उन्होंने आचार्य बालकृष्ण एवं योगगुरु बाबा रामदेव को मानवतावादी महान व्यक्ति बताया. कादर खान ने योगपीठ के सभी विद्यार्थियों और सेवियों को अपनी शुभकामनाएं दीं.

feedback@chauthiduniya.com